

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



जनवरी 2020

खंड 74 अंक 1

संपादन समिति
राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवडकर

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

\$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था: आकांक्षा से कार्रवाई तक शक्तिकांत दास	1
भारत में समावेशी विकास की ओर यात्रा शक्तिकांत दास	9

लेख

भारत की बाह्य कर्ज वहनीयता और संवेदनशीलता का अध्ययन	13
आस्ति गुणवत्ता मूल्यांकन में क्रेडिट रेटिंग्स की प्रभावकारीता	35

वर्किंग पेपर की प्रेस प्रकाशनियां

अमेरिका से भारतीय बाजारों में टर्म प्रीमियम स्पिलओवर	45
सी-डाइवर्जेंस पर आधारित रोबस्ट वाल्ड-टाइप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स	47

वर्तमान सांख्यिकी

49

हाल के प्रकाशन

94

अनुपूरक

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2018-19	
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: दिसंबर 2019	

भाषण

\$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था: आकांक्षा से कार्रवाई तक
शक्तिकांत दास

भारत में समावेशी विकास की ओर यात्रा
शक्तिकांत दास

\$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था: आकांक्षा से कार्रवाई तक*

शक्तिकांत दास

द टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित इस सुप्रतिष्ठित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में आज सुबह यहाँ होना एक विशेष अवसर है। मैंने पिछले साल 12 दिसंबर को रिजर्व बैंक का प्रभार संभाला था, और यह कार्यक्रम लगभग उसी समय आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की कई कार्यवाहियां पिछले साल टेलीविज़न पर देखने के बाद, मैं इस वर्ष के सम्मेलन में भाग लेने को उत्सुक था। विषय व कार्यक्रम के थीम को इतने सटीक ढंग से रखने के लिए मैं टाइम्स नेटवर्क के श्री आनंद और आईडीएफसी फ़र्स्ट बैंक के श्री वैद्यनाथन की भी प्रशंसा करना चाहूँगा।

आज हम यहाँ या कहीं भी बातचीत के लिए बैठें तो लगभग हर चर्चा घूम-फिरकर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आती है। कई विचार व्यक्त किए जाते हैं, कई विश्लेषण किए जाते हैं, और कई सुझाव दिए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में पूरे देश की रुचि एक बहुत अच्छा संकेत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बड़ी जानकारी भरी और वस्तुनिष्ठ बातचीत की आवश्यकता तो है ही, और इससे भी महत्वपूर्ण हमारी भावी कार्रवाई के बारे में।

इस संदर्भ में, 21वीं शताब्दी के लिए विकास पर जोर देने वाली एक वित्तीय प्रणाली बनाने में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका पर बोलना चाहूँगा। वित्तीय स्थिरता पर भी आऊँगा, जो वृद्धि व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, रिजर्व बैंक भारत की स्वतंत्रता से पहले अस्तित्व में आया। आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में आरबीआई की भूमिका इस प्रकार बताई गई है:

“...बैंक नोटों के निर्गमन को विनियमित करने और भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित राशियों

* श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक -16 दिसंबर को मुंबई में इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में दिया गया भाषण। इस आशु (एक्सटेम्पोर) भाषण को ट्रांसक्रिप्ट और मामूली रूप से संपादित किया गया है।

का रखा जाना तथा करेंसी और प्रत्यय व्यवस्था (क्रेडिट सिस्टम) को देश के लाभार्थ चलाने के लिए....”

समय के साथ, इस अधिदेश (मैंडेट) को कीमतों में स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के रूप में देखा गया है और तात्कालिक समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इनका तुलनात्मक महत्त्व तय किया गया। मई 2016 में आरबीआई ऐक्ट में संशोधन किया गया और मौद्रिक नीति के क्षेत्र में रिजर्व बैंक की भूमिका का इस प्रकार पुनरोल्लेख किया गया:

“मौद्रिक नीति की प्राथमिक भूमिका वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कीमत में स्थिरता बनाए रखना है”।

इस मेंडेट से अधिकृत होकर आरबीआई ने एक लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढाँचा अपनाया जिसके अंतर्गत कीमतों में स्थिरता के उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है जिसे उपभोक्ता हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए, +/- 2 प्रतिशत के सह्य दायरे के साथ 4 प्रतिशत के लक्ष्य द्वारा अंकीय रूप से परिभाषित किया गया है, और साथ ही जिसमें, मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो तो वृद्धि पर ध्यान दिया जाना है। समष्टि-आर्थिक परिदृश्य, मुद्रास्फीति और वृद्धि के परिदृश्य तथा आ रहे आँकड़ों से मिलने वाले संकेतों पर मुद्रास्फीति व वृद्धि का तुलनात्मक महत्त्व निर्भर करता है।

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद, दुनिया भर के बैंकों के लिए वित्तीय स्थिरता एक प्रमुख प्राथमिकता बनकर सामने आई है। वैसे अभी भी इस पर सर्वसम्मति नहीं है कि इसे मौद्रिक नीति के स्पष्ट उद्देश्य में जोड़ा जाए या नहीं, तथ्य यह है कि इस अधिदेश में यह अंतर्निहित है। वस्तुतः इस अधिदेश के आधार पर, घरेलू माँग को पुनर्जीवित करने व आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई मौद्रिक व चलनिधि तथा समष्टि-आर्थिक कदम भी उठाए हैं। साथ ही, बैंकिंग व गैर-बैंकिंग (एनबीएफसी) क्षेत्र की मजबूती के लिए हम कदम उठा रहे हैं। वृद्धि में सुस्ती, मुद्रास्फीतीय दबावों में बढ़ोतरी तथा घरेलू बैंकिंग क्षेत्र व एनबीएफसी की सेहत की बहुविध चुनौतियों से निपटने के लिए जो आवश्यक होगा, रिजर्व बैंक करेगा।

रिजर्व बैंक की भूमिका के बारे में संक्षेप में उल्लेख के बाद अब मैं वृद्धि और उसके बाद वित्तीय स्थिरता की ओर मुड़ता हूँ।

वैश्विक वृद्धि

हाल के वर्षों में हमने देखा कि व्यापारिक तनावों, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों, ब्रेक्जिट पर लंबे समय से बनी हुई अनिश्चितता के कारण वैश्विक वृद्धि धीमी पड़ गई है। अहम यह है कि इन सबका परिदृश्य लगातार बदल रहा है।

जो व्यापारिक तनाव चल रहे हैं, उनके बारे में कहें तो प्रायः सुनने में आता है कि दो प्रमुख देशों के बीच व्यापार युद्ध अब समाप्त होगा और उसके अगले दिन उसके विपरीत समाचार आ जाता है। यह अस्थिरता कुछ समय से जारी है, विशेषतः विगत कुछ महीनों में। अमेरिका व चीन में कुछ सहमति की कल की घोषणा, उम्मीद है कि टिकाऊ हो और आने वाले हफ्तों या महीनों में उलट न जाए। यूएसए से चीन द्वारा अपने कृषि आयातों को बढ़ाने एवं चीनी आयातों पर अमेरिका द्वारा लेवी लगाने में तेजी न दिखाने की मीडिया रिपोर्टों से, मुझे आशा है कि विश्व व्यापार व वृद्धि के क्षेत्र में काफी हद तक निश्चितता आएगी।

इसी प्रकार, ब्रेक्जिट के मामले में एक सकारात्मक बात इस मायने में है कि ब्रेक्जिट के लिए प्रतिबद्ध एक स्थिर सरकार है। इसके पहले, यूनाइटेड किंगडम (यूके) में सावर्जनिक चर्चा ब्रेक्जिट और नो ब्रेक्जिट के बीच झूल रही थी। संयोग से, कुछ निश्चितता वहाँ आती प्रतीत हो रहा है।

अपने दौर की अनिश्चितता पर प्रकाश डालने के लिए, मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगा। जब कुछ महीनों पहले सऊदी तेल ड्रोन हमले हुए, तेल बाजारों में तुरंत बड़ी आशंका छा गई। ड्रोन हमलों के दो/तीन दिनों के भीतर ही आपके चैनल ईटी नाऊ ने मुझसे इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा था और मेरा जवाब था कि मैं कम कम दो हफ्ते की प्रतीक्षा करूँगा, यह देखने के लिए कि सऊदी अरब की पुनरुत्थान योजना क्या है। लेकिन सौभाग्य से, बिना समय गंवाए, सऊदी के अधिकारियों ने एक पुनरुत्थान योजना बनाई और आघात को अल्पकालिक कर दिया। समय अनिश्चित है, पर ये अच्छा है कि अनिश्चितता का तत्व कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में, अक्टूबर 2019 में आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनीटरी एंड फाइनेंशियल (आईएफएमसी) मीटिंग के प्रारंभिक सत्र में मैंने अपनी टिप्पणी में कहा था कि सुस्ती को गहराने से रोकने के लिए हमें अभी मिलकर काम करने की जरूरत है।

भारत में वैश्विक वृद्धि पर काफी बात होती है क्योंकि यह घरेलू वृद्धि को प्रभावित करता है। मेरा मतलब यह नहीं कि देश में जो धीमापन हम देख रहे हैं, वह पूरी तरह वैश्विक कारणों के चलते है, पर उनका असर तो है। भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, वृद्धि को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है – वैश्विक वृद्धि में उनके योगदान को देखते हुए – और इसलिए, सभी देशों द्वारा समन्वित व समय से कार्रवाई की जरूरत है। ये बात अच्छी तरह समझी जानी चाहिए।

2008 में जब जीएफसी हुआ, बहुपक्षवाद वैश्विक चर्चा में आगे था। दस वर्षों बाद, आज, जब वैश्विक सुस्ती है, तो यह प्रमुख विषय नहीं रहा – द्विपक्षवाद ने बहुपक्षवाद की भावना का स्थान ले लिया है। जीएफसी के बाद सभी जी-20 देशों ने साथ आकर वृद्धि को पुनर्जागृत करने की एक वैश्विक कार्य योजना बनाई। वर्तमान परिदृश्य में हमें उस तरह की वैश्विक कार्रवाई नहीं दिखती। मैं इतनी ही उम्मीद करता हूँ कि वैश्विक वृद्धि शिथिलता (हिस्टेरिसिस) का शिकार न हो। अर्थात्, देशों द्वारा कार्रवाई में देरी सुधार प्रक्रिया को पीछे न छोड़ दे या उसे बेअसर न कर दे। उदाहरण के लिए, पिछली दो तिमाहियों से यूरो क्षेत्र (ईए) में तिमाही वृद्धि (वार्षिकीकृत) – इस वर्ष की दूसरी व तीसरी तिमाही में 0.8 प्रतिशत – के स्थिर होने के बावजूद, ईए के लिए यह वांछनीय नहीं है। हम देख रहे हैं कि कई बड़े यूरोपीय देशों में राजकोषीय कार्रवाई की गुंजाइश है, पर उस मोर्चे पर बात आगे बढ़ती नहीं दिख रही। राजकोषीय कार्रवाई रोके रखने के इन देशों के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के रूप में और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक गवर्नरों से बातचीत के बाद महसूस होता है कि यूरोप में राजकोषीय कार्रवाई में कुछ देर है और 2008 जैसी राजकोषीय कार्रवाई हमें अभी तक देखने को नहीं मिली। वास्तव में यह नोट करने लायक है कि, यूरोपीयन सेंट्रल बैंक

की नई चीफ सुश्री क्रिस्टाइन लगाई ने ईए के जिन देशों से हो सके, उनके द्वारा कुछ राजकोषीय विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है।

विश्व वृद्धि परिदृश्य पर आए तो हम पाते हैं कि यूएस अर्थव्यवस्था में, 2019 की दूसरी तिमाही के 2.0 प्रतिशत की तुलना में तीसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ. सुधार के हल्के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तिमाही में -0.8 प्रतिशत की चौकाने वाली वृद्धि वाले यूके ने तीसरी तिमाही में 1.2 प्रतिशत की वार्षिकीकृत वृद्धि दर्ज की। चीन में वृद्धि में हास है। दक्षिण अफ्रिका की वृद्धि दूसरी तिमाही के 3.2 प्रतिशत से घटकर तीसरी तिमाही में -0.6 प्रतिशत पर आ गई है। ब्राजिल ने मामूली सुधार दर्शाया है। तथापि समग्र तस्वीर अस्पष्ट बनी हुई है।

सौभाग्य से, भारत में सरकार व रिज़र्व बैंक दोनों ने समय पर कदम उठाए। आरबीआई के बारे में कह सकता हूँ कि, धीमेपन को हमने बढ़ता हुआ भाँपकर फरवरी 2019 में जब दरों में कटौती की तो बाजार आरबीआई की समय से पहले की इस कार्रवाई से कुछ चौंके थे। अपनी तरफ से सरकार ने भी, पिछले पाँच से छह महीनों में कई नीतिगत कदमों की घोषणा की है।

अपने वक्तव्य का यह हिस्सा यह कहकर समाप्त करूँगा कि सभी देशों में एक साथ आ रहे धीमेपन के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

घरेलू आर्थिक वृद्धि

घरेलू अर्थव्यवस्था की बात करें तो विगत व वर्तमान वृद्धि चालकों को पहचानना आवश्यक है। विगत दो से तीन दशकों में भारत में वृद्धि की कहानी कैसे लिखी गई? आज कौन से क्षेत्र वह भूमिका निभा सकते हैं?

अतीत में वृद्धि के चालक

1990 के अंतिम वर्षों और 21वीं शताब्दी के पहले दशक में मूलतः सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने वृद्धि को नेतृत्व दिया। भारत ने आईटी धमाके का फायदा उठाया; दरअसल भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात 2000-01 के यूएस \$ 6.3 बिलियन से 13

गुना बढ़कर 2018-19 में यूएस \$ 83.5 बिलियन हो गया। इसी अवधि में दूरसंचार क्रांति भी घटित हुई, कई नौकरियां बनीं और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान मिला। आधार-संरचना क्षेत्र, विशेषतः हाइवे का निर्माण, भी स्वर्णिम चतुर्भुज और बाद के प्रयासों से बढ़ा। वैश्विक वृद्धि की लहर चढ़ते हुए, विनिर्माण उद्योग मुख्यतः भारत में आने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों जैसे फोर्ड, ह्यून्डाई, टोयोटा, रीनॉल्ट और निसान आदि द्वारा चालित हुआ। मारुति और अशोक लीलैंड ने विस्तार किया और निर्विमाण (मैन्यूफैक्चरिंग) के नए केंद्र बने। इसी प्रकार, बड़ी वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों ने भारत में अपने बेस बनाने शुरू किए। आगे, अतुल्य भारत अभियान आरंभ किया गया और भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत में रुचि लेने लगे। वस्तुतः, पर्यटन क्षेत्र से प्राप्तियां 2000-01 के यूएस \$ 3.5 बिलियन से लगभग 8 गुना बढ़कर 2018-19 में यूएस \$ 28.4 बिलियन हो गईं। इस प्रकार 1990 के अंतिम और सदी के शुरुआती वर्षों में वृद्धि मुख्यतः आईटी, दूरसंचार, विनिर्माण, विशेषतः ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यटन द्वारा चालित हुई। सेवा क्षेत्र में संबंधित वर्गों ने भी साथ-साथ विस्तार का अनुभव किया।

आज के वृद्धि के चालक कौन हो सकते हैं?

आगे चलकर, भारत को वैश्विक विनिर्माण मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने का प्रयास करना और बनना चाहिए। हम वैश्विक मूल्य श्रृंखला से काफ़ी अलग-थलग रहे हैं। अतः अतीत में जब प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं ने सुस्ती का अनुभव किया, भारत खास प्रभावित नहीं हुआ था। यह इससे बहुत देर तक स्थायी रूप से दूर रहने का कोई कारण नहीं हो सकता। हमारे जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए, जो विश्व में उत्तरोत्तर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अहम भूमिका निभाना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि सरकार में नीति बनाने वाले इस पक्ष पर ध्यान देंगे। दरअसल हाल के महीनों व वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं; तथापि और भी कदम आवश्यक हैं।

खाद्य प्रसंस्करण एक और क्षेत्र हो सकता है। वस्त्र उद्योग में भी अपनी धाक हमें वापस पानी है। विनिर्माण व पर्यटन क्षेत्र के अवसरों को और खंगालने की जरूरत है। आधार-संरचना पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा व्यय एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राज्यों का पूंजीगत व्यय विगत कुछ वर्षों में उनके जीडीपी का 2.6 – 2.7 प्रतिशत रहा है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में अनुकूल माहौल बनाने में ई-कॉमर्स और स्टार्ट-अप्स नए अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं और कई कदम उठाए भी गए हैं।

वृद्धि के पुनरुत्थान में आरबीआई की भूमिका बहुमुखी रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, माँग को जागृत करने के लिए फरवरी 2019 और अब के बीच हमने नीतिगत दर पहले से ही 135 आधार अंक घटा दिए हैं। उदार रुख के अनुसार, रिजर्व बैंक ने बड़ी मात्रा में चलनिधि प्रणाली में डाली है जो लंबे समय तक कमी में थी। वर्तमान में सिस्टम में लगभग 2.5 – 3.0 लाख करोड़ का दैनिक अधिशेष (सरप्लस) है - पैसे की मात्रा जो हम रिवर्स रिपो कार्रवाइयों से हर दिन सोख रहे हैं।

ऋण का बेहतर और अधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, हमने कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं - बैंकों से एनबीएफसी को जाने वाले सिंगल एक्सपोजर लीमिट को हमने बढ़ाया है; कुछ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को आगे ऋण देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एनबीएफसी को उधार देने की अनुमति दी है; बासल-निर्धारित मानकों के तहत समष्टि-विवेकी सिद्धांतों से समझौता किए बिना हमने व्यक्तियों को दिए जाने वाले कुछ कर्जों के मामले में, बैंकों के लिए जोखिम भार घटाए हैं।

वित्तीय स्थिरता कायम करने में आरबीआई की भूमिका

इसके साथ ही मैं वित्तीय स्थिरता कायम करने में आरबीआई की भूमिका पर आता हूँ। इस संबंध में मैं कुछ रोचक तथ्य शेयर करना चाहूँगा। मैंने मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संक्षेप में इस पर बोला था, लेकिन मैं कुछ बिंदुओं पर फिर से प्रकाश डालना चाहूँगा। हमने 1539 सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों का एक सर्वेक्षण किया था और 2019-20 की पहली छमाही के उनके अलेखापरीक्षित अर्धवार्षिक विवरणों का एक विश्लेषण किया गया जिससे निम्नलिखित संकेत मिलते हैं:

- इन विनिर्माण कंपनियों ने 2019-20 की पहली छमाही के दौरान पूंजीगत चालू-कार्य सहित अचल संपत्तियों में निवेश बढ़ाया है।
- पिछले वर्ष के पहले छह महीनों में 18.9 प्रतिशत की तुलना में इन कंपनियों के पास उपलब्ध धन का 45.6 प्रतिशत अचल संपत्तियों में लगाया गया, जिसका अर्थ है कि विनिर्माण कंपनियों के पास कुछ फंड था जिसे अचल संपत्ति (फिक्स्ड एसेट) में डाल दिया गया था। इसका शायद यह मतलब है कि निवेश चक्र में पुनरुत्थान के कुछ संकेत दिखने लगे हैं। इसके साथ मैं इतना अवश्य जोड़ दूँ कि किसी निष्कर्ष पर पहुँचना जल्दबाजी होगी। जो भी हो, यह एक दिलचस्प तथ्य है जिस पर ध्यान देना चाहिए।
- हमारे विश्लेषण से यह भी पता चला है कि इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के दौरान कुछ मात्रा में डीलीवरेजिंग (यानी उधार में कमी) के प्रमाण हैं। 2019-20 की पहली छमाही में दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार को कम करने के लिए प्रयुक्त उपलब्ध धन का अनुपात क्रमशः 11 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत था।
- कई कंपनियां अपनी कार्यशील पूँजी सीमा का पूरा लाभ नहीं उठा रही हैं, जो हो सकता है कि बहुत अच्छा संकेत न हो। यह आर्थिक गतिविधियों में कुछ सुस्ती की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर, इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि उनके पास पर्याप्त अधिशेष है, जिसका उपयोग उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, उनसे निवेश में इन फंडों के अधिक उपयोग की उम्मीद की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, सिस्टम में एक निश्चित मात्रा में पूंजी उपलब्ध है जिसे निवेश चक्र में फीड करने की जरूरत है।

इसे कैसे समझा जाए? मुझे लगता है कॉरपोरेट्स में बैलेंस शीट की सफ़ाई की कोई प्रक्रिया चल रही है। जहाँ तक इन

कॉर्पोरेट्स का सवाल है, नए निवेशों की योजना सोच समझ कर बनाई जा रही है। कुछ फंड्स, कुछ निवेश योग्य संसाधन उनके पास हैं लेकिन अपनी निवेश योजना फिर से शुरू करने से पहले वे डिलीवरेजिंग और अपने बैलेंस शीट ठीक करने की प्रक्रिया में हैं।

बैंक और एनबीएफसी भी अपनी बैलेंस शीट ठीक कर रहे हैं। ये सकारात्मक संकेत हैं जो भविष्य की वृद्धि का आधार तैयार कर रहे हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के मामले में, हमने पाया कि मार्च 2019 के अंत में प्रणाली स्तर पर जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) लगभग 14.3 प्रतिशत है। दूसरे देशों, जैसे चीन व यूएस के तुलनात्मक आँकड़े क्रमशः 14.1 और 14.9 प्रतिशत हैं। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि फ्रांस व जर्मनी जैसे विकसित यूरोपीय देशों के मामले में यह थोड़ा ज्यादा, 18-19 प्रतिशत है। लेकिन हमारा 14.3 प्रतिशत विनियामक अपेक्षा¹ से काफी अधिक है।

दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या पर भी ध्यान दिया जा रहा है और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निपटान ने गति पकड़ी है। एस्सार स्टील के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने निपटान के बड़े मुद्दे को सुलझा दिया है जो एक अर्से से लंबित चल रहा था। सकल आस्तियों के आँकड़े में सुधार है। लंबे समय के बाद, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लाभअर्जकता में कुछ प्रत्यक्ष सुधार आया।

इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका विनियम और पर्यवेक्षण को मजबूत करने पर केंद्रित रही है ताकि वित्तीय स्थिरता का एक मजबूत ढाँचा बनाया या सुगम किया जा सके जहाँ बैंक व एनबीएफसी समाज की प्रत्याशाओं को पूरा कर सकें। हमने हाल के महीनों में बैंकों व एनबीएफसी के विनियम की एक समीक्षा की है और उनके पर्यवेक्षण में कई सुधार किए हैं। हमने पर्यवेक्षण व विनियम के अलग विभाग बनाए हैं; अपने कार्मिकों के पर्यवेक्षण कौशल को बेहतर करने के लिए एक

कॉलेज ऑफ़ सुपरवाइज़र बनाया जा रहा है और विनियम और पर्यवेक्षण विभागों में एक आंतरिक शोध व विश्लेषण स्कंध बनाया जा रहा है जिससे इन विभागों को विश्लेषणात्मक व अनुसंधान सामग्री मिले। अपनी वित्तीय प्रणाली के आपस में जुड़े होने के कारण शोध व विश्लेषण का यह स्कंध चीजों पर एक साथ नजर डाल पाएगा; उनको सहसंबंधित कर पाएगा और मुद्दों को समग्रता में देख पाएगा; और यदि कोई संभावित नाजुक व कमजोर बिंदु उभरकर सामने आने वाले हों तो उसका पता लगाएगा।

हमें 21वीं शताब्दी की बैंकिंग पर ध्यान देने की जरूरत है जिसमें डिजिटल बैंकिंग में अभी काफी गतिविधि हो रही है। हमलोगों ने फिनटेक के लिए एक 'विनियामक सैंडबॉक्स' बनाया है। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक ने (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई)) का एक प्रकार का मॉडल बनाने में एक अहम भूमिका अदा की है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) ने हाल में प्रकाशित एक पत्र में कहा है कि भारत का यूपीआई फ्रेमवर्क न केवल देशों के अंदर बल्कि एक देश से दूसरे देश में भी तेज और अबाध भुगतानों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बन सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने यूपीआई मॉडल को बिजनेस योजना की तरह दूसरे देशों में ले जाने पर ध्यान देने के लिए एक अनुषंगी संगठन बनाने का निर्णय लिया है।

संप्रेषण की भूमिका

इन कार्यों के दौरान, एक अहम क्षेत्र, जिस पर चर्चा नहीं होती, पर जिसका मैं अलग से उल्लेख करना चाहूँगा वो है संप्रेषण। केंद्रीय बैंक के संप्रेषण पर अलग-अलग मत हैं, पर इसे नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी केंद्रीय बैंक के कार्य में इसकी बड़ी अहम भूमिका है। अतीत में कुछ केंद्रीय बैंक यह मानते थे कि केंद्रीय बैंक का संप्रेषण आनंददायक रूप से अस्पष्ट होना चाहिए। यानी, गवर्नर की बात समाप्त होने पर, जब कोई यह समझना चाहे कि उन्होंने क्या कहा, तो उसे समझ में

¹ मार्च 2019 के अंत की स्थिति, सीआरएआर मार्च 2013 के अंत के 14.3 प्रतिशत से बढ़कर 15.1 प्रतिशत हो गया।

यही आता है कि उन्होंने या तो कुछ भी नहीं कहा या कुछ भी नया नहीं कहा। इसका प्रतिपक्षी विचार यह है कि केंद्रीय बैंक संप्रेषण से स्पष्टता आए, नीति निर्माण में पारदर्शिता आए और भविष्य का मार्गदर्शन मिले।

यह आकलन आपको करना है कि इस मामले में हम कैसे रहे हैं, पर हाल के महीनों में हमने अपना संप्रेषण सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह पहली बार है क्योंकि पहले भी यह हुआ है – लेकिन अधिकांशतः आरबीआई के संप्रेषण का फोकस निर्णयों की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने और यथासंभव पारदर्शी होने पर रहा है। दरअसल, मैं कह सकता हूँ कि विगत कुछ महीनों में, हमने जब कभी भी कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है, हमने विश्लेषकों, अनुसंधानकर्ताओं और मीडिया कर्मियों के साथ विस्तृत व लंबी बैठके की हैं। हमने अकादमिक व शोध संस्थाओं से भी चर्चा की है और ये खुले में नहीं होती ताकि चर्चा का प्रवाह अबाध और स्पष्ट हो तथा हम नीति-निर्माण की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास कर पाएं। पहली बार, हमने अपने बड़े नीतिगत निर्णयों, विशेषतः मौद्रिक नीति पर भविष्य का मार्गदर्शन भी देना शुरू किया है। आप लोगों को कुछ उदाहरण दूँ :

- i. लगभग छह महीने पहले, एक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) संकल्प में हमने कहा था कि जब तक मुद्रा स्फीति नियंत्रण में हो, वृद्धि एक सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। हमने साफ संदेश दिया कि जहाँ तक रिज़र्व बैंक का सवाल है, मौद्रिक नीति और एमपीसी का सवाल है, वृद्धि एक सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है।
- ii. कुछ महीने पहले जब हमने अपने रुख को उदार किया तो बाजार को कुछ फॉरवर्ड गाइडेंस देने के लिए, हमने एमपीसी संकल्प में कहा था कि वृद्धि को जागृत करने के लिए जहाँ तक जरूरी होगा, मुद्रास्फीति पर ध्यान रखते हुए रिज़र्व बैंक उदार रुख जारी रखेगा।

- iii. पिछली एमपीसी मीटिंग में हमने जब विराम (पॉज़) लिया तो पता नहीं क्यों, बाजारों ने कहा कि वे चकित हो गए। मुझे पता चला कि बाजार फरवरी के हमारे नीतिगत निर्णय से चकित हुआ था, लेकिन बाद में मुझे खुशी हुई और आप सबको इसे स्वीकारने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह सही निर्णय था। इस बार भी, हमने जो विराम लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे के घटनाक्रम एमपीसी के निर्णय को सही साबित करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह नहीं है और केवल समय ही बता सकता है कि परिस्थितियाँ कैसे आगे बढ़ेंगी। जब हमने विराम लिया, एमपीसी ने साफ माना कि मौद्रिक अवकाश है और उसका उपयोग ये, मुद्रास्फीति व वृद्धि के मिलने वाले आँकड़ों को देखते हुए, जरूरत के अनुसार करेगी। इसे भावी मार्गदर्शन का एक उदाहरण समझा जा सकता है जहाँ विराम के कारणों को एमपीसी संकल्प में और प्रेस कॉन्फरेंस में मेरे वक्तव्य में विस्तार से समझाया गया है। आरबीआई की वेबसाइट पर यह उपलब्ध है। विराम के अपने निर्णय में, जहाँ हमने ये कहा है कि मौद्रिक नीति कार्रवाई की गुंजाइश है, वहीं हमने बड़ी सावधानी और पक्के तौर पर यह भी कहा है कि इसकी टाइमिंग इस प्रकार तय की जाए कि इसका प्रभाव पर्याप्त व अधिकाधिक हो।

दरअसल, हमने अन्य नीतिगत कार्रवाइयों में भी काफ़ी पारदर्शिता लानने की कोशिश की है जो संप्रेषण पर ध्यान को दर्शाता है। संप्रेषण की शक्ति समझाने के लिए, मैं 2008 के जीएफसी और उस समय यूएसफेड द्वारा अपनाई गई उदार नीति का उदाहरण देना चाहूँगा। उस समय संप्रेषण बड़ा दमदार था; अतः अंतरराष्ट्रीय बाजारों और विश्लेषकों ने इसे स्वीकार किया। फेड क्या करने जा रहा है, यह हर कोई समझ गया। 2013 में कथित टेपर टैंट्रम में यूएस फेड के संप्रेषण में वो ताकत नहीं थी – सिर्फ़ इस उल्लेख से, कि वे शायद उदार नीति को रोल बैक करने या उधेड़ने (अनवाइंड करने) वाले हैं,

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में भारी तबाही और अस्थिरता आ गई। इस प्रकार, संप्रेषण एक ताकतवर औजार है। केंद्रीय बैंक का कोई भी निर्णय, संप्रेषण द्वारा समर्थित होना चाहिए। और ये तो है ही कि संप्रेषण को कार्रवाई द्वारा समर्थित होना चाहिए और खोखले शब्द कभी नहीं होने चाहिए।

समापन

मैं यह कर समापन करना चाहूँगा कि भारत जैसी जटिल व अंतर्संबद्ध अर्थव्यवस्था में, मौद्रिक नीति, वित्तीय बाजारों के विनियम व पर्यवेक्षण तथा अन्य बातों के साथ-साथ धोखाधड़ी पकड़ने, जोखिम प्रबंधन और बैंकों व बैंकेतर इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के क्षेत्रों से भी चुनौतियां आती हैं।

फलतः केंद्रीय बैंक में एक भी क्षण नीरस नहीं होता। हमेशा चुनौतियों से भरा होता है; महत्वपूर्ण यह है कि हमें इन पर समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। हाल ही में मुंबई में एक पुराने साथी ने कहा कि रिज़र्व बैंक की ऊँची मंजिलों पर आपको दो अलग—अलग दिशाओं से हवाओं का प्रवाह मिलेगा। मुझे लगा वे रिज़र्व बैंक की जटिल भूमिका के बारे में संकेत कर रहे हैं और फिर मैंने समझा कि वे यह कहना चाह रहे हैं कि हवा वाकई दो भिन्न दिशाओं से आती है। उनको मेरा उत्तर था:

“तब तो यह दर्शाता है कि भारत जैसी जटिल अर्थव्यवस्था में रिज़र्व बैंक की भूमिका कितनी जटिल व चुनौतीपूर्ण है!”
धन्यवाद!

भारत में समावेशी विकास की ओर यात्रा*

शक्तिकांत दास

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से श्री थर्मन शन्मुगरत्नम का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ जो प्रोफेसर सुरेश तेंडुलकर स्मृति व्याख्यान श्रृंखला का तीसरा व्याख्यान देने के लिए पधारे हैं। आज स्वर्गीय प्रोफेसर सुरेश तेंडुलकर की पत्नी श्रीमती सुनेत्रा तेंडुलकर और उनकी बेटी श्रीमती साई सप्रे की यहाँ उपस्थिति से भी हम बड़े सम्मानित महसूस कर रहे हैं। रिज़र्व बैंक की ओर से आमंत्रित सभी विशिष्ट सम्मानित जनों का हार्दिक स्वागत।

प्रो. सुरेश डी तेंडुलकर के बारे में

प्रो. सुरेश डी तेंडुलकर एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री और नीति विश्लेषक थे। देश में जीवन स्तर की माप व विश्लेषण पर उनका मौलिक कार्य, लोक नीति निरूपण में उनकी स्थायी विरासत रहेगा। वस्तुतः गरीबी के प्रति गहरी संवेदनशीलता और गरीबी को समझने के लिए आँकड़ा – आधारित शोध के प्रति प्रतिबद्धता ऐसी विशेषताएं हैं जो एक पेशेवर अर्थशास्त्री के रूप में प्रोफेसर तेंडुलकर के जीवन को परिभाषित करती हैं।

उनका अकादमिक रिकॉर्ड जबरदस्त और बड़ी उपलब्धियों से भरा था। उन्होंने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान 1968 में ज्वाइन किया। इसके बाद उनको वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर में दो वर्ष का प्रतिष्ठित दायित्व मिला। 1978 से लेकर 2004 में अवकाश ग्रहण तक दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स में उनका कार्यकाल उपलब्धियों भर रहा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों (एनएसएस) के अभिकल्प (डिज़ाइन) व संचालन के कई कार्य दलों में उन्होंने कार्य किया तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) के अध्यक्ष; राष्ट्रीय लेखा परामर्श समिति (नेशनल अकाउंट्स एडवाइजरी कमिटी) के अध्यक्ष; और राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष रहे। वे

* श्री थर्मन शन्मुगरत्नम, वरिष्ठ मंत्री, सिंगापुर गणराज्य द्वारा 07 जनवरी 2020 को दिए गए सुरेश तेंडुलकर स्मृति व्याख्यान में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उद्बोधन वक्तव्य।

199 में गरीबी आकलन पर लकड़ावाला समिति के सदस्य थे जिसने गरीबी के आकलन के लिए राज्यों के अनुसार विशिष्ट उपभोग टोकरी/समूह (बास्केट) का सुझाव दिया था। 2004 व 2008 में वे प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हुए और 2008 में इस परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

2006 से 21 जून 2011 तक अपने दुखद निधन तक प्रो. तेंडुलकर ने रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक और पूर्वी स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दी। अर्थशास्त्र के कार्य में उनके योगदान व रिज़र्व बैंक से उनके संबंध के सम्मान में यह व्याख्यान श्रृंखला 2013 में प्रारंभ की गई थी।

श्री थर्मन शन्मुगरत्नम के बारे में

मुझे प्रसन्नता है कि श्री थर्मन शन्मुगरत्नम, 7 वर्षों के अंतराल के बाद ही सही, तृतीय सुरेश तेंडुलकर स्मारक व्याख्यान के लिए रिज़र्व बैंक आने के लिए तैयार हुए। इसके पहले वे सितंबर 2012 में 13वां एल के झा स्मारक व्याख्यान देने के लिए आए थे। श्री शन्मुगरत्नम एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व एक राजनैतिक व्यक्तित्व हैं। उनका कर्मजीवन लोक सेवा तथा आर्थिक व सामाजिक नीतियों में प्रमुख भूमिकाओं में बीता है। वर्तमान में वे सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री और सामाजिक नीतियों के लिए समन्वय मंत्री के रूप में भी कार्य कर रहे हैं तथा आर्थिक नीतियों पर सिंगापुर के प्रधान मंत्री के सलाहकार हैं। साथ ही, वे मॉनिटरी अथॉरिटी आफ़ सिंगापुर (एमएस) के अध्यक्ष और गवर्नमेंट ऑफ़ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं।

श्री शन्मुगरत्नम ने मॉनिटरी अथॉरिटी आफ़ सिंगापुर के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। बाद में वे सिंगापुर प्रशासनिक सेवा से जुड़े और शिक्षा मंत्रालय में पॉलिसी के वरिष्ठ उप सचिव रहे। बाद में 2001 में जब वे जुरॉन्ग ग्रुप रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग के सदस्य चुने गए, उनके राजनैतिक जीवन की शुरुआत हुई, और तब से तीन बार पुनर्निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों तथा 2011 के आम चुनाव के बाद उप प्रधान मंत्री के रूप में भी कार्य किया है।

श्री शन्मुगरत्नम ग्रुप ऑफ़ थर्टी नामक आर्थिक व वित्तीय नेताओं के एक स्वतंत्र वैश्विक परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जी20 एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप ऑन ग्लोबल फाइनेंसियल गवर्नेन्स की भी अध्यक्षता की है जिसने वैश्विक विकास वित्त और वित्तीय स्थिरता की अधिक प्रभावी व्यवस्था के मानक सुझाए हैं। विगत में उन्होंने आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंसियल कमिटी को नेतृत्व दिया है, वे संयुक्त राष्ट्र की 2019 मानव विकास रिपोर्ट के परामर्शी (एडवाइजरी) बोर्ड की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

आज के लिए श्री शन्मुगरत्नम द्वारा चुना गया “व्यापक आधार की समृद्धि: आधारभूत का समाधान” का विषय पूरे विश्व और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रासंगिक है। व्यापक आधार की समृद्धि का महत्त्व बहुत पहले से ही अच्छी तरह माना गया है और आर्थिक वृद्धि के लाभ व्यापक जनता तक पहुँचाने को सुनिश्चित करने की जरूरत पर सहमति है। एक विचार और नीतिगत उद्देश्य के रूप में, यह समावेशी विकास की अवधारणा के जैसा है। एक अधिक समानता वाली सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था प्राप्त करने को लेकर जहाँ दुनिया और देश में भी सहमति है, आधारभूत पक्षों पर ध्यान देना और वृहत्तर समावेश को सुगम करने वाली व्यवस्था बनाना भी उतना ही आवश्यक है। अंतर्निहित विषय संरचनात्मक सुधार ही होंगे।

इस संदर्भ में, कीमतों में स्थिरता, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक वृद्धि पर आरबीआई को दिया गया अधिदेश न केवल समष्टि-आर्थिक परिप्रेक्ष्य बल्कि समावेशी विकास के उद्देश्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। लगातार ऊँची मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की आबंटन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और वृद्धि में बाधक है। यह आय वितरण को बदतर करती है क्योंकि इससे गरीबों की वास्तविक आय का मूल्यहास हो जाता है। जी20 देशों की तुलना में बहुत ऊँची घरेलू मुद्रास्फीति को देखते हुए हमने 2016 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढाँचा अपनाया जिसके अंतर्गत मूल्य स्थिरता के उद्देश्य एवं साथ ही, मुद्रास्फीति नियंत्रण में हो तो वृद्धि पर ध्यान देने को प्रधानता दी गई है।

इसी प्रकार, वित्तीय स्थिरता के साथ ऊँची वृद्धि समावेशी विकास के लिए अच्छी होती है। ऊँची वृद्धि धन सृजन और इसकी प्रसार प्रभाव की प्रक्रिया के जरिये समावेश ला सकती है। मुझे ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, पर ऊँची वृद्धि से टैक्स-जीडीपी अनुपात में सुधार आता है जिससे सरकार को सामाजिक व बुनियादी संरचना व्यय के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। पुनः, स्वस्थ बैंकों व एनबीएफसी वाली एक अच्छी वित्तीय प्रणाली पिरामिड के तल वालों की ऋण जरूरतों को पूरा करने में अच्छी भूमिका निभा सकती है। इसलिए, हम वित्तीय स्थिरता का सुदृढ़ ढाँचा विकसित करने के लिए विनियम और पर्यवेक्षण को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं जिससे बैंक और एनबीएफसी समाज की प्रत्याशाओं को पूरा कर सकें।

सामाजिक समावेश हासिल करने व आय की असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने अत्यंत छोटे स्तर पर भी कई कदम उठाए हैं। भारतीय संदर्भ में वित्तीय समावेश को एक वृहत्तर संरचनात्मक सुधार एजेंडा के अंग के रूप में देखा जाता है। बैंकिंग सेवाओं को सुगम करने वाली *जन धन योजना* ने विकास प्रक्रिया के लाभ वृहत्तर जनता तक पहुँचाने के अवसर व दायरे को बढ़ा दिए हैं। पीएम-किसान, ई-नैम आदि अन्य योजनाएं आय का सहारा बनने व किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं।

कृषि व बाजार सुधारों के क्षेत्र में, इस पर सहमति है कि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार समावेशी विकास को बढ़ाने का प्रमुख जरिया हो सकता है क्योंकि इससे उपभोक्ताओं द्वारा दी गई कीमतों में किसानों का हिस्सा बढ़ सकता है। 16 राज्यों में फैली 85 मंडियों में किसानों, व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के बीच 2018 में आरबीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने बताया कि अलग-अलग फसलों व केंद्रों में उपभोक्ता द्वारा दिए गए खुदरा मूल्य और किसानों को मिलने वाली मंडी कीमतें (अर्थात् मार्जिन या मार्क-अप) अलग-अलग हैं। प्रमुख प्राथमिक खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में किसानों का औसत हिस्सा 28-78 प्रतिशत की रेंज में है। यह विकारी वस्तुओं के मामले में कम व अविकारी वस्तुओं में ज्यादा है। किसानों को खुदरा कीमतों का बड़ा हिस्सा मिलना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा

है जो घरेलू माँग बनाए रखने में सहायक हो सकता है। बड़े ग्रामीण रोड नेटवर्क, सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बेहतर संचार सुविधाओं और सूक्ष्म ऋण की आसान उपलब्धता के लिए उठाए गए कदम किसानों को बेहतर कीमत दिलाने में सहायक होंगे। निरंतर चलने वाली इस प्रक्रिया को कृषि बाजार में आगे के सुधारों के साथ बनाए रखने की जरूरत है। नीति एजेंडा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता, उपभोक्ताओं को किसानों द्वारा कृषि उत्पाद की सीधी बिक्री, बेहतर कीमत निर्धारण के लिए ई-नैम का सुदृढीकरण और उत्पादक केंद्रों के समीप भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा देने से कृषि आय और ग्रामीण रोजगार अवसर बढ़ेंगे।

असेवित व अल्पसेवित इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। हाल में आरबीआई द्वारा बनाई गई वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय रणनीति (2019-24) को वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद (एफएसडीसी) ने मान्यता दी है। यह भारत में वित्तीय समावेश का विज्ञान व प्रमुख उद्देश्य तय करता है और इसके लक्ष्य हैं, औपचारिक व किरायायती वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना; वित्तीय समावेश का प्रसार और गहनता; और वित्तीय साक्षरता व ग्राहक संरक्षण को बढ़ावा।

आरबीआई के दूसरे कदमों में हैं सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) और कृषि क्षेत्र को जाने वाले ऋण प्रवाहों से जुड़े विषयों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति और एक कार्य दल का गठन। वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानकों के माध्यम से हम कृषि व कृषेतर गतिविधियों को सहारा देना चाहते हैं जो आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए रोजगार का साधन हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण मानकों की अब हम समीक्षा कर रहे हैं, ताकि ये मानक अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों के मुताबिक हों और इनको अधिक समावेशी बनाया जा सके। लीड बैंक स्कीम, नो फ्रिल्स अकाउंट, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बैंकिंग फेसिलिटेटर मॉडलों और मोबाइल बैंकिंग, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों आदि ने भी इन प्रयासों में सहायता पहुँचाई है।

जनता के लाभ के लिए लेटेस्ट तकनीक का प्रयोग भी रिज़र्व बैंक के नीतिगत एजेंडे में है। हर भारतीय को ई-पेमेंट के संरक्षित, सुरक्षित, सुविधाजनक, तेज और किरायायती विकल्पों की ताकत देने के विज्ञान को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक राष्ट्रीय भुगतान आधार-संरचना व तकनीक प्लेटफॉर्मों को विकसित करने पर ध्यान दिया गया है। हाल में 16 दिसंबर 2019 को हमने 24x7x365 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक अंतरण (एनईएफटी) सुविधा शुरू की। इसके साथ, भारत उन गिने-चुने विशिष्ट देशों की पंक्ति में चला गया है जिनके पास चौबीसों घण्टे तत्काल (रीयल टाइम) फंड्स ट्रांसफर और निपटान वाली भुगतान प्रणाली है। निपटान की सुविधा के लिए, आरबीआई ने सहभागी बैंकों के लिए 24x7 आधार पर चलनिधि अवलंब सुविधा भी दी है। हमने एनईएफटी पर लगने वाले प्रभार हटा दिए हैं। बचत बैंक ग्राहक अब आनलाइन एनईएफटी लेन-देन निःशुल्क कर सकते हैं। आग चलकर, इससे बड़ी मूल्य वाली तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली भी देश को 24x7 आधार पर देने का मार्ग खुलेगा। फिलहाल, हमने आरटीजीएस की टाइमिंग बढ़ा दी है।

अल्प मूल्य डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए, हाल ही में रु.10,000 तक के बकाया शेष वाले एक नए प्रकार का प्रिपेड इनस्ट्रुमेंट (पीपीआई) शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने और डिजिटल भुगतान शिकायतों के प्रभावी निपटान के लिए, एक डिजिटल लोकपाल (ओमबड्समैन) योजना प्रारंभ की गई है। हाल में 1 जनवरी, 2020 को रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकनोट के मूल्यवर्ग की पहचान करने में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (मणि) नामक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं “व्यापक आधार की समृद्धि: आधारभूत का समाधान” पर अपने विचार साझा करने के लिए श्री थर्मन शन्मुगरत्नम को आमंत्रित करना चाहूँगा। व्याख्यान के बाद एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सत्र के लिए सदन खुला रहेगा।

लेख

भारत की बाह्य कर्ज वहनीयता और संवेदनशीलता का अध्ययन
आस्ति गुणवत्ता मूल्यांकन में क्रेडिट रेटिंग्स की प्रभावकारीता

भारत की बाह्य कर्ज वहनीयता और संवेदनशीलता का अध्ययन*

यह लेख भारत के बाह्य कर्ज प्रोफाइल और बाह्य संवेदनशीलता संकेतकों में हाल के दिनों में हुए परिवर्तनों का परीक्षण करता है। यद्यपि 2017-18 के बाद से भारत के बाह्य कर्ज का आकार बढ़ गया है, तथापि यह जीडीपी का लगभग 20 प्रतिशत बना हुआ है। जहां बाह्य कर्ज में वृद्धि काफी हद तक गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा लिए गए उधार के कारण थी, वहीं कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण (अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर) की हिस्सेदारी में 2017-18 के बाद से हुई वृद्धि का कारण अनिवासी जमा, वाणिज्यिक उधार और अल्पावधि व्यापारिक ऋणों में हुई वृद्धि थी। आरक्षित निधि पर्याप्तता संकेतकों के संदर्भ में भारत की बाह्य क्षेत्र संवेदनशीलता पहले के वर्षों की तुलना में लगातार कम रही। अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय रुपये और विश्व की अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रभाव भारत के बाह्य कर्ज के आकार पर पड़ता है जबकि इस पर चालू खाता घाटे (सीएडी) का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता।

भूमिका

जिन देशों का चालू खाता घाटा अत्यधिक बढ़ जाता है, वे आम तौर पर विदेशी इक्विटी और कर्ज से प्राप्त पूंजी के जरिए अपना वित्तपोषण करते हैं। घरेलू बचत और निवेश के बीच के अंतर को कम करते हुए विदेशी पूंजी इन देशों में निवेश और विकास को गति देती है। हालांकि, अतिशय बाह्य ऋणग्रस्तता को विकास के लिए हानिकारक माना जाता है क्योंकि इससे बाह्य आघातों और बाहरी संकटों से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए बाह्य कर्ज का विवेकपूर्ण प्रबंधन आवश्यक होता है।

भारत में वर्ष 2004-05 से लगातार चालू खाता घाटे (सीएडी) की स्थिति बनी हुई है। बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी),

* यह आलेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के जॉन वी. गुरिया और जितेंद्र सोकल द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और ये भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

अनिवासी जमा और अल्पकालिक व्यापारिक ऋण जैसे बाह्य कर्ज प्रवाह ने भारत में निरंतर बने हुए सीएडी के वित्तपोषण में इक्विटी प्रवाह के पूरक का काम किया है। इन प्रवाहों से भारत को प्रतिकूल बाह्य गतिविधियों (जैसे 2013 में टेपर टेंट्रम के दौरान) से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा आरक्षित बफर तैयार करने में भी मदद मिली है। चूंकि 1991 के भुगतानों शेष (बीओपी) के संकट के बाद 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शुरू किए गए प्रमुख आर्थिक सुधारों के बाद से, भारत ने अपने बाह्य कर्ज का विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया है और इसे लगातार वहनीय स्तर पर बनाए रखा है। भारत की अन्य बाह्य क्षेत्र नीतियों ने भी इसकी बाह्य संवेदनशीलता को कम बनाए रखने में मदद की है।

इसी पृष्ठभूमि में इस आलेख में भारत के बाह्य कर्ज संविभाग और ऋण स्थिरता और संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से आरक्षित निधि संबंधी बाह्य जोखिम संकेतकों में आए हालिया परिवर्तनों का परीक्षण किया गया है। आलेख के शेष भाग इस प्रकार हैं : अगले भाग में सितंबर 2019 के अंत में भारत के बाह्य कर्ज से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। तीसरे भाग में मार्च 2015 के अंत से सितंबर 2019 के अंत तक की अवधि के लिए भारत की बाह्य कर्ज स्थिरता और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। चौथा भाग भारत के बाह्य कर्ज पर मूल्यांकन प्रभाव की भूमिका का विश्लेषण करता है। पाँचवाँ भाग आरक्षित निधि की पर्याप्तता और भारत की बाह्य संवेदनशीलता का आकलन करता है। छठे भाग में समकक्ष ईएमई की तुलना में भारत के बाह्य कर्ज की स्थिति और संवेदनशीलता पर चर्चा की गयी है और इसके बाद निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

II. सितंबर 2019 के अंत में भारत का बाह्य कर्ज : सारांश

भारत का सीएडी 2018-19 में बढ़कर जीडीपी का 2.1 प्रतिशत हो गया जो कि एक साल पहले जीडीपी का 1.8 प्रतिशत था। हालांकि, 2019-20 के पहली छमाही में यह कम होकर जीडीपी का 1.5 प्रतिशत हो गया। भारत के बाह्य कर्ज में, उच्च सीएडी के बावजूद, 2018-19 में मामूली वृद्धि हुई क्योंकि घरेलू पूंजी बाजार के कर्ज संविभाग से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश का बहिर्वाह हो रहा था। वर्ष 2018-19 में और 2019-20 की पहली छमाही में बाह्य कर्ज में हुई वृद्धि मुख्य

रूप से ईसीबी, अनिवासी जमा, और अल्पकालिक व्यापार क्रेडिट के बढ़ने के कारण थी। मार्च 2019 के अंत में, भारत के बाह्य कर्ज में एक साल पहले के स्तर से 13.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी 2.6 प्रतिशत) की वृद्धि देखी गई और यह 543.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में तक पहुंच गया। आगे इसमें 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (यानी 2.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा सितंबर 2019 के अंत में यह 557.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

सितंबर 2019 के अंत में भारतीय रुपये और अन्य प्रमुख मुद्राओं (एसडीआर¹, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग) की तुलना में अमेरिकी डॉलर महंगा होने के परिणामस्वरूप होने वाला मूल्यन लाभ भारत के बाह्य कर्ज में वृद्धि के प्रभाव को आंशिक रूप से कम कर दिया। बाह्य कर्ज में मूल्यन लाभ 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जिसका मतलब है कि मार्च 2019 के अंत की स्थिति की तुलना में सितंबर 2019 के आखिर में बाह्य कर्ज में वृद्धि (मूल्यन प्रभाव को छोड़कर) 19.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही होगी न कि 14.3 बिलियन (वैल्यूएशन प्रभाव सहित) अमेरिकी डॉलर। यद्यपि पूर्णांकों में वृद्धि होने के बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बाह्य कर्ज में मामूली वृद्धि हुई और यह मार्च 2019 के अंत के 19.8 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2019 के अंत में 20.1 प्रतिशत हो गया। कर्ज चुकौती-चालू प्राप्तियाँ अनुपात कम होकर मार्च 2019 के अंत के 6.4 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2019 के अंत में 6.2 प्रतिशत हो गया।

सितंबर 2019 के अंत में, वाणिज्यिक उधार 38.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ बाह्य कर्ज का सबसे बड़ा घटक रहा, इसके बाद अनिवासी जमा (23.8 प्रतिशत) और अल्पकालिक व्यापार कर्ज (18.6 प्रतिशत) था। अल्पकालिक कर्ज (मूल परिपक्वता के आधार पर) में मार्च 2019 के अंत की स्थिति से 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सितंबर 2019 के अंत में यह 109.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था; हालांकि, इसी अवधि में कुल कर्ज में इसकी हिस्सेदारी 20.0 प्रतिशत से घटकर 19.6 प्रतिशत रह गई। अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर देखें तो, अल्पकालिक कर्ज सितंबर 2019 के अंत में 239.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, जो कि मार्च 2019 के अंत की स्थिति से 1.7 प्रतिशत अधिक था। हालांकि, कुल बाह्य कर्ज में इसका हिस्सा मार्च 2019

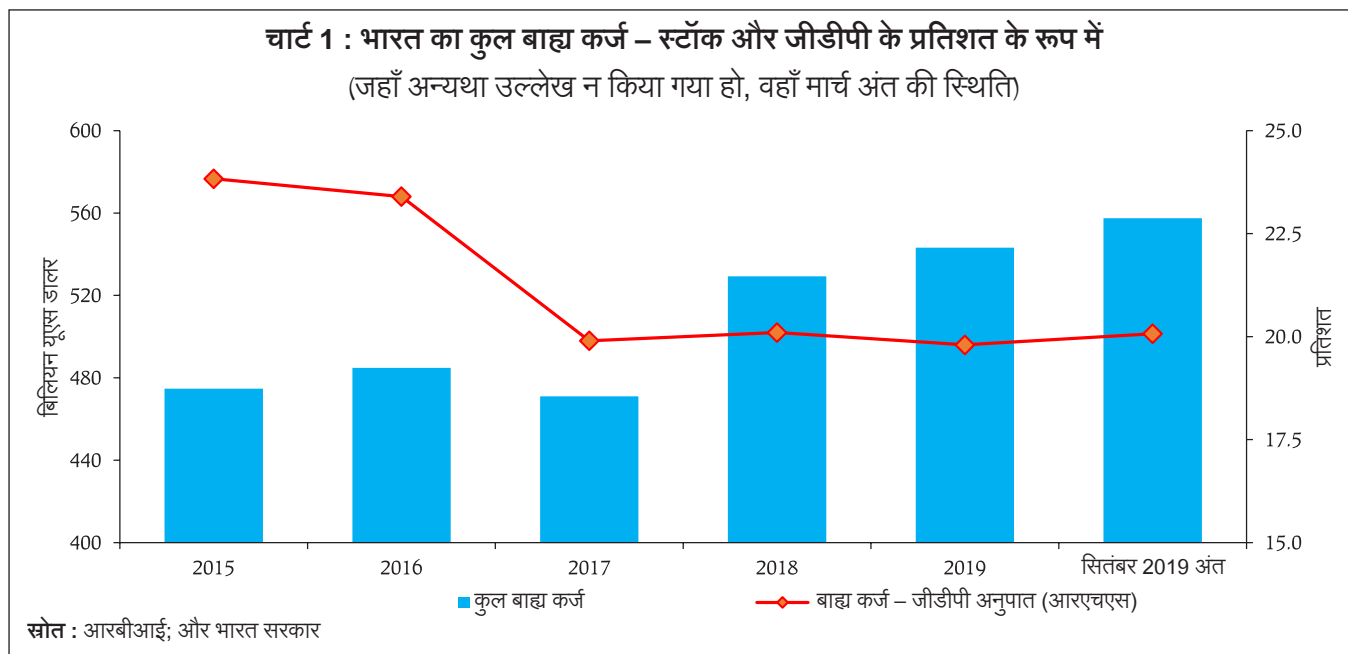
के अंत के 43.4 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2019 के अंत में 42.9 प्रतिशत रह गया। इसी तरह, उसी अवधि के दौरान आरक्षित निधि के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर) 57.0 प्रतिशत से घटकर 55.2 प्रतिशत हो गया, जिससे अल्पकालिक बाह्य दायित्वों के निर्वहन की क्षमता में सुधार का संकेत देता है।

मुद्रावार विचार करें तो पाते हैं कि सितंबर 2019 के अंत में अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित कर्ज भारत के बाह्य कर्ज का सबसे बड़ा घटक बना रहा जिसकी हिस्सेदारी 51.9 प्रतिशत थी, इसके बाद भारतीय रुपया (34.4 प्रतिशत), येन (5.2 प्रतिशत), एसडीआर (4.6 प्रतिशत) और यूरो (3.0 प्रतिशत) का स्थान रहा। उधारकर्ता क्षेत्र-वार वर्गीकरण से पता चलता है कि कुल कर्ज में गैर-वित्तीय निगमों के बकाया कर्ज का हिस्सा सर्वाधिक 41.7 प्रतिशत था, इसके बाद जमा स्वीकार करने वाले निगमों (केंद्रीय बैंक को छोड़कर) (29.1 प्रतिशत), सामान्य सरकार (19.2) प्रतिशत) और अन्य वित्तीय निगम (6.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। लिखत-वार वर्गीकरण दर्शाता है कि 34.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ ऋण बाह्य कर्ज के सबसे बड़े घटक थे, इसके बाद मुद्रा और जमा (24.4 प्रतिशत), व्यापार कर्ज और अग्रिम (19.1 प्रतिशत) तथा कर्ज प्रतिभूतियाँ (17.7 प्रतिशत) थीं।

III. भारत का बाह्य कर्ज : वहनीयता और जोखिम परिप्रेक्ष्य

बाह्य कर्ज की भावी स्थिति और कर्ज की वहनीयता के परीक्षण के नज़रिए से बाह्य कर्ज की वर्तमान स्थिति का आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाह्य कर्ज वहनीयता के विश्लेषण से देनदार देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जैसे कि क्या उस देश में चलनिधि की स्थिति और/अथवा वह देश चलनिधि की समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा, यह विश्लेषण कर्ज संबंधी जोखिमों की पहचान करने और संभावित संकटों को रोकने में की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ में, कर्ज की राशि में होने वाली वृद्धि, कर्ज-जीडीपी अनुपात में घट-बढ़, परिपक्वता संरचना, मुद्रा-वार और क्षेत्र-वार संघटन, कर्ज-चुकौती, और लिखत-वार वर्गीकरण महत्वपूर्ण पहलू हैं और इसलिए इनका अंतर-आवधिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाता है। इस भाग में, भारत के बाह्य कर्ज के इन पहलुओं का विश्लेषण मार्च 2015 के अंत से लेकर सितंबर 2019 के अंत तक की अवधि के लिए किया जाएगा।

¹ एसडीआर : स्पेशल ड्राइंग राइट्स (विशेष आहरण अधिकार)



बाह्य कर्ज वहनीयता के दृष्टिकोण से, किसी देश के बाह्य कर्ज की मात्रा में वृद्धि का मूल्यांकन आमतौर पर कर्ज दायित्वों के निर्वहन की क्षमता के संबंध में किया जाता है। इस संदर्भ में, बाह्य कर्ज-जीडीपी अनुपात एक मानक माप है जिसका उपयोग किसी देश की शोधन क्षमता और अपने उत्पादन को निर्यात में बदलने की क्षमता जानने के लिए किया जाता है ताकि वह अपनी कर्ज चुकौती क्षमता को बढ़ा सके² यह आवश्यक नहीं कि बाह्य कर्ज किसी देश के लिए हानिकारक हो बशर्ते उस देश की अर्थव्यवस्था का आकार भी समानुपाती रूप से बढ़े और/या निर्यात के पक्ष में घरेलू उत्पादन में एक वांछित संरचनात्मक परिवर्तन आए।

III.1 भारत का बाह्य कर्ज: स्टॉक और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

भारत के बाह्य कर्ज का स्टॉक वर्ष 2016-17 में गिरावट के बाद 2017-18 से बढ़ता गया है। बाह्य कर्ज का स्टॉक जो मार्च 2015 के अंत में 474.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ा और मार्च 2016 के अंत में 484.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था, वह मार्च 2017 के अंत में घटकर 471.0 बिलियन यूएस डॉलर हो गया (चार्ट 1)। इसके बाद, यह मार्च 2018 के अंत में 529.3

बिलियन अमेरिकी डॉलर और मार्च 2019 के अंत में 543.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। यह सितंबर 2019 के अंत में और बढ़कर 557.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वर्ष 2017-18 के बाद से हो रही वृद्धि मुख्य रूप से ईसीबी, अनिवासी जमा और अल्पकालिक व्यापार कर्ज द्वारा प्रेरित थी।

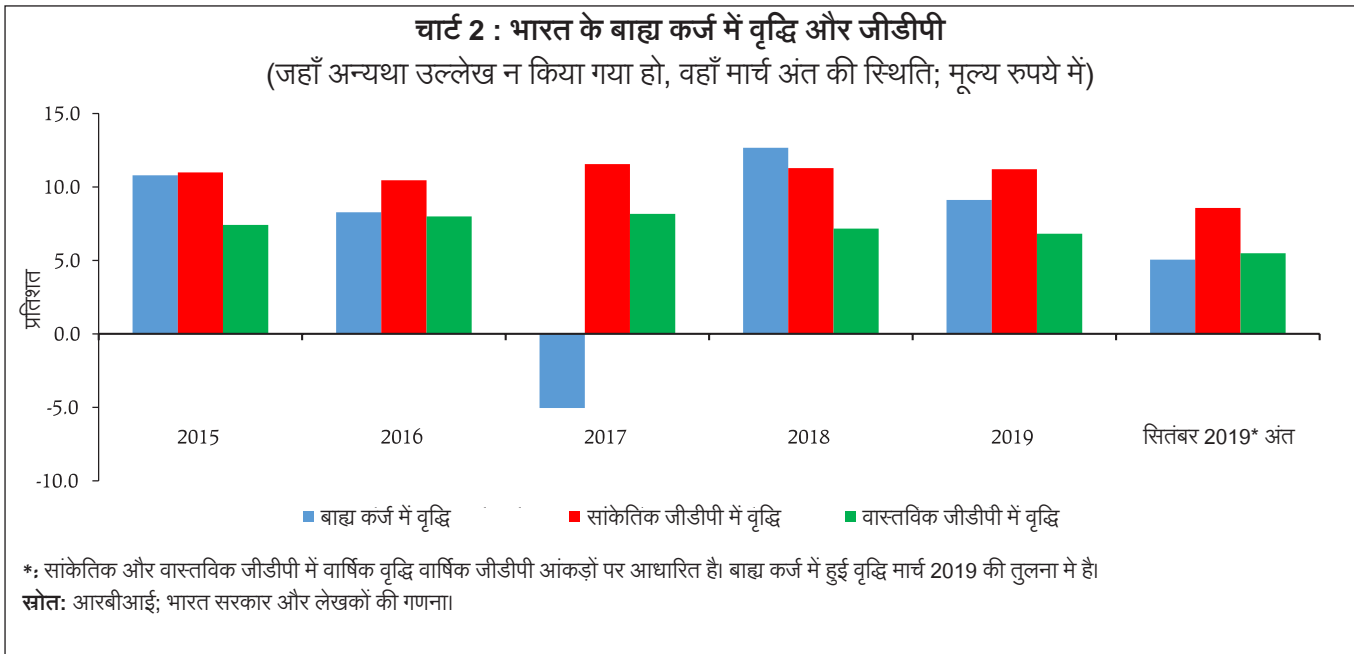
निरपेक्ष मान की दृष्टि से वृद्धि के बावजूद, भारत का बाह्य कर्ज स्टॉक 2017-18 के बाद से जीडीपी के लगभग 20 प्रतिशत के आस-पास ही रहा है³, जो क्रमशः 2014-15 के 23.4 प्रतिशत और 2015-16 के 23.8 प्रतिशत से कम है। बाह्य कर्ज-जीडीपी अनुपात में गिरावट और वहनीयता का कारण बाह्य कर्ज की तुलना में जीडीपी में रही उच्चतर वृद्धि को माना जाना चाहिए (चार्ट 2)।

III.2 कर्ज चुकौती अनुपात

स्टॉक-आधारित कर्ज भार संकेतकों के अलावा, बाह्य कर्ज वहनीयता और जोखिम का आकलन कर्ज प्रवाह-आधारित संकेतकों द्वारा किया जाता है। इन संकेतकों का उपयोग चलनिधि के दृष्टिकोण से बाह्य कर्ज वहनीयता का आकलन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, कर्ज चुकौती अनुपात प्रवाह आधारित संकेतक होते हैं। कर्ज चुकौती (यानी, परिशोधन और ब्याज भुगतान) किसी देश द्वारा अपने कर्ज की

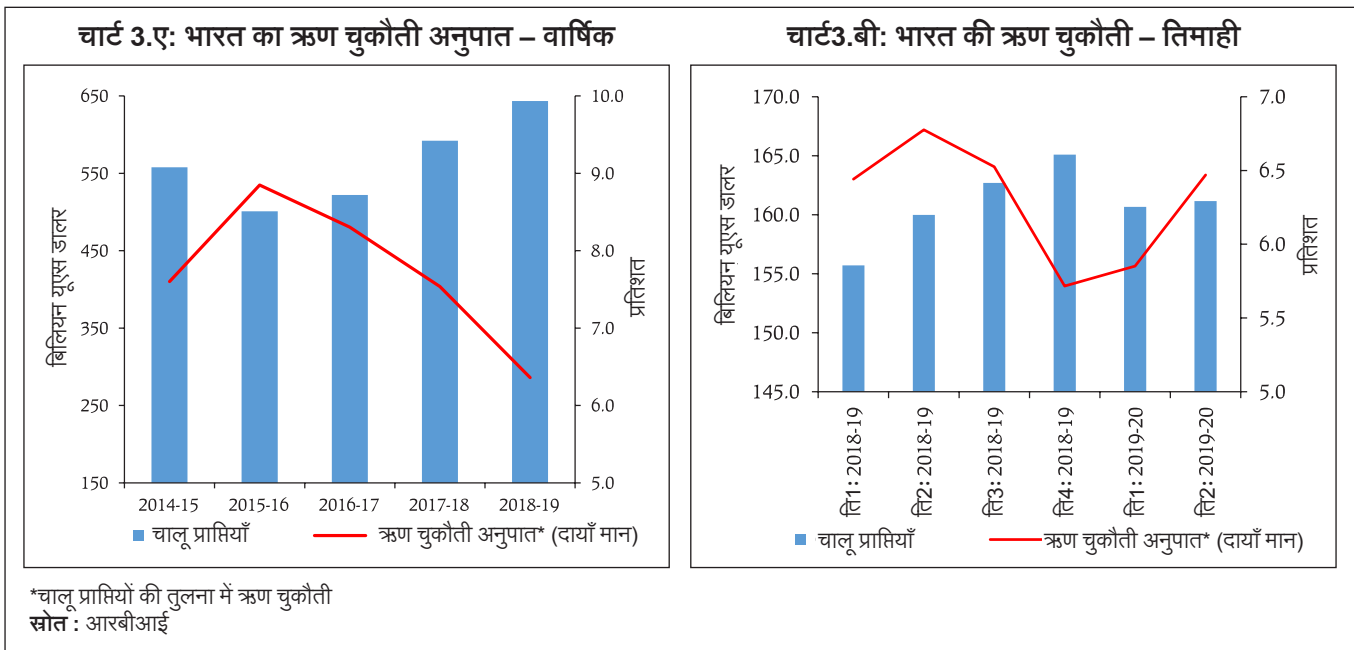
² किसी देश अर्थक्षम होने का आकलन अन्य स्टॉक आधारित संकेतकों के माध्यम से भी किया जाता है जैसे कि निर्यात अथवा चालू प्राप्तियों अथवा सरकारी राजस्व के प्रतिशत के रूप में। ऐसे देश जहाँ बाह्य कर्ज अधिकांशतः सरकारों द्वारा ही लिया जाता है, उनमें चुकौती क्षमता की माप के रूप में सरकारी राजस्व अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होता है।

³ बाह्य कर्ज-जीडीपी अनुपात रुपये के मूल्य पर आधारित होता है।



चुकौती हेतु आवश्यक संसाधनों और वित्तीय संसाधनों के समाप्त हो जाने के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इसलिए किसी देश की वर्ष-दर-वर्ष पुनर्भुगतान क्षमता की तुलना करने में बहुत उपयोगी होता है। उच्च और अस्थिर कर्ज चुकौती अनुपात कर्ज चुकाने में कठिनाई और संकट का स्पष्ट संकेत देते हैं, और जिससे कर्ज की अवहनीयता और जोखिम की संभावना बढ़ जाती है।

भारत की बात करें तो, कर्ज चुकौती आम तौर पर चालू प्राप्तियों की तुलना में देखी जाती है। वर्ष 2015-16 में भारत का कर्ज चुकौती अनुपात 8.8 प्रतिशत के स्तर पर था परंतु उसके बाद से इसमें धीरे-धीरे गिरावट देखी गई, जो मुख्य रूप से चालू प्राप्तियों में हुए सुधार को दर्शाता है (चार्ट 3. ए)। वर्ष 2018-19 के दौरान और 2019-20 की पहली छमाही में तिमाही कर्ज चुकौती अनुपात 7 प्रतिशत से कम बना रहा (चार्ट 3. बी)।

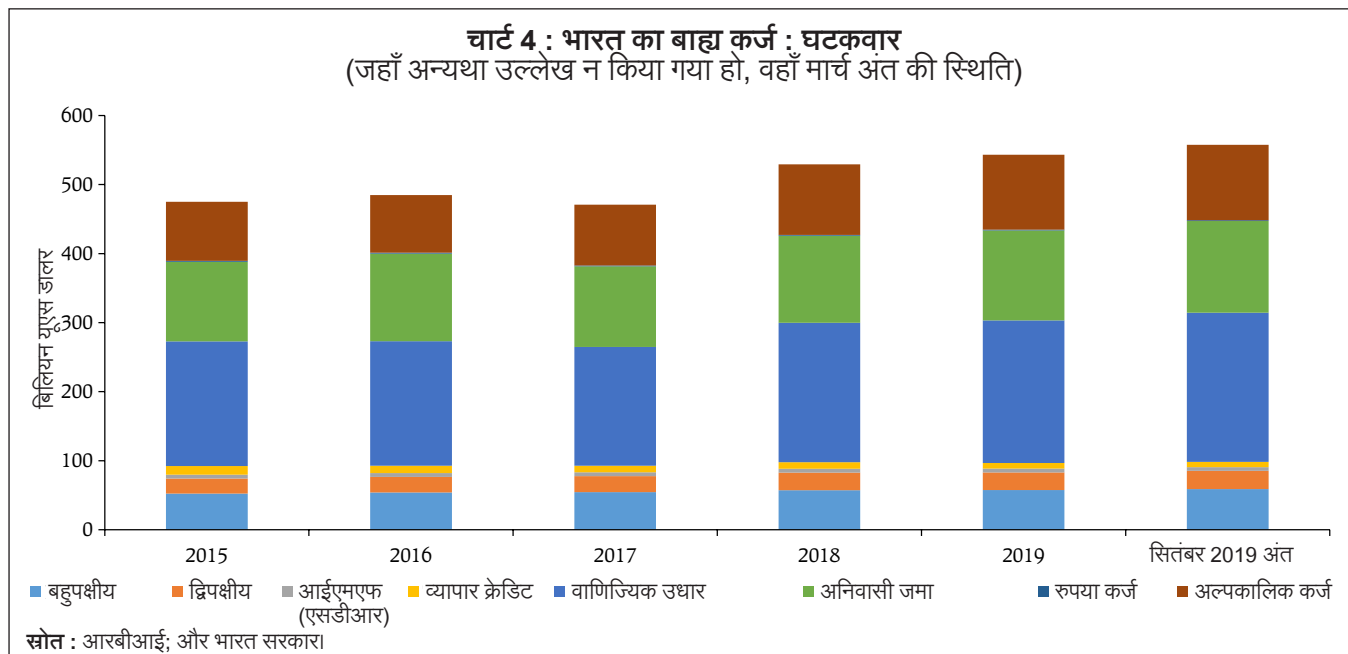


III.3 भारत का बाह्य कर्ज घटक-वार

मूल परिपक्वता के आधार पर, वाणिज्यिक उधार भारत के बाह्य कर्ज का सबसे बड़ा घटक बना रहा, इसके बाद अनिवासी जमा और अल्पकालिक कर्ज का स्थान था। सितंबर 2019 के अंत में, कुल कर्ज में वाणिज्यिक उधार की हिस्सेदारी 38.8 प्रतिशत थी, जबकि अनिवासी जमा और अल्पकालिक कर्ज कुल कर्ज का क्रमशः 23.8 प्रतिशत और 19.6 प्रतिशत (चार्ट 4)। वाणिज्यिक बैंकों के ऋण और एफपीआई निवेश वाणिज्यिक उधार के दो प्रमुख घटक रहे हैं, जिनकी संयुक्त हिस्सेदारी सितंबर 2019 के अंत में कुल बकाया वाणिज्यिक उधार का लगभग 76 प्रतिशत थी। यह ध्यान देने योग्य है कि वाणिज्यिक उधार में वाणिज्यिक बैंक ऋणों की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जबकि ईसीबी की हिस्सेदारी प्रतिभूत लिखतों (एफसीसीबी⁴ सहित) के माध्यम से बढ़ी है और बैंकों की विदेशी उधारियों में मार्च 2015 के अंत से सितंबर 2019 के अंत की अवधि में वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक उधारों में वाणिज्यिक बैंक ऋणों का हिस्सा जो मार्च 2015 के अंत में 56 प्रतिशत था, वह

सितंबर 2019 के अंत में यह 47 प्रतिशत पर आ गया। इसके विपरीत, प्रतिभूत लिखतों (एफसीसीबी सहित) के माध्यम से ईसीबी की हिस्सेदारी मार्च 2015 के अंत के 7 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 के अंत में 16 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में कर्ज लिखतों में एफपीआई निवेशों की हिस्सेदारी 28 से 35 फीसदी के बीच बनी रही।

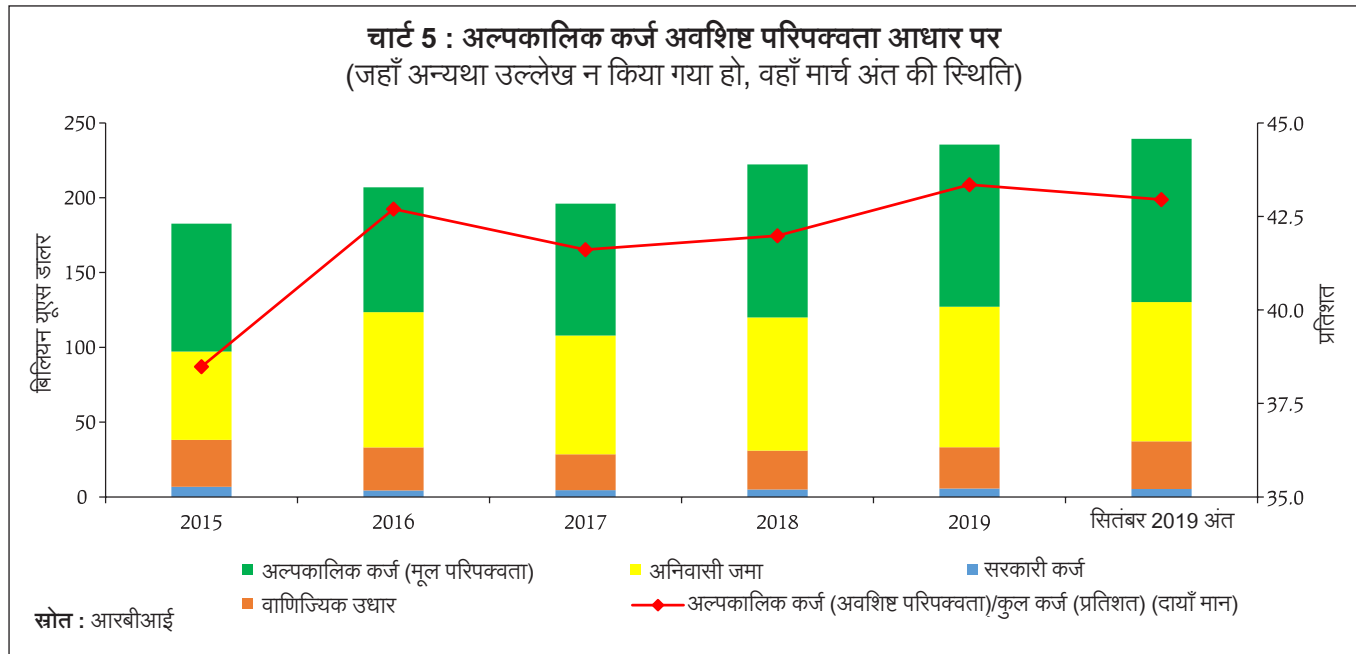
एनआर (ई)आरए जमाराशियाँ अनिवासी जमा का सबसे बड़ा घटक रही हैं, जिनके बाद एफसीएनआर (बी) और एनआरओ जमा का स्थान है⁵ मार्च 2015 के अंत से लेकर सितंबर 2019 के अंत तक कुल अनिवासी जमा में एनआर(ई)आरए जमा का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है और एफसीएनआर (बी) का हिस्सा घटा है। मार्च 2015 के अंत में कुल अनिवासी जमा में एनआर(ई)आरए जमा का हिस्सा 54 प्रतिशत था, सितंबर 2019 के अंत तक बढ़कर 70 प्रतिशत हो गया। इसके विपरीत, इसी अवधि में एफसीएनआर(बी) जमा का हिस्सा 37 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया। एफसीएनआर(बी) जमा में आयी कमी 2016-17 में जमा में कमी को दर्शाती है⁶



⁴ एफसीसीबी : विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड।

⁵ एनआरई (आर) ए : अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता; एफसीएनआर (बी) : विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक); एनआरओ : अनिवासी साधारण।

⁶ 24 बिलियन अमेरिकी डालर के एफसीएनआर (बी) जमा का मोचन सितंबर से दिसंबर 2016 के बीच किया गया। ये वो जमाराशियां थीं जिनकी उगाही सितंबर से नवंबर 2013 के बीच रिज़र्व बैंक की विशेष स्वैप विंडो के माध्यम से की गयी थी।



2014-15 के बाद से अल्पकालिक कर्ज में 95-98 प्रतिशत के साथ अल्पकालिक व्यापार क्रेडिट सबसे बड़ा घटक रहा है। 6 महीने से 1 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए व्यापार कर्ज अल्पकालिक व्यापार कर्ज का सबसे बड़ा घटक रहा है। उल्लेखनीय है कि अल्पकालिक व्यापार कर्ज में 6 महीने से 1 वर्ष के व्यापार क्रेडिट की हिस्सेदारी मार्च 2015 के अंत से सितंबर 2019 तक के बीच गिरावट आयी और यह 65 प्रतिशत से धीरे-धीरे 51 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई है। इससे मार्च 2018 से व्यापार क्रेडिट के लिए लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और लेटर्स ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) बंद होने के बाद अल्पकालिक व्यापार क्रेडिट फ्लो की सैपिंग का पता चलता है (अनुबंध I भी देखें)।

III.4 अवशिष्ट परिपक्वता आधारित अल्पकालिक कर्ज

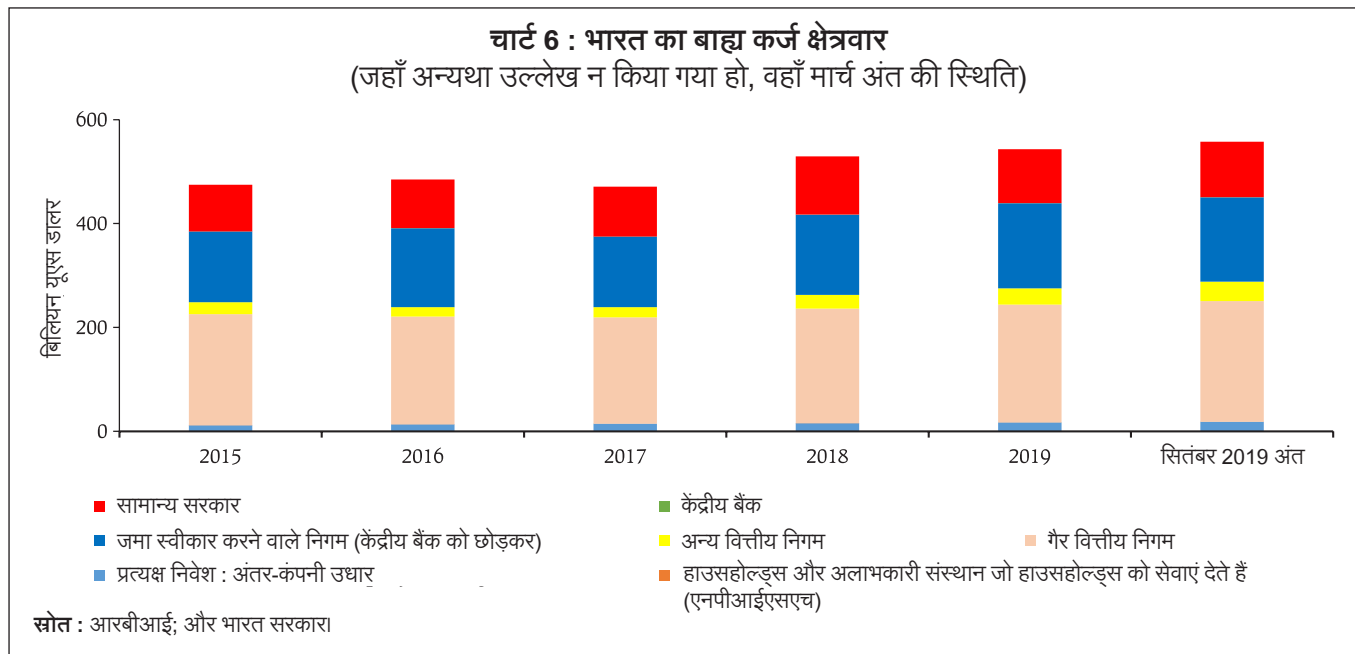
अवशिष्ट परिपक्वता आधारित अल्पकालिक कर्ज अगले एक वर्ष के भीतर भुगतान योग्य कर्ज दायित्वों (मूल परिपक्वता आधार पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) की एक माप है और यह चलनिधि जोखिमों का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है।

अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता आधारित) में मार्च 2015 के अंत में कुल बाह्य कर्ज के 38.5 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2019 के अंत में 42.9 प्रतिशत था। सितंबर 2019 के अंत में कुल अल्पकालिक कर्ज के उस हिस्से जिसकी चुकौती

अगले एक वर्ष में की जानी थी, का 46 प्रतिशत मूल रूप से एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए ही लिया गया था (चार्ट 5)। इसी अवधि के दौरान, अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर अनिवासी जमा राशियों का हिस्सा मार्च 2016 के अंत में सर्वाधिक लगभग 44 प्रतिशत था, जो सितंबर से नवंबर 2016 के दौरान बड़ी एफसीएनआर (बी) जमा के भुना लिए जाने को दर्शाता है। अवशिष्ट परिपक्वता आधारित अनिवासी जमा का हिस्सा सितंबर 2019 के अंत में लगभग 39 प्रतिशत था। अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर अल्पकालिक कर्ज में वाणिज्यिक उधार और सरकारी कर्ज का हिस्सा सितंबर 2019 के अंत में क्रमशः 13 प्रतिशत और 2 प्रतिशत था।

III.5 क्षेत्रवार संघटन

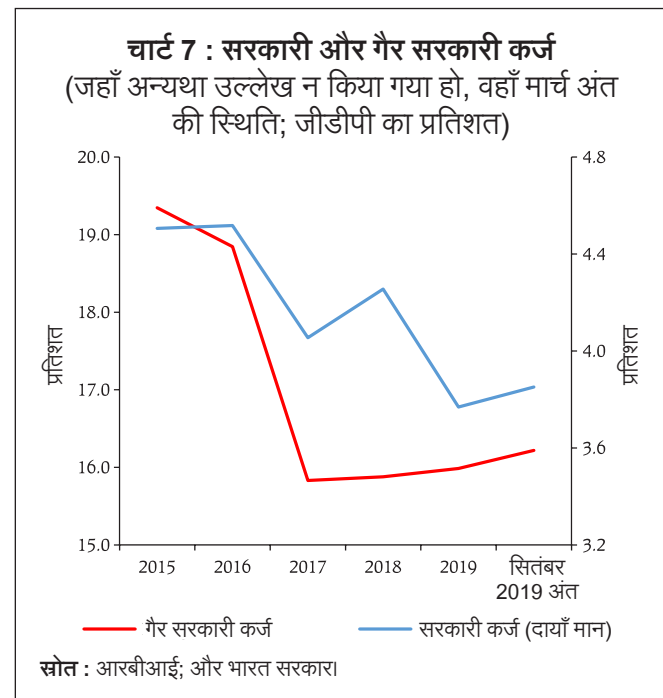
किसी देश की बाह्य कर्ज वहनीयता विभिन्न क्षेत्रों – सरकारी, बैंकिंग तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, और कॉर्पोरेट तथा घरेलू क्षेत्र - के तुलन-पत्रों और राजस्व-व्यय शेषों पर निर्भर करती है जो वास्तविक और आकस्मिक देनदारियों के माध्यम से जुड़े होते हैं (आईएमएफ, 2002)। जून 2019 के अंत से, रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की 2013 एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स (ईडीएस) गाइड को अपनाया है, जिससे भारत के बाह्य कर्ज पर और अधिक अलग-अलग डेटा मिलता है (अनुलग्नक II)।



कुल कर्ज में गैर-वित्तीय निगमों के बकाया कर्ज का हिस्सा सबसे अधिक रहा है, इसके बाद जमा-लेने वाले निगमों (केंद्रीय बैंक को छोड़कर), सामान्य सरकार, अन्य वित्तीय निगम और एफडीआई⁷ कंपनियों के बीच, अंतर-कंपनी उधारियाँ आती हैं। गैर-वित्तीय निगमों की हिस्सेदारी, जो मार्च 2015 के अंत में 45 प्रतिशत थी, सितंबर 2019 के अंत में घटकर 42 प्रतिशत रह गई (चार्ट 6)। इसी अवधि के दौरान जमा स्वीकार करने वाले निगमों (केंद्रीय बैंक को छोड़कर) और सामान्य सरकार का हिस्सा क्रमशः 29 प्रतिशत और 19 प्रतिशत पर रहा। अन्य वित्तीय निगमों के बकाया कर्ज की हिस्सेदारी मार्च 2015 के अंत के 5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 के अंत में 7 प्रतिशत हो गई। इसी प्रकार, इसी अवधि में एफडीआई कंपनियों के बीच इंटर-कंपनी उधार की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 3 प्रतिशत हो गई।

मार्च 2015 के अंत से लेकर सितंबर 2019 के अंत तक की अवधि में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी और गैर-सरकारी कर्ज दोनों में गिरावट आयी। सरकारी कर्ज, जो मार्च 2015 के अंत में जीडीपी का 4.5 प्रतिशत था, वह घटकर सितंबर 2019

तक 3.9 प्रतिशत रह गया (चार्ट 7)। इसी प्रकार, उसी अवधि में गैर-सरकारी कर्ज 19.3 प्रतिशत से गिरकर 16.2 प्रतिशत हो गया।



⁷ एफडीआई : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।

III.6. मुद्रा संरचना

विनिमय दरों में परिवर्तन उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाहों और तुलन पत्रों को प्रभावित करता है – विनिमय दरों में भारी उतार-चढ़ाव से उनके नकदी प्रवाहों और तुलन पत्रों पर गहरा असर पड़ सकता है। अतः, कर्ज संवहनीयता और संवेदनशीलता के नजरिए से बाह्य कर्ज की मुद्रा संरचना का आकलन महत्वपूर्ण है।

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के कर्ज भारत के बाह्य कर्ज के सबसे बड़े घटक रहे हैं। फिर भी, मार्च 2015 के अंत और सितंबर 2019 के अंत के बीच अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के कर्ज की हिस्सेदारी घटी जबकि भारतीय रुपया मूल्यवर्ग के कर्ज की हिस्सेदारी बड़ी। अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के कर्ज की हिस्सेदारी मार्च 2015 के अंत में 58 प्रतिशत थी, जो सितंबर 2019 के अंत में घटकर 52 प्रतिशत रह गई (चार्ट 8)। इसके विपरीत, उक्त अवधि में भारतीय रुपया मूल्यवर्ग के कर्ज की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गई।

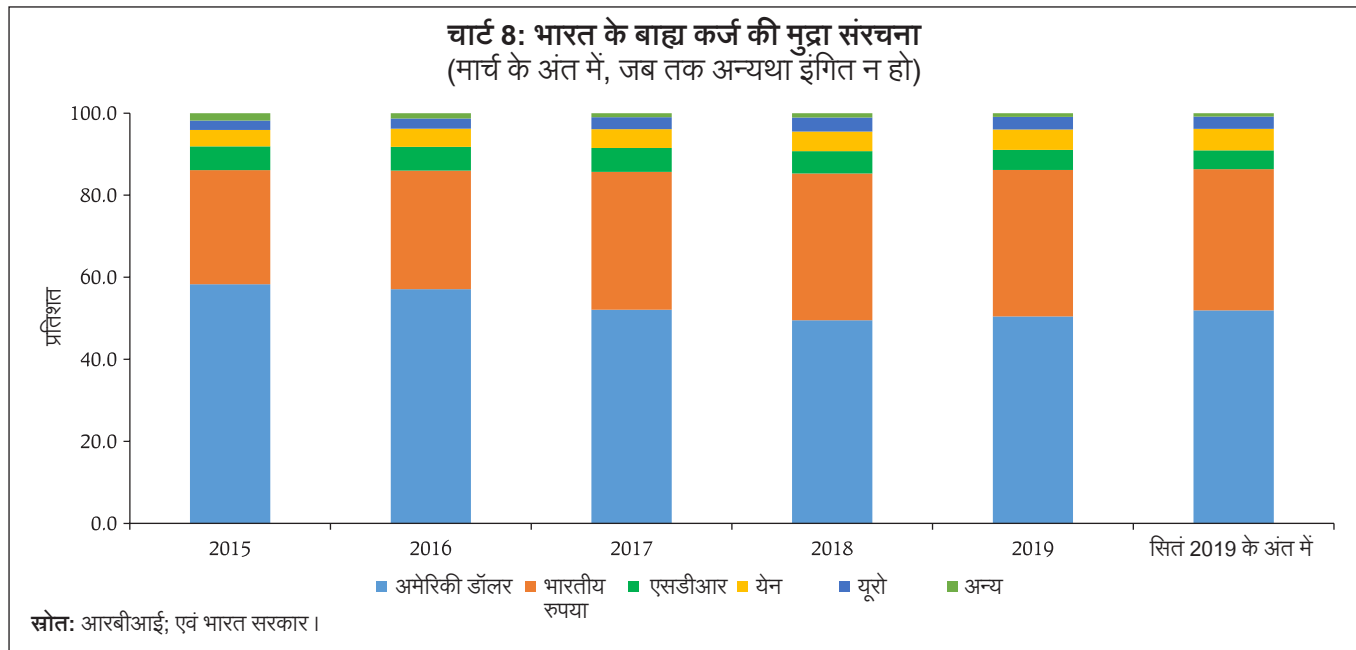
III.7. लिखत-वार वर्गीकरण

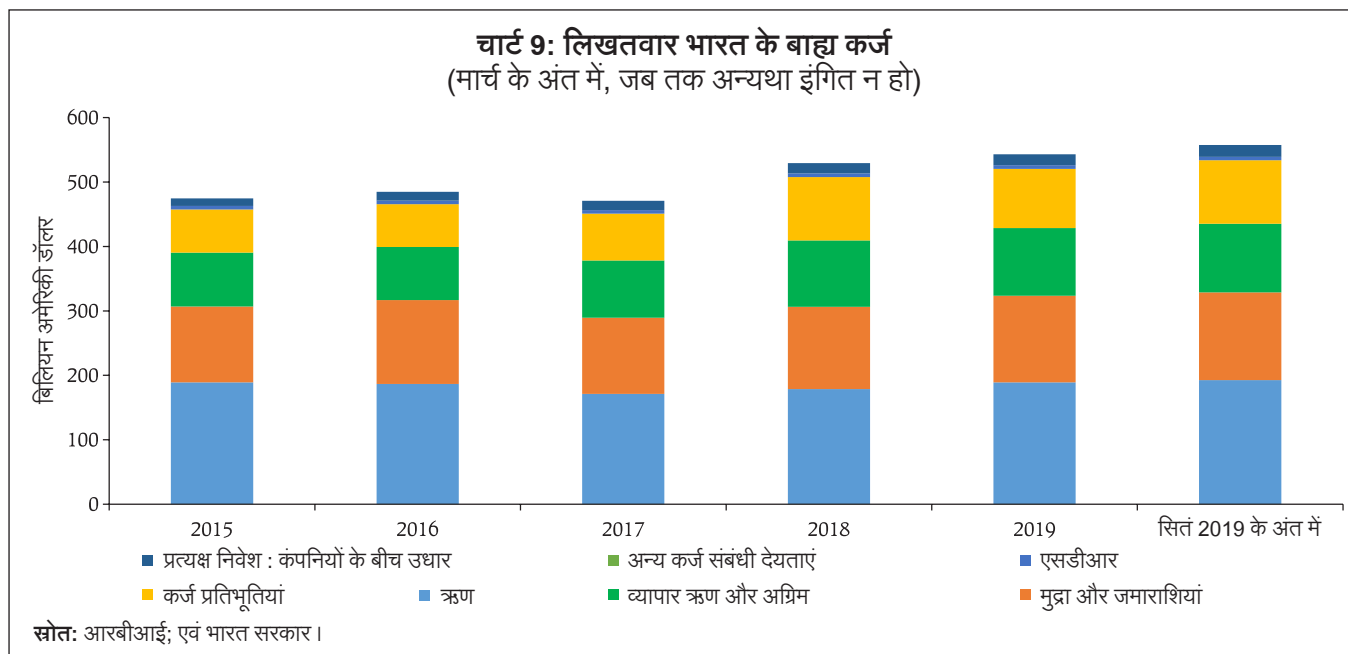
ऋण, भारत के बाह्य कर्ज का सबसे बड़ा घटक रहा है, और उसके बाद क्रमशः मुद्रा और जमाराशियां, व्यापार ऋण एवं अग्रिम, तथा कर्ज प्रतिभूतियां आती हैं। इन प्रमुख लिखतों में से,

मार्च 2015 के अंत और सितंबर 2019 के अंत के बीच ऋणों की हिस्सेदारी में गिरावट आई जबकि कर्ज प्रतिभूतियों में वृद्धि हुई। मार्च 2015 के अंत में कुल कर्ज में ऋण का हिस्सा 40 प्रतिशत था, जो सितंबर 2019 के अंत में घटकर 35 प्रतिशत रह गया (चार्ट 9)। इसके विपरीत, मार्च 2015 के अंत में कर्ज प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 के अंत में 18 प्रतिशत हो गई। उक्त अवधि में मुद्रा और जमाराशियों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 24 प्रतिशत रह गई। मार्च 2015 के अंत में व्यापार ऋण और अग्रिमों की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर सितंबर 2019 के अंत में 19 प्रतिशत हो गई।

IV. भारत के बाह्य कर्ज पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का मूल्यांकन प्रभाव

अमेरिकी डॉलर को अधिकांश देशों में बाह्य कर्ज के भंडार का मूल्यांकन करने के लिए *मूल्यमान (न्यूमरेर)* मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए, अन्य कारणों के अलावा, कर्ज को जिन मुद्राओं में मूल्यवर्गीकृत किया गया है, उन मुद्राओं में उतार-चढ़ाव से बाह्य कर्ज के स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है (बॉक्स I)। कर्ज को जिन मुद्राओं में मूल्यवर्गीकृत किया गया है उन मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के गिरने (मजबूत होने) से बाह्य कर्ज का मूल्य अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में बढ़ता (घटता) है। भारत के





मामले में, मूल्यांकन प्रभाव प्रमुख रूप से बड़ी मुद्राओं, जैसे भारतीय रुपया, येन, यूरो एवं एसडीआर में उतार-चढ़ाव से प्रभावित है।

इन मुद्राओं में, हाल के वर्षों में मूल्यांकन प्रभाव के संबंध में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के उतार-चढ़ाव का योगदान सबसे अधिक रहा। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के

बॉक्स I: भारत के बाह्य कर्ज पर अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

प्रमुख मुद्राओं (अर्थात, भारतीय रुपया, येन, यूरो और एसडीआर) की तुलना में अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव प्रधान रूप से अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मापे जाने वाले भारत के बाह्य कर्ज के मूल्यांकन को प्रभावित करता है। अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि (मूल्यहास) से कर्ज का मूल्य घटता (बढ़ता) है। आईएमएफ ने बाह्य खाते की स्थिति को लेकर मूल्यांकन परिवर्तन की भूमिका पर जोर दिया है (आईएमएफ, 2009 देखें)। तिल्ली (2003) ने अमेरिका के बाह्य कर्ज पर विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव की जांच की है। इस बॉक्स में प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव का अमेरिकी डॉलर में भारत के बाह्य कर्ज के मूल्य पर प्रभाव की प्रयोगसिद्ध जांच की गई है।

प्रयोगसिद्ध अध्ययन में 2000-01 से 2018-19 की अवधि के लिए त्रैमासिक डेटा का उपयोग किया गया है। इस अवधि के दौरान, कुल कर्ज में अमेरिकी डॉलर और अन्य प्रमुख चार मुद्राओं में मूल्यवर्गीकृत कर्ज की औसत हिस्सेदारी क्रमशः 53 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के करीब थी। प्रमुख गैर-अमेरिकी डॉलर मुद्राओं में मूल्यवर्गीकृत कर्ज की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए, इन मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव का कर्ज के मूल्यांकन पर भारी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

भारत के बाह्य कर्ज के भंडार पर प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, चार प्रमुख मुद्रा समूह के संयुक्त सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर) सूचकांकों की गणना की गई। इन सूचकांकों की गणना के लिए अमेरिकी डॉलर की तुलना में प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों को भारत के बाह्य कर्ज में उनके संबंधित हिस्सों के अनुसार भारित किया गया है। इन सूचकांकों के लिए वर्ष 2000 को आधार वर्ष के रूप में चुना गया। नीर सूचकांक में वृद्धि (गिरावट) का तात्पर्य इन प्रमुख मुद्रा समूह की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि (मूल्यहास) से है।

इस अध्ययन में सांख्यिकीय आकलन पर विचार किया गया है जिसमें बाह्य कर्ज का भंडार (अमेरिकी डॉलर में) अश्रित चर है और अमेरिकी डॉलर का नीर सूचकांक तथा सीएडी (अमेरिकी डॉलर में) व्याख्यात्मक चर हैं। सीएडी का उपयोग एक नियंत्रण चर के रूप में किया जाता है क्योंकि कुछ परिस्थितियों में उसके वित्तपोषण के लिए ज्यादा उधार लेने की नौबत आ सकती है। सभी चरों को लॉगरिदमिक रूप में लिया गया है।

यूनिट रूट टेस्ट के नतीजे पुष्टि करते हैं कि ये चर I(1) हैं। जोहनसेन कोइंटीग्रेशन टेस्ट बताते हैं कि ये चर कोइंटीग्रेटड रहें। तदनुसार, इस

(क्रमशः...)

मॉडल के लिए वेक्टर एरर करेक्शन (वीईसी) अनुमान लगाए गए नतीजों को निम्नलिखित सारणी में पेश किया गया है :

सारणी 1.1: भारत के बाह्य कर्ज पर अमेरिकी डॉलर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव – वीईसी अनुमान⁹

आश्रित चर : एलडी

ईसीटी	कोइंटिग्रेटिंग इक्वेशन			आर ²	अडजसेंट आर ²
	एलनीर	एलसीएडी	सी		
-0.07*	-2.17*	-0.08	-14.03	0.86	0.83

एलडी: लॉग (बाह्य कर्ज आघात); एलनीर: लॉग (नीर); एलसीएडी: लॉग (सीएडी); ईसीटी: एरर करेक्शन टर्म; और सी: कान्सटन्ट।

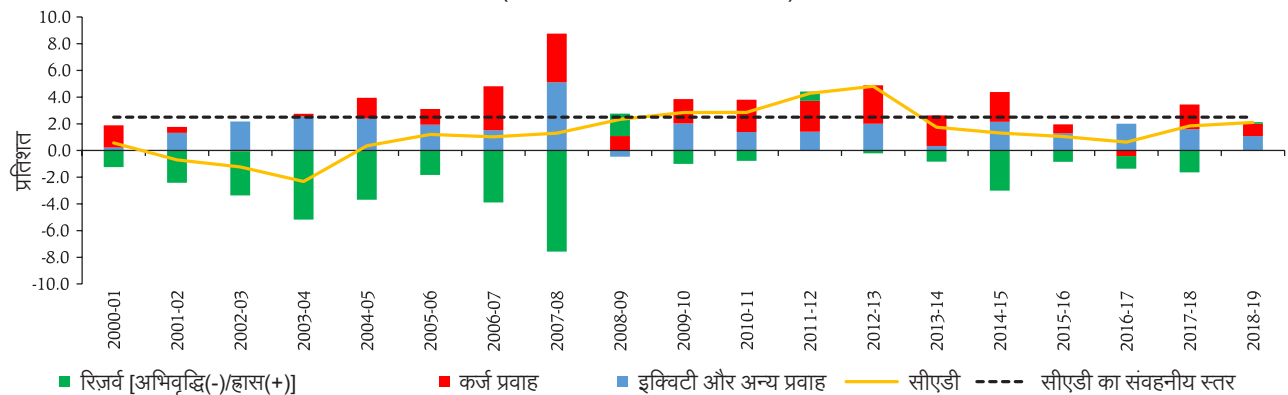
*1 प्रतिशत स्तर पर काफी।

स्रोत: लेखकों के अनुमान।

नतीजे पुष्टि करते हैं कि प्रमुख मुद्रा समूह (भारतीय रुपया सहित) की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि से अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में बाह्य कर्ज के भंडार में भारी कमी आती है। अमेरिकी डॉलर में एक प्रतिशत की मूल्यवृद्धि का संबंध बाह्य कर्ज के भंडार में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट से है। तथापि, सीएडी भारत के बाह्य कर्ज का प्रमुख वाहक बनकर नहीं उभरा।

भारत के बाह्य कर्ज पर सीएडी के मामूली प्रभाव का संभावित कारण भारत के सीएडी के वित्तपोषण का स्वरूप है। भारत को बड़ी मात्रा में इक्विटी और अन्य प्रवाह (जैसे, प्रत्यक्ष विदेशी एवं पोर्टफोलियो इक्विटी निवेश) प्राप्त होते हैं, जिससे भारत के सीएडी का भरपूर वित्तपोषण होता है। सैम्पल अवधि के दौरान पूंजी प्रवाहों में इन प्रवाहों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था (शुद्ध आधार पर)। इक्विटी और अन्य प्रवाहों के अतिरिक्त, रिजर्व के जरिए भी सीएडी का वित्तपोषण किया गया, जब निवल पूंजी प्रवाह आवश्यकता से कम पड़ गए थे। उदाहरण के लिए, 2008-09, 2011-12 और 2018-19 के दौरान रिजर्व के जरिए सीएडी का आंशिक रूप से वित्तपोषण किया गया (चार्ट 1.1)। उल्लेखनीय है कि, 2008-09 के दौरान, 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सीएडी के वित्तपोषण के लिए 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पूंजी प्रवाह (शुद्ध संदर्भों में) अपर्याप्त थे, एवं, इसलिए, रिजर्व में 20.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध हास हुआ। इसी प्रकार, जीडीपी की तुलना में 4.3 प्रतिशत के सीएडी, जो भारत के सीएडी के वहनीय स्तर से अधिक था, का आंशिक रूप से वित्तपोषण पूंजी प्रवाहों के जरिए किया गया, परिणामस्वरूप, 2011-12 के दौरान रिजर्व में 12.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हास हुआ।

चार्ट 1.1: सीएडी और उसका वित्तपोषण
(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

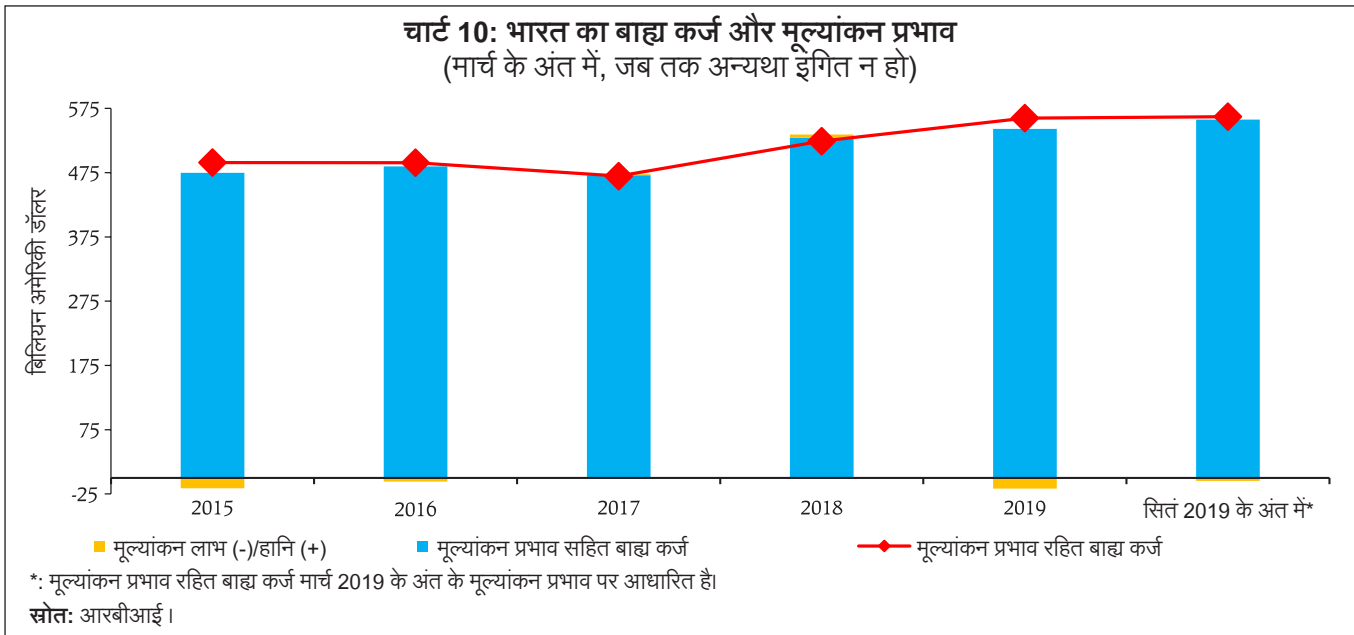


स्रोत: आरबीआई; आईएमएफ (2018); और लेखकों की गणनाएं।

मद्देनज़र, मार्च 2015, 2016 एवं 2019 के अंत में और सितंबर 2019 के अंत में भारत के बाह्य कर्ज को मूल्यांकन लाभ हुआ, जब मूल्यांकन प्रभाव सहित बाह्य कर्ज मूल्यांकन प्रभाव सिवाय बाह्य कर्ज की अपेक्षा कम था (चार्ट 10)। इसके विपरीत, मार्च 2017 और 2018 के अंत में मूल्यांकन हानि दर्ज की गई। मार्च 2015 के अंत से सितंबर 2019 के अंत तक की अवधि के दौरान मार्च 2019 के अंत में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर

का मूल्यांकन लाभ हुआ जो सर्वाधिक था, और उसके बाद मार्च 2015 एवं 2016 के अंत में क्रमशः 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर आते हैं (चार्ट 11.ए)। ये मूल्यांकन लाभ प्रमुख रूप से भारतीय रुपये की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने की वजह से भारतीय रुपये में मूल्यवर्गीकृत कर्ज में मूल्यांकन संबंधी परिवर्तन होने की बदौलत थे (चार्ट 11.बी)।

⁹ वीईसी मॉडल अवशिष्टों की सामान्यता स्थितियों को संतुष्ट करता है, कोई स्वसहसंबंध और होमोसेडास्टिसिटी नहीं है।

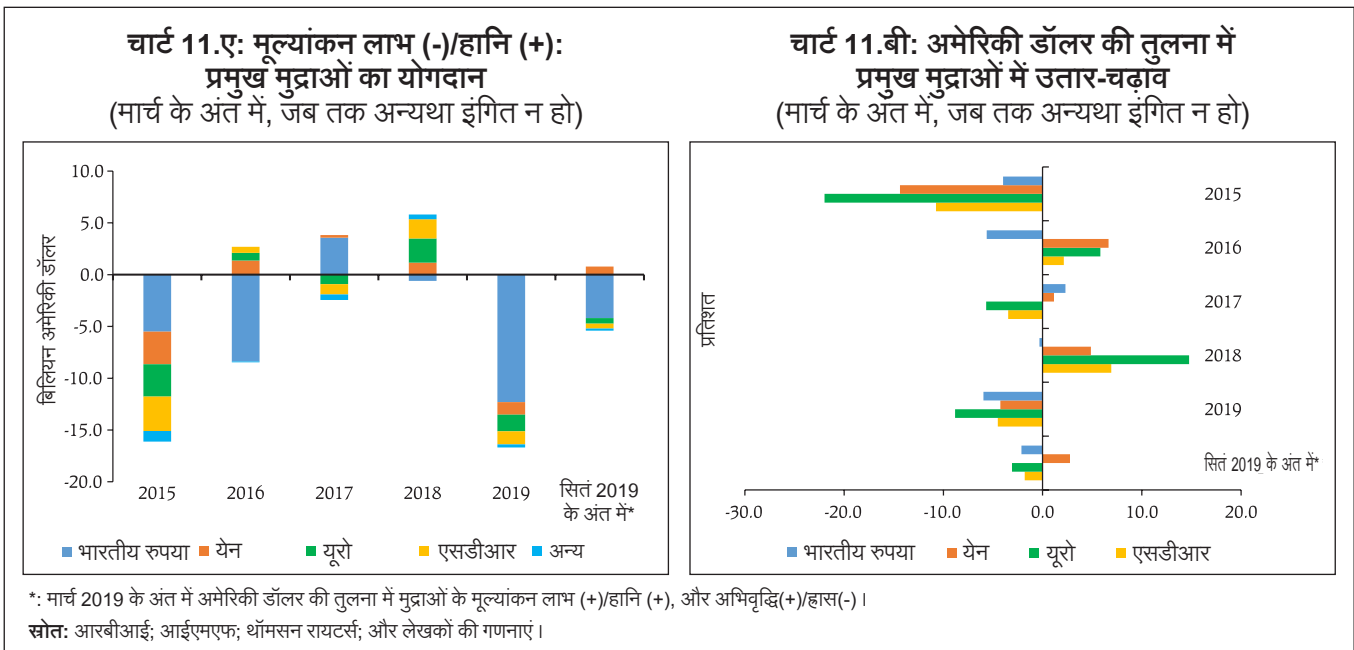


V. रिज़र्व की पर्याप्तता और भारत की बाह्य संवेदनशीलता

कर्ज संबंधित संकेतकों के आधार पर देश की बाह्य संवेदनशीलता का आकलन करने के अलावा, रिज़र्व पर्याप्तता उपायों के आधार पर संवेदनशीलता का आकलन किया जाता है। कई कारणों से रिज़र्व रखा जाता है। इन कारणों में से प्रमुख है बाह्य आघात और संकट से बचने के लिए स्व-बीमा और चलनिधि बफर सुनिश्चित करना। इसके अलावा, रिज़र्व के

संचय से बाह्य देयताओं को समय पर अदा करने तथा देश की मुद्रा के मूल्य को सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता को लेकर प्राधिकारियों में विश्वास बढ़ता है। रिज़र्व पर्याप्तता संकेतक घटना एवं संकट की गहराई के उपयोगी पूर्व सूचक हैं (आईएमएफ, 2000)।

1991 के भुगतान संतुलन संकट के परिणामस्वरूप भारत की विवेकपूर्ण बाह्य क्षेत्र प्रबंधन नीतियों ने सीएडी के



साथ-साथ बाह्य कर्ज संबंधी देयताओं के वित्तपोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त रिज़र्व रखना सुनिश्चित किया है।

V.1. बाह्य कर्ज हेतु रिज़र्व कवर

भारत का रिज़र्व 2014-15 से बढ़ा है, सिवाय 2018-19 के, जब सीएडी के वित्तपोषण के चलते उसमें हास हुआ था (चार्ट 12.ए)। इतना कुछ होते हुए भी, रिज़र्व ने बाह्य कर्ज संबंधी देयताओं (अल्पावधि और कुल कर्ज, दोनों) के लिए पर्याप्त गुंजाइश उपलब्ध कराई है। मार्च 2015 के अंत में रिज़र्व ने कुल बाह्य कर्ज के 72 प्रतिशत का कवर प्रदान किया, जो मार्च 2018 के अंत में बढ़कर 80.2 प्रतिशत हो गया। फिर भी, उसके बाद, मार्च 2019 के अंत में कुल बाह्य कर्ज का रिज़र्व कवर घटकर 76 प्रतिशत रह गया, जो रिज़र्व में हास को दर्शाता है। तथापि, वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में रिज़र्व में फिर से वृद्धि के चलते सितंबर 2019 के अंत में कुल बाह्य कर्ज का रिज़र्व कवर बढ़कर 77.8 प्रतिशत हो गया।

ऋणी देश के चलनिधि दबाव और बाह्य संवेदनशीलता के आकलन में उपयोगी होने वाला एक और संकेतक है अल्पावधि कर्ज का रिज़र्व कवर, विशेष रूप से अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर। घटना और बाह्य संकट की गहराई अधिक होने से अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर) का रिज़र्व कवर कम होता

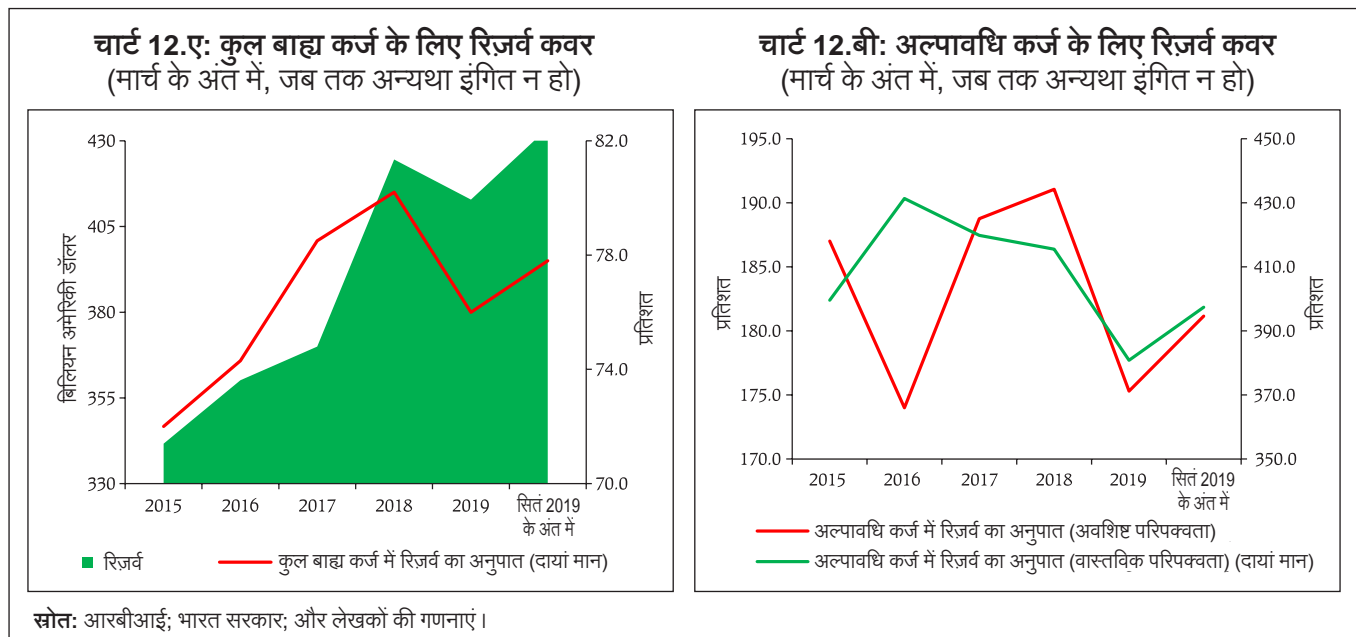
है (आईएमएफ, 2000)। “ग्रीनस्पैन-गाइडोटी” नियम अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर) के कम से कम 100 प्रतिशत रिज़र्व कवर की सिफ़ारिश करता है; और ईएमई में बाह्य आघातों के विरुद्ध रिज़र्व की पर्याप्तता एवं चलनिधि बफ़र के उपाय के रूप में इस नियम का व्यापक रूप से पालन किया जाता है। सितंबर 2019 के अंत में रिज़र्व ने भारत के अल्पावधि कर्ज – जो अल्पावधि कर्ज के लिए अवशिष्ट एवं वास्तविक परिपक्वता आधार पर क्रमशः 181.2 प्रतिशत और 397.4 प्रतिशत था, के लिए भरपूर कवर प्रदान किया (चार्ट 12.बी)।

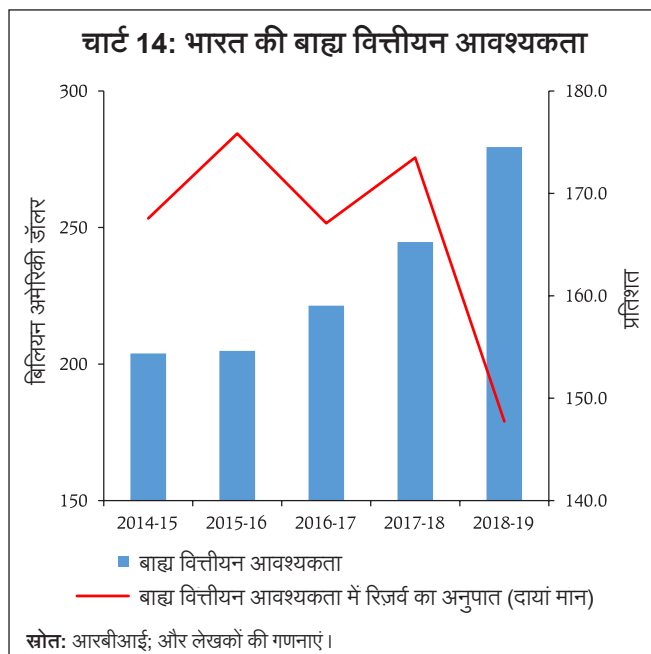
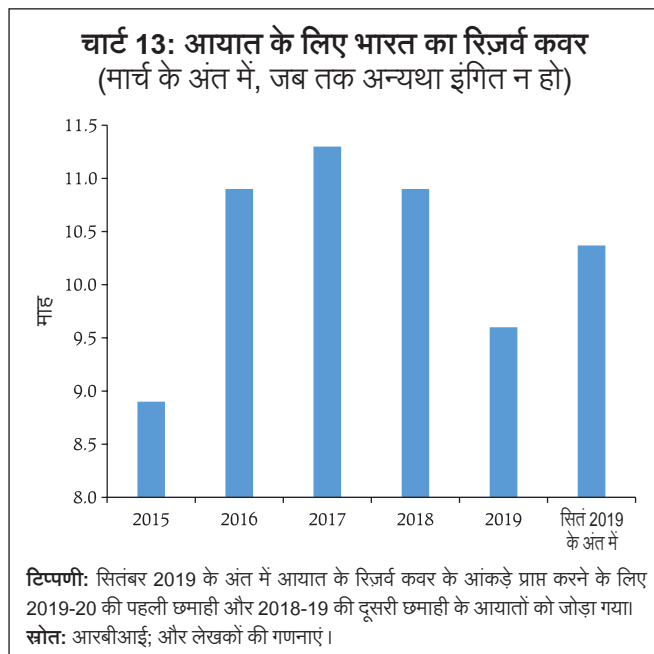
V.2. आयात हेतु रिज़र्व कवर

आयात हेतु रिज़र्व कवर देश की बाह्य संवेदनशीलता का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण बाह्य चलनिधि संकेतक है। इससे जानकारी मिलती है कि कोई देश कितने महीने तक अपने आयात का वित्तपोषण कर सकता है जब सभी बाह्य अंतर्वाह बंद हो जाए। वर्ष 2015-16 के बाद से भारत के रिज़र्व ने 9.5 महीने से अधिक के आयात के लिए कवर प्रदान किया था, जो तीन महीने के आयात के रिज़र्व कवर के पारंपरिक नियम से अधिक था (चार्ट 13)।

V.3. बाह्य वित्तीय आवश्यकता हेतु रिज़र्व कवर

उपर्युक्त पारंपरिक संकेतकों के अलावा, बाह्य वित्तीय आवश्यकता एक और संकेतक है जो ऋणी देश के चलनिधि





दबाव एवं संवेदनशीलता के आकलन में उपयोगी है (बॉक्स II)। यह देश के सीएडी और एक वर्ष में परिपक्व होने वाली कर्ज संबंधी देयताओं (अर्थात्, अवशिष्ट परिपक्वता के जरिए अल्पावधि कर्ज) के वित्तपोषण की आवश्यकता का माप है। इस उपाय से भी, रिजर्व कवर 2014-15 से 2018-19 के दौरान 145 प्रतिशत पर काफी ऊंचे स्तर पर रहा (चार्ट 14)।

VI. अंतर-देशीय विश्लेषण

2018 के अंत की स्थिति के अनुसार बाह्य कर्ज के भंडार के संदर्भ में, भारत का सर्वाधिक ऋणग्रस्त देशों में चीन और ब्राजील के बाद तीसरा स्थान आता है। भारत का बाह्य कर्ज 521.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि चीन और ब्राजील का क्रमशः 1,965.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर एवं 665.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तथापि, जीडीपी की तुलना में बाह्य कर्ज के

बॉक्स II: भारत हेतु बाह्य संवेदनशीलता सूचकांक

अर्थव्यवस्था की बाह्य संवेदनशीलता का आकलन करने के लिए रिजर्व, बाह्य देयताएं, कर्ज-इक्विटी अनुपात, एवं कर्ज की परिपक्वता के स्वरूप जैसे भिन्न-भिन्न संकेतकों का उपयोग किया गया। इन संकेतकों में उतार-चढ़ाव बाह्य संवेदनशीलता के स्तर में वृद्धि या गिरावट के बारे में जानकारी देता है, फिर भी, इन संकेतकों में उतार-चढ़ाव में भिन्नता होने की वजह से किसी निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता के स्तर का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, बदतर बाह्य कर्ज संबंधी संकेतक बढ़ती संवेदनशीलता की ओर संकेत करते हैं, नतीजतन आयात के रिजर्व कवर में सुधार निम्न संवेदनशीलता दर्शाता है। इसलिए, यह उपयोगी है कि किसी निश्चित समय पर अर्थव्यवस्था की संवेदनशीलता के स्तर का आकलन करने के लिए प्रमुख समष्टिआर्थिक संकेतकों का उपयोग करने के जरिए बाह्य संवेदनशीलता के संबंध में संयुक्त सूचकांक बनाया जाए।

इस बॉक्स में भारत के लिए बाह्य संवेदनशीलता तैयार करने की कार्यप्रणाली प्रस्तुत की गई है। कैटो और मीलेसी-फेर्डी (2013) का अनुसरण करते हुए, संयुक्त सूचकांक की गणना करने के लिए प्रमुख समष्टिआर्थिक संकेतकों का पैनल प्रोबिट मॉडल प्रयोग में लाया गया। प्रोबिट मॉडल संकट की संभावना को लेकर प्रत्येक संवेदनशीलता संकेतकों के संगत प्रभाव का अनुमान लगाता है। पैनल में भारत सहित उसके अन्य ईएमई समकक्ष, जैसे, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मलेशिया, मेक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, एवं तुर्की शामिल हैं, जिन्होंने सैम्पल अवधि 1991 से 2018 में भिन्न-भिन्न समय पर संकट का सामना किया था।

प्रोबिट मॉडल का आश्रित चर बाइनरी है जो संकट होने की संभावना के लिए 1 वैल्यू लेता है, अन्यथा शून्य। इस मॉडल में छह प्रमुख समष्टिआर्थिक चरों को व्याख्यात्मक चरों के रूप में माना जाता है

(जारी...)

जिसे बाह्य संवेदनशीलता एवं संकट के नजरिए से महत्वपूर्ण माना गया है (उदाहरण के लिए, देखें, कैटो और मीलेसी-फेर्डी (2013), गोयल (2012))। ये चर इस प्रकार हैं, जीडीपी में निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थित (आईआईपी) का अनुपात, रिज़र्व में बाह्य वित्तीय आवश्यकता का अनुपात, कुल बाह्य कर्ज में अल्पावधि कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) का हिस्सा, देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के अनुपात के रूप में मापा जाने वाला वृद्धि अंतर, जिसे संयुक्त राज्य, वैश्विक चलनिधि, एवं सरकारी प्रभावशीलता संकेतक के सैम्पल में शामिल किया गया है। अनुभवजन्य आकलन से पहले, आइसोप्रिनी और बोर्डो (2002) के बाद, संकट वाले वर्षों का पता लगाने के लिए विनिमय दर, रिज़र्व और अल्पावधि ब्याज दर में परिवर्तन के आधार पर विनिमय बाजार के दबाव की गणना की गई। विनिमय बाजार के दबाव की गणना ने पैनल के लिए 25 संकट वर्षों का पता लगाया।

अनुभवजन्य नतीजे बताते हैं कि जीडीपी में निवल अंतरराष्ट्रीय देयताओं का अनुपात तथा कुल बाह्य कर्ज में अल्पावधि कर्ज का हिस्सा बढ़ने से संकट की संभाव्यता काफी बढ़ती है, जबकि वृद्धि की संभावनाएं बेहतर होने से संकट की संभाव्यता काफी हद तक घट जाती है (सारणी II.1)। सरकार की प्रभावशीलता से संकट की संभाव्यता काफी कम होती है। रिज़र्व की तुलना में बाह्य वित्तीय आवश्यकता के अनुपात में वृद्धि से संकट की संभाव्यता बढ़ती है।

भारत के लिए संयुक्त बाह्य संवेदनशीलता सूचकांक तैयार करने के लिए संकट की अनुमानित संभाव्यता की समय श्रृंखलाओं का उपयोग किया गया। सूचकांक, संकट की संभाव्यता के बेस वैल्यू के विरुद्ध तैयार किए गए थे, जो उस न्यूनतम सीमा को दर्शाता है जिसके ऊपर संभाव्यता में वृद्धि होने का मतलब है कि बाह्य आघातों और संकट के प्रति देश की संवेदनशीलता बढ़ेगी। संकट की शर्त रहित संभाव्यता, अर्थात्, न्यूनतम सीमा, 0.096 (या 9.6 प्रतिशत) अनुमानित थी। संकट की शर्त रहित संभाव्यता को 100 के बराबर करने के जरिए, संकट की संभाव्यताओं की श्रृंखलाओं को बाह्य संवेदनशीलता सूचकांकों में रूपांतरित किया गया। कोई अर्थव्यवस्था

सारणी II.1: संकट की संभाव्यता का प्रोबिट अनुमान

व्याख्यात्मक चर	गुणांक
जीडीपी में निवल आईआईपी अनुपात	2.34***
रिज़र्व में बाह्य वित्तीय आवश्यकता अनुपात	0.23*
कुल बाह्य कर्ज में अल्पावधि कर्ज का हिस्सा	3.20***
सरकारी प्रभावशीलता सूचकांक	-0.68**
वैश्विक चलनिधि	0.06
वृद्धि अंतर (-1)	-5.15***
मैकफेडन आर ²	0.26
एलआर सांख्यिकी	30.60

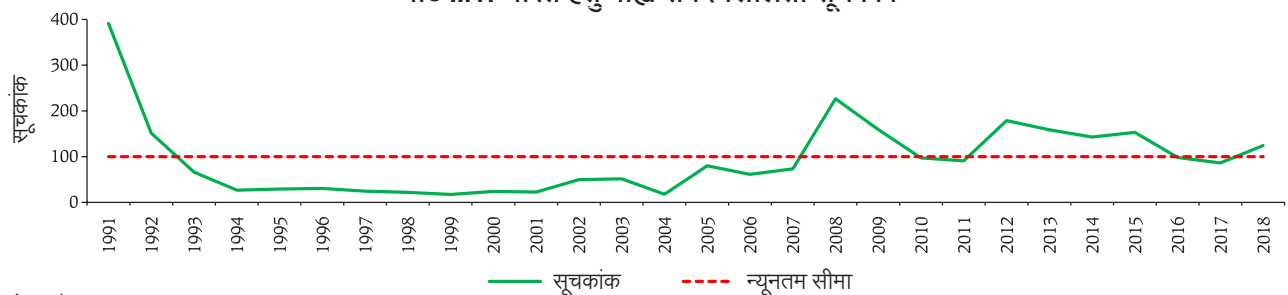
***, **, और * दर्शाता है कि 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तरों पर काफी है।

स्रोत: गोयल (2019)।

बाह्य आघातों और संकट के प्रति संवेदनशील मानी जा सकती है जब बाह्य संवेदनशीलता सूचकांक 100 या उससे अधिक हो।

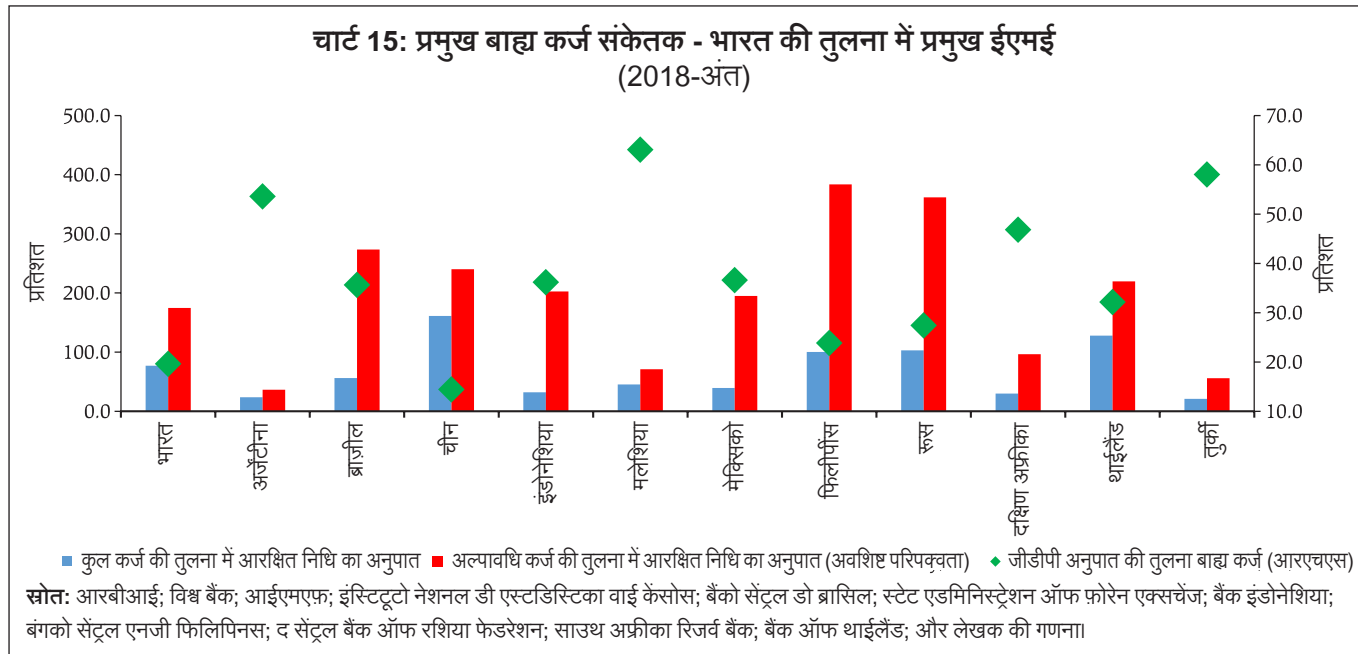
बाह्य संवेदनशीलता सूचकांक को लेकर तैयार की गई श्रृंखला काफी हद तक भारत के बाह्य क्षेत्र में दबाव के पिछली घटनाओं को दर्शाती है (चार्ट II.1)। सैम्पल अवधि में, भारत की बाह्य संवेदनशीलता का स्तर 1990 के दशक की शुरुआत में भुगतान संतुलन संकट की घटना के दौरान उच्चतम मापा गया था, और तत्पश्चात 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट की घटना के दौरान। भारत का बाह्य संवेदनशीलता सूचकांक 2012-15 के दौरान न्यूनतम सीमा के ऊपर रहा, जो इस अवधि में भारत के सीएडी में तेज वृद्धि और भारत के बाह्य क्षेत्र पर प्रमुख केंद्रीय बैंकों के कटौती के त्रास भरे दौर तथा मौद्रिक नीतियों के प्रभाव को दर्शाता है। वर्ष 2018 में, सूचकांक न्यूनतम सीमा से मामूली रूप से ऊपर था क्योंकि कुल बाह्य कर्ज में अल्पावधि कर्ज की हिस्सेदारी और रिज़र्व में बाह्य वित्तीय आवश्यकता के अनुपात में मामूली बढ़ोतरी हुई। महत्वपूर्ण रूप से, फिर भी 2019 में अधिकांश बाह्य संवेदनशीलता संकेतक (विशेषकर रिज़र्व से जुड़े संकेतक) बेहतर हुए हैं।

चार्ट II.1: भारत हेतु बाह्य संवेदनशीलता सूचकांक



स्रोत: गोयल (2019)।

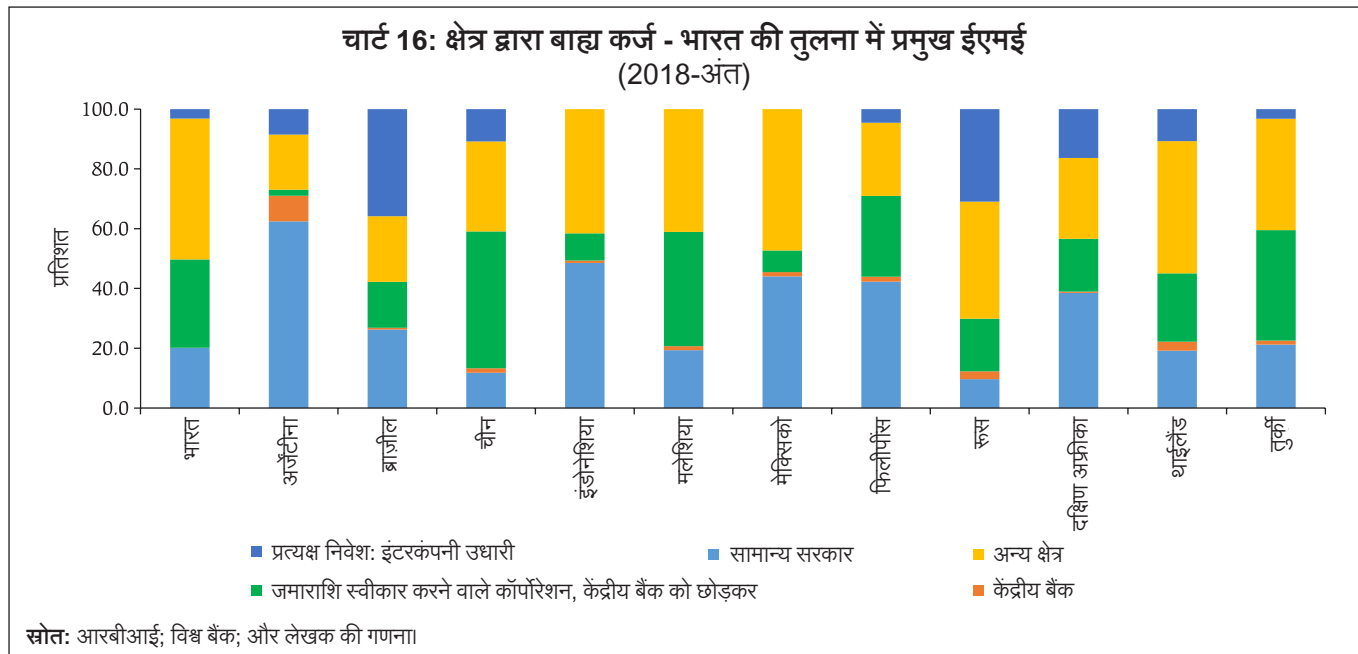
[एह बॉक्स अनुभवजन्य अनुमान एवं गोयल. आर. (2019) द्वारा भारत हेतु बाह्य संवेदनशीलता सूचकांकों को लेकर तैयार की गई श्रृंखलाओं पर आधारित है, "भारत हेतु बाह्य संवेदनशीलता सूचकांक", भारतीय रिज़र्व बैंक, मिमीओ।]



अनुपात के संदर्भ में, भारत की स्थिति उसके समकक्ष ईएमई की तुलना में बेहतर है – उसका जीडीपी की तुलना में बाह्य कर्ज में अनुपात, चीन के सिवाय उसके प्रमुख समकक्षों की अपेक्षा कम थी (चार्ट 15)। कुल बाह्य कर्ज के आरक्षित निधि कवर के मामले में, भारत ब्राजील, मलेशिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और तुर्की से बेहतर है। हालाँकि भारत का आरक्षित निधि अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर उसकी

अल्पकालिक देनदारियों से अधिक था, लेकिन इसका कवर उसके कुछ समकक्षों (अर्थात्, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, तुर्की और अर्जेंटीना) की तुलना में अधिक था।

बाह्य कर्ज की क्षेत्रीय संरचना से पता चलता है कि अधिकांश प्रमुख ईएमई में सरकारों की कुल बाह्य कर्ज में भारत की तुलना में बड़ी हिस्सेदारी है (चार्ट 16)। इन देशों में तुर्की,

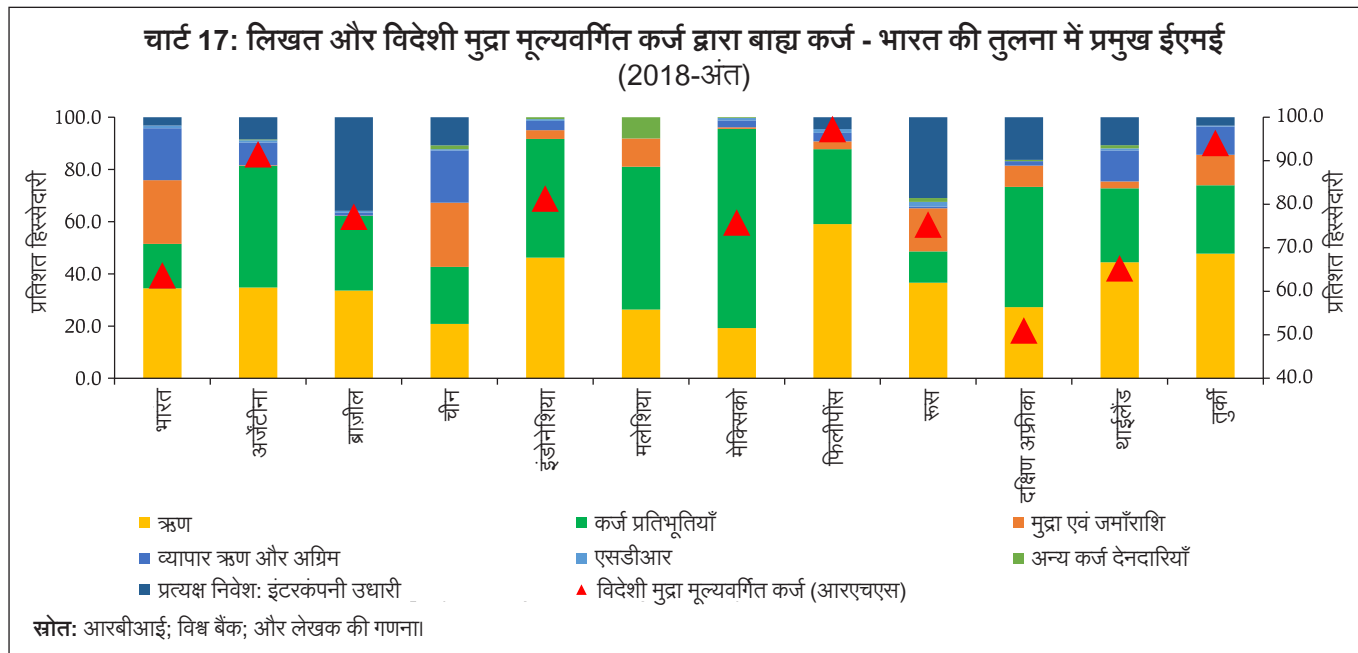


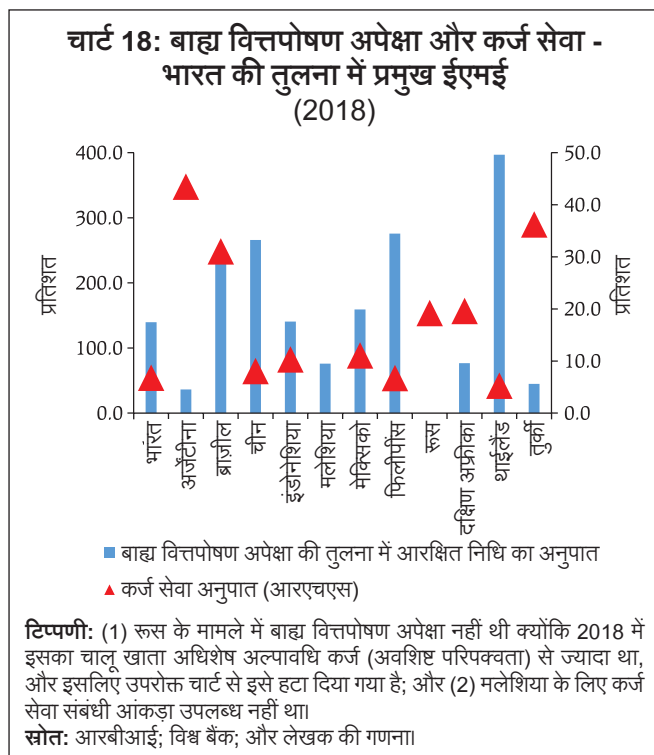
ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, मैक्सिको, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना शामिल हैं। विशेष रूप से, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में सरकारें बाह्य उधारी गतिविधि में शामिल हैं और अन्य क्षेत्रों की तुलना में बाह्य कर्ज में डूबी हुई हैं। गैर-सरकारी क्षेत्रों में, कुल कर्ज में भारत के अन्य क्षेत्रों (अन्य वित्तीय निगमों, गैर-वित्तीय निगम और एनपीआईएसएच सहित) के कर्ज की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। यह चुनिंदा प्रमुख ईएमई के बीच मैक्सिको के बाद दूसरा उच्चतम स्तर है। चीन, मलेशिया और तुर्की में जमाराशि स्वीकार करने वाले निगमों (केंद्रीय बैंक को छोड़कर) की भारत की तुलना में हिस्सेदारी अधिक है। ज्यादातर चुनिंदा प्रमुख ईएमई में एफडीआई कंपनियों के बीच इंटरकंपनी लेंडिंग का हिस्सा भारत से अधिक है।

बाह्य कर्ज के लिखत-वार वर्गीकरण से पता चलता है कि भारत की तरह, फिलीपींस, तुर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड, और रूस में कर्ज की हिस्सेदारी सबसे अधिक है (चार्ट 17)। भारत के

बाह्य कर्ज में क्रमशः मुद्रा और जमा, और व्यापार ऋण और अग्रिम जो दूसरे और तीसरे सबसे बड़े घटक हैं, भारत में उनकी तुलना में केवल चीन में उच्चतर हिस्सेदारी है। रूस को छोड़कर सभी देशों में कर्ज प्रतिभूतियों की भारत की तुलना में उसकी हिस्सेदारी अधिक है। विशेष रूप से, अधिकांश प्रमुख ईएमई में ऋण और कर्ज प्रतिभूतियों में उनके बाह्य कर्ज का 50 प्रतिशत से अधिक है। प्रमुख ईएमई में, फिलीपींस में ऋण की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जबकि ऋण प्रतिभूतियों की मैक्सिको में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर सभी प्रमुख ईएमई में बाह्य कर्ज भारत की तुलना में विदेशी मुद्राओं में अधिक मूल्यवर्गीकृत हैं।

बाह्य वित्तपोषण आवश्यकता के आरक्षित निधि कवर के मामले में, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, तुर्की और अर्जेंटीना जैसे अपने कुछ समकक्षों की तुलना में भारत का स्थान बेहतर है। हालांकि, कर्ज सेवा अनुपात के मामले में, भारत अपने अधिकांश समकक्षों से बेहतर स्थान पर रहा।





VII. निष्कर्ष

वर्ष 2016-17 में गिरावट के बाद 2017-18 के बाद से भारत के बाह्य कर्ज का स्टॉक बढ़ गया है। फिर भी, 2014-15 से 2015-16 के दौरान 23.6 प्रतिशत का औसत निकालने के बाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाह्य कर्ज बाद के वर्षों में लगभग 20 प्रतिशत कम रहे। इसका श्रेय बाह्य कर्ज के बजाए भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च विकास को दिया जा सकता है। भारत की विवेकपूर्ण बाह्य क्षेत्र प्रबंधन नीतियों ने इसकी बाह्य भेद्यता को कम करके रखा है – आरक्षित निधियों ने अल्पकालिक कर्ज दायित्वों (अवशिष्ट परिपक्वता), आयात और बाह्य वित्तपोषण आवश्यकता के लिए पर्याप्त कवर प्रदान किया है; और कर्ज सेवा अनुपात कम बना हुआ है।

भारत जीडीपी अनुपात और कर्ज सेवा अनुपात की तुलना में बाह्य कर्ज के मामले में अपने ईएमई समकक्षों की तुलना में बेहतर है। हालांकि, भारत के अधिकांश समकक्षों ने अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता) और बाह्य वित्तपोषण आवश्यकता के आरक्षित निधि कवर के अपने स्तर को पार कर लिया है। फिर भी, यह बहुत चिंता का विषय नहीं है क्योंकि भारत की आरक्षित निधि ने अल्पकालिक कर्ज (अवशिष्ट परिपक्वता)

और बाह्य वित्तपोषण आवश्यकता के लिए 100 प्रतिशत से अधिक कवर प्रदान किया है।

भारत के बाह्य कर्ज पर अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव की अनुभवजन्य जाँच ने पुष्टि की है कि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर, जिसमें भारत का बाह्य कर्ज मूल्यवर्गित है, की मजबूती (मूल्यहास) से अमेरिकी डॉलर में भारत के बाह्य कर्ज के परिमाण को कम करता (बढ़ता है) है। हालांकि, सीएडी बाह्य कर्ज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देता है क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा गैर-कर्ज प्रवाह के साथ-साथ मध्यम पूंजी प्रवाह की अवधि के दौरान आरक्षित निधि है जैसा कि वर्ष 2008-09, 2011-12 और 2018-19 में हुआ था। लेख में भारत के लिए बाह्य भेद्यता सूचकांक तैयार करने की पद्धति भी प्रस्तुत की गई है। बाह्य भेद्यता सूचकांकों की निर्मित श्रृंखला काफी हद तक भारत के बाह्य क्षेत्र में तनाव के पिछले प्रकरणों को ग्रहण कर लेती है। बाह्य भेद्यता सूचकांक ने 1990 के दशक की शुरुआत में भुगतान संतुलन संकट के प्रकरण, इसके बाद 2008-09 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भेद्यता के स्तर को उच्चतम रहने, और भारत के सीएडी में तेज वृद्धि तथा कटौती के त्रास भरे दौर के प्रभाव और 2012-15 के दौरान प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों के बारे में संकेत दिया है।

संदर्भ

Catão, L.A.V. and G.M. Milesi-Feretti (2013), "External Liabilities and Crises", *IMF Working Paper No. 13/113*.

Eichengreen, B. and M.D. Bordo (2002), "Crises Now and Then: What Lessons from the Last Era of Financial Globalization?", *NBER Working Paper Series 8716*.

Goyal (2012), "Sustainable Level of India's Current Account Deficit", *RBI Working Paper Series No. WPS (DEPR): 16/2012*, Reserve Bank of India.

International Monetary Fund (2000), "Debt- and Reserve-related Indicators of External Vulnerability", Prepared by the Policy Development and Review Department, International Monetary Fund.

International Monetary Fund (2009), *Balance of Payments and International Investment Position Manual*, International Monetary Fund.

International Monetary Fund (2011), "Assessing Reserve Adequacy", Prepared by Monetary and Capital Markets, Research, and Strategy, Policy, and Review Departments, International Monetary Fund.

International Monetary Fund (2014), *External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users*, International Monetary Fund.

International Monetary Fund (2018), "2018 Article IV Consultation – Press Release; Staff Report; And Statement by The Executive Director for India". Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/08/06/India-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-46155>.

International Monetary Fund, "International Financial Statistics", Retrieved from <https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B>.

International Monetary Fund, "World Economic Outlook Database", Retrieved from <https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending>.

Lane, P.R. and G.M. Milesi-Ferretti (2017), "International Financial Integration in the Aftermath of the Global Financial Crisis", *IMF Working Paper No. 17/115*.

Reserve Bank of India (1998), *Report of the Technical Group on External Debt*, Reserve Bank of India.

Tille, C. (2003), "The Impact of Exchange Rate Movements on U.S. Foreign Debt", *Current Issues in Economic and Finance, Vol. 9, No. 1*, Federal Reserve Bank of New York.

World Bank Group, "DataBank", Retrieved from <https://databank.worldbank.org/home.aspx>.

परिशिष्ट I:

भारत का बाह्य कर्ज प्रबंधन - 2018-19 और 2019-20 के दौरान अब तक की प्रमुख नीतिगत गतिविधियाँ

बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ (ईसीबी)

नवंबर 2018: भारत सरकार के परामर्श से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 और 5 वर्ष के बीच की परिपक्वता अवधि के लिए पात्र उधारकर्ताओं द्वारा ईसीबी फ्रेमवर्क के ट्रैक I के तहत जुटाए गए ईसीबी के लिए अनिवार्य हेज कवरेज को 100 प्रतिशत से घटाकर 70 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

जनवरी 2019: ईसीबी और रुपए में मूल्यवर्गित बॉन्ड्स (आरडीबी) के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से ट्रैक I और II को "विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित ईसीबी" और ट्रैक III एवं आरडीबी फ्रेमवर्क को "रुपए मूल्यवर्गित ईसीबी" के रूप में विलय करने का निर्णय लिया। एफडीआई प्राप्त करने के लिए पात्र सभी संस्थाओं को पात्र उधारकर्ताओं के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की इकाइयों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), एक्जिम बैंक, माइक्रो-फाइनेंस गतिविधियों में लगे पंजीकृत संस्थाएं, अर्थात्, पंजीकृत अलाभकारी कंपनियां, पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट/सहकारी और गैर-सरकारी संगठनों को भी इस फ्रेमवर्क के तहत उधार लेने की अनुमति दी गई थी।

फरवरी 2019: रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत अनुमोदन मार्ग के तहत लक्ष्य कंपनी के रुपये में लिए गए मियादी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए समाधान आवेदकों के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया और भारतीय बैंकों की शाखाओं/विदेशों में स्थित अनुषंगी संस्थाओं को छोड़कर, मान्यताप्राप्त उधारदाताओं से ईसीबी जुटाने की अनुमति दी।

जुलाई 2019: रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से ईसीबी के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया। तदनुसार, पात्र उधारकर्ताओं को भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर, मान्यता प्राप्त उधारदाताओं से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ईसीबी जुटाने की अनुमति दी गई थी:

i. कार्यशील पूंजीगत उद्देश्यों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए 10 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि

वाली ईसीबी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आगे ऋण देने के लिए उपरोक्त परिपक्वता के लिए उधार देने की भी अनुमति है।

- ii. 7 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले ईसीबी का लाभ पात्र उधारकर्ताओं द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू रूप से प्राप्त किए गए रुपये ऋण के पुनर्भुगतान के लिए और साथ ही एनबीएफसी द्वारा उसी उद्देश्य के लिए आगे ऋण देने के लिए उठाया जा सकता है। पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए और एनबीएफसी द्वारा आगे ऋण देने के लिए घरेलू स्तर पर प्राप्त किए गए रुपये ऋण के पुनर्भुगतान के लिए, ईसीबी की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए।
- iii. यदि एसएमए -2 या एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के लिए घरेलू स्तर पर लिए गए रुपये ऋण चुकाने के लिए उधारकर्ता के साथ किसी भी एक मुश्त निपटान के तहत पात्र कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को ईसीबी का लाभ उठाने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया था। भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/विदेशी सहायक कंपनियों को छोड़कर, पात्र ईसीबी ऋणदाताओं को ऐसे ऋणों को असाइनमेंट के माध्यम से बेचने के लिए भी ऋणदाता बैंकों को अनुमति दी जाती है, बशर्ते परिणामी बाह्य वाणिज्यिक उधारी ईसीबी फ्रेमवर्क के सभी-लागत सहित, न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि और अन्य प्रासंगिक मानदंडों का अनुपालन करें।

कर्ज प्रतिभूति में एफपीआई निवेश

अप्रैल 2018: रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) में एफपीआई द्वारा निवेश के लिए न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता को संशोधित किया। एफपीआई को बिना किसी न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता की आवश्यकता के (पहले यह तीन साल थी) ट्रेजरी बिल, और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) सहित जी-सेक में निवेश करने की अनुमति थी, इस शर्त के अधीन कि एफपीआई द्वारा अल्पकालिक निवेश श्रेणी उस श्रेणी के उस एफपीआई के कुल निवेश का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, एफपीआई को एक वर्ष (पहले यह तीन

साल थी) से ऊपर की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दी गई थी, इस शर्त के अधीन कि एफपीआई द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड में अल्पकालिक निवेश कॉर्पोरेट बॉन्ड में उस एफपीआई के कुल निवेश का कुल के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

फरवरी 2019: भारतीय कॉर्पोरेट कर्ज बाजार तक पहुँचने हेतु निवेशकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने यह कहते हुए प्रावधान को वापस लेने का फैसला किया कि “कोई भी एफपीआई एकल कॉर्पोरेट (कॉर्पोरेट से संबंधित संस्थाओं को एक्सपोजर सहित) को अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो के 20 प्रतिशत से अधिक का एक्सपोजर नहीं करेगा।”।

मार्च 2019: भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने ‘स्वैच्छक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर)’ नामक एक अलग चैनल शुरू किया, जिससे एफपीआई को भारत में कर्ज बाजारों में निवेश करने में सक्षम बनाया जा सके। मोटे तौर पर, रूट के माध्यम से निवेश मैक्रो-प्रूडेंशियल और अन्य विनियामक मानदंडों से मुक्त है, जो ऋण बाजारों में एफपीआई निवेश के लिए लागू होते हैं, बशर्ते एफपीआई

स्वेच्छा से एक अवधि के लिए भारत में अपने निवेश के न्यूनतम प्रतिशत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो।

अप्रैल 2019: भारत में कर्ज लिखतों के लिए अनिवासी निवेशकों की पहुंच को व्यापक बनाने के उपाय के रूप में, रिज़र्व बैंक ने एफपीआई को नगरपालिका बांड में निवेश करने की अनुमति दी।

अनिवासी रुपया खाता

नवंबर 2019: भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा आईएनआर उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने (i) ईसीबी; (ii) व्यापार क्रेडिट; (iii) व्यापार (निर्यात/आयात) चालान; और (iv) गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) में आईएफएससी इकाइयों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के बाहर व्यापार से संबंधित लेनदेन जैसे आईएफएससी के बाहर आईएनआर में प्रशासनिक व्यय, स्क्रेप की बिक्री से प्राप्त आईएनआर राशि, आईएनआर में सरकार के प्रोत्साहन आदि के लिए इस तरह के खाते को खोलने के लिए भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को अनुमति देकर विशेष अनिवासी रुपये (एसएनएनआर) खाते के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया। यह खाता भारत में स्थित बैंक (आईएफएससी के बाहर) में रहेगा।

परिशिष्ट II

आईएमएफ के 2013 ईडीएस गाइड के अनुसार भारत के बाह्य कर्ज के डेटा प्रसार का परिचय

पिछले चार दशकों में कर्ज और वित्तीय संकट, विशेष रूप से 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट, ने कई उन्नत, और उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की उच्च बाह्य कर्ज में डूबे होने संबंधी कमजोरियों को उजागर किया है। इन संकटों ने देशों की बाहरी कमजोरियों का जल्द पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बाह्य कर्ज पर विश्वसनीय, समय से और व्यापक डेटा के संकलन और प्रसार के महत्व को रेखांकित किया है। इसके मद्देनजर, आईएमएफ ने 2013 एक्स्टर्नल डेट स्टेटिस्टिक्स: गाइड फॉर कंपाइलर्स एंड यूजर्स को इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स ऑन फाइनेंस स्टेटिस्टिक्स (टीएफएफएस) के नौ अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत बाह्य कर्ज के राष्ट्रीय संकलक, भुगतान संतुलन (बीओपी) और अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति (आईआईपी) के आंकड़े को ध्यान में रखकर तैयार किया। आईएमएफ के 2013 एक्स्टर्नल डेट स्टेटिस्टिक्स (ईडीएस) गाइड में निर्धारित अवधारणाएं सिस्टम ऑफ नेशनल एकाउंट्स (एसएनए) 2008 और 2009 में प्रकाशित आईएमएफ के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इनवेस्टमेंट पोजिशन मैनुअल (बीपीएम6) के छठे संस्करण के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं। गाइड का अवधारणात्मक दृष्टिकोण बाह्य कर्ज संबंधी सांख्यिकी और किसी देश के अन्य समष्टि-आर्थिक सांख्यिकी, जैसे कि बीओपी, आईआईपी और राष्ट्रीय खातों के बीच स्थिरता और तुलना की सुविधा प्रदान करता है। यह गाइड सकल बाह्य कर्ज की स्थिति पर व्यापक डेटा के संकलन और प्रसार की सिफारिश करता है, यानी कि देनदार क्षेत्रों, लिखतों और परिपक्वता द्वारा दूसरों के बीच में। गाइड की सिफारिशें बाह्य पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय आंकड़ों के संकलन और प्रसार में उपयोगी हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बाह्य कर्ज की स्थिति पर सांख्यिकी तैयार करने के लिए और भारत के अन्य मैक्रोइकॉनॉमिक आंकड़ों जैसे कि बीओपी और आईआईपी आंकड़े, जो पहले से ही आईएमएफ के बीपीएम6 के अनुसार संकलित और प्रसारित किए जा रहे हैं, के अनुरूप बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सितंबर

2019 में जून 2019 के अंत तक की भारत के बाह्य कर्ज की स्थिति संबंधी सांख्यिकी को जारी करने के साथ ही आईएमएफ के 2013 ईडीएस गाइड प्रारूप के अनुसार भारत के बाह्य कर्ज पर आंकड़ों के संकलन और प्रसार की शुरुआत अतिरिक्त प्रारूप के रूप में की। ब्राजील, चिली, चीन मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड और अमेरिका जैसे कई उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं अपने बाह्य कर्ज संबंधी आंकड़ों का संकलन और प्रसार करने के लिए आईएमएफ के 2013 ईडीएस गाइड का पालन करते हैं। जून 2019 में मार्च 2019 के अंत तक की भारत की बाह्य कर्ज स्थिति पर आंकड़े जारी होने तक, भारत के बाह्य कर्ज सांख्यिकी संबंधी नीति समूह/कार्य बल (पीजी/टीएफ) की सिफारिशों (1992) और बाह्य कर्ज पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (1998) के अनुसार, सकल कर्ज की स्थिति को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा रहा था: बहुपक्षीय कर्ज, द्विपक्षीय कर्ज, आईएमएफ-एसडीआर, व्यापार ऋण, वाणिज्यिक उधारियाँ, अनिवासी जमाराशि, रुपया कर्ज, और अल्पकालिक कर्ज। आईएमएफ के 2013 ईडीएस गाइड की सिफारिशों के बाद, भारत की बाह्य कर्ज की स्थिति को कर्ज क्षेत्रों, लिखतों और परिपक्वता द्वारा वर्गीकृत किया गया है। देनदार क्षेत्रों में सामान्य सरकार, केंद्रीय बैंक, जमाराशि स्वीकार करने वाले कॉरपोरेशन (केंद्रीय बैंक को छोड़कर), अन्य क्षेत्र (अन्य वित्तीय निगमों, गैर-वित्तीय निगम और हाउसहोल्ड और हाउसहोल्ड की सेवा देने वाली गैर-लाभकारी संस्थाएं (एनपीआईएसएच)), और प्रत्यक्ष निवेश: इंटरकंपनी ऋण देना शामिल हैं। कर्ज की क्षेत्रीय स्थिति को अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्थिति के तहत, क्षेत्र-विशिष्ट लिखतों, यथा, ऋण, कर्ज प्रतिभूतियों, मुद्रा और जमाराशि, व्यापार ऋण और अग्रिम, एसडीआर (आवंटन), और अन्य कर्ज देनदारियों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार, आईएमएफ के 2013 ईडीएस गाइड के अनुसार प्रारूप नीति निर्माताओं और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भारत के बाह्य कर्ज पर अतिरिक्त जानकारी (यानी, क्षेत्रीय, लिखत- और परिपक्वता-वार कर्ज की स्थिति) प्रदान करता है।

आरित गुणवत्ता मूल्यांकन में क्रेडिट रेटिंग्स की प्रभावकारीता*

प्रोवेस के साथ मैप किए गए सेंट्रल रिपॉजिटोरी ऑफ इनफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिटस (सीआरआईएलसी) से क्रेडिट रेटिंग्स पर डेटा का उपयोग करते हुए, यह लेख बड़े उधारकर्ताओं की आरित गुणवत्ता की सही और समय पर मूल्यांकन की सुविधा में रेटिंग की प्रभावकारीता की जांच करता है। सीआरआईएलसी से नमूना अनर्जक आरितियों (एनपीए) के एक्सपोजर का लगभग एक-चौथाई हिस्सा एनपीए की श्रेणी में आने से ठिक एक तिमाही पहले, निवेश ग्रेड में पाया गया था। अनर्जक बनने से ठिक पहले निवेश ग्रेड रेटिंग के साथ एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) में अलग-अलग है तथा अध्ययन में शामिल छह में से तीन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) में इस तरह के एक्सपोजर का अपेक्षाकृत उच्च केंद्रीकरण दर्शाता है।

भूमिका

आधुनिक समय के वित्तीय क्षेत्र विनियामक ढांचे के कार्यान्वयन में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां महत्वपूर्ण हितधारक हैं। विभिन्न आरितियों की जोखिम का आकलन करने और बैंकों के लिए संबंधित पूंजी अपेक्षाओं का अनुमान लगाने के लिए बासेल II विनियामक ढांचे के अंतर्गत एजेंसी / बाहरी रेटिंग को निर्धारित किया गया था। इसके जोखिम-संवेदनशील दृष्टिकोण को देखते हुए, बासेल II ढांचे को 1988 के बासेल समझौते (अक्सर बासेल I ढांचे के रूप में जाना जाता है) का संशोधित रूप माना गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की आरितियों में अंतर्निहित डिफॉल्ट जोखिमों के अलावा पूंजी गणना के लिए एक सरलीकृत प्रणाली का पालन किया (रॉय, 2005)। हालाँकि, सीआरए की भूमिका, विशेष रूप से अंतर्निहित जोखिमों के कारकों की अक्षमता की 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान आलोचना की गयी, एजेंसी रेटिंग्स बासेल III ढांचे का एक अभिन्न अंग बना रहा जो संकट की विनियामक प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ (सिंकलेयर, 2010)।¹

* यह लेख सुखबीर सिंह और पल्लवी चव्हाण, पर्यवेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

¹ हालाँकि, बासेल III ढांचे को पूंजी आवश्यकताओं के प्रचक्रिय स्वरूप को संबोधित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें क्रेडिट रेटिंग्स के लिए जोखिम भार को जोड़ने से उत्पन्न होने वाली चक्रियता भी शामिल है।

बासेल II और बासेल III ढांचे दोनों के अंतर्गत क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण में एजेंसी रेटिंग का उपयोग शामिल है। इन रूपरेखाओं के अंतर्गत, मानकीकृत दृष्टिकोण को आधार-स्तरीय दृष्टिकोण के रूप में वर्णित किया गया है; बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न आरितियों को सौंपी गई अपनी आंतरिक रेटिंग के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं की मॉडलिंग करते हुए आंतरिक रेटिंग-आधारित (आईआरबी) दृष्टिकोण पर जाएं। आंतरिक रूप से तैयार किए गए दृष्टिकोणों की बढ़ती आलोचना के कारण, हाल ही में, बैंकिंग पर्यवेक्षण (बीसीबीएस) की बासल समिति ने बासल III ढांचे पर फिर से विचार किया है और आईआरबी दृष्टिकोण के उपयोग पर कुछ प्रतिबंधों का प्रस्ताव किया है और वास्तव में इसकी ग्रैनुलैरिटी और जोखिम संवेदनशीलता (बीसीबीएस, 2017) के संदर्भ में² मानकीकृत दृष्टिकोण को मजबूत किया है। प्रस्तावित सुधारों के बाद, नियामक ढांचे में एजेंसी रेटिंग की भूमिका पुनः पुष्टि होती है।³

वर्तमान में, भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) सहित दुनिया भर के अधिकांश बैंक मानकीकृत दृष्टिकोण (पूर्वोक्त) का उपयोग करते हैं। जबकि आईआरबी दृष्टिकोण पर कई अध्ययन हैं, मानकीकृत दृष्टिकोण (रॉय, 2005) पर सीमित चर्चा है। सीआरए पर उपलब्ध अध्ययनों में से कुछ मुख्य रूप से उनकी कार्यपद्धति (एडरिंगटन, 1986) के कारण उनकी रेटिंग में अंतर का विश्लेषण करते हैं। जारीकर्ताओं द्वारा रेटिंग खरीदारी और आत्म-चयन की संभावना की साहित्य (बीट्टी एंड सेरले, 1992 और केंटर एंड पैकर, 1997) में भी सिफारिश की है।

भारतीय संदर्भ में, जबकि सीआरए के संचालन पर व्यापक वास्तविक साक्ष्य हैं, इस मुद्दे पर व्यवस्थित अध्ययन कम हैं। सीआरए के बारे में उल्लेखनीय अध्ययनों में से एक, यह दर्शाता है कि भारत में मान्यता प्राप्त सीआरए के लिए संचयी निर्धारित दरें (सीडीआर) बासेल ढांचे के अंतर्गत निर्धारित की तुलना में

² इन सुधारों के हिस्से के रूप में एक उल्लेखनीय प्रस्ताव गैर निर्धारित जोखिम (ibid) के लिए जोखिम भार संशोधित करना था।

³ <https://www.reuters.com/article/basel-banks-regulations/basel-regulators-make-u-turn-on-banks-use-of-credit-rating-agencies-idUSL8N1290WX20151009>. पर ह्यू जॉन्स (2015) द्वारा " बैंकों की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के उपयोग पर बासेल नियामकों का यू-टर्न" देखें।

बहुत अधिक हैं। परिणामस्वरूप, बीसीबीएस (चौधरी और अन्य, 2017) द्वारा निर्धारित जोखिम भार बैंकों में कम लागू करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है (चौधरी और अन्य, 2017)। उधारकर्ताओं की कमजोर साख पर समय पर मार्गदर्शन प्रदान करने में सीआरए की असमर्थता पर भी कुछ प्रमाण हैं। (चौधरी और अन्य, 2017 में एनआईएसएम 2009)।

वर्तमान लेख भारत में विशेष रूप से बैंकिंग पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता का आकलन करने के लिए भारत में एजेंसी रेटिंग की प्रभावकारिता का विश्लेषण से योगदान देता है। बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य संरक्षण के दीर्घकालिक लक्ष्य से प्रेरित पर्यवेक्षक, उधारकर्ताओं / जारीकर्ताओं की साख की एक सटीक और समय पर मूल्यांकन में रुचि रखता है, जो बैंकों में पूंजी पर्याप्तता का एक उचित सही मूल्यांकन करता है।

इसके विपरीत, सीआरए व्यवसाय विस्तार से संबंधित अल्पकालिक लक्ष्यों में दिलचस्पी के कारण, उनके पोर्टफोलियो के लिए कम सीडीआर रखते हैं। बैंक भी बढ़ी हुई आस्ति वृद्धि के लिए पूंजी संरक्षण के अल्पकालिक लक्ष्य से प्रेरित हो सकता है।⁴ प्रमुख अर्थात् पर्यवेक्षक और दो एजेंटों, यानी सीआरए और बैंकों के बीच एक स्पष्ट टकराव होता है, और यह संघर्ष सीआरए द्वारा दी गई रेटिंग और बैंकों द्वारा उनकी पूंजी गणना में उपयोग की जाने वाली रेटिंग में परिलक्षित होता है। लेख निम्नलिखित प्रश्नों को संबोधित करता है जो इस संघर्ष का कारण हैं:

1. क्या बाहरी क्रेडिट रेटिंग्स बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करते हैं?
 - ए. समय-सीमा में उधारकर्ता के एनपीए की स्थिति को किस हद तक दर्शाया जा सकता है और क्या इस मूल्यांकन में सीआरए में कोई मतभेद है?
 - बी. एनपीए बनने के बाद उधारकर्ता के लिए कितनी जल्दी डाउनग्रेड आती है?
2. उधारकर्ता के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और बैंकों द्वारा सूचित रेटिंग के बीच कितना मतभेद है?

⁴ साहित्य में रेटिंग बढ़ाने के लिए बैंकों की प्रवृत्ति के बारे में चर्चा की गई है ताकि कम पूंजी (बालिन, 2010 को गोपालन और अन्य, 2016 में उद्धृत) आवंटित की जा सके।

II. डेटा स्रोत और कार्यपद्धति

इस लेख का प्रमुख डेटा स्रोत “बड़े उधारकर्ताओं” (50 मिलियन और उससे अधिक के वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित एक्सपोजर) पर डेटा के संग्रह के लिए 2014 में रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित सीआरआईएलसी है। सीआरआईएलसी में बाहरी क्रेडिट रेटिंग उधारकर्ता-विशिष्ट रेटिंग हैं। बीसीबीएस के मार्गदर्शन के बाद, एक ही उधारकर्ता पर दो अंतर रेटिंग के मामले में, बैंक दोनों की पारंपारिक रेटिंग सूचित करने की अपेक्षा है। सीआरआईएलसी उधारकर्ताओं के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में स्थायी खाता संख्या (पीएएन) का उपयोग करता है। अप्रैल 2018 से, सीआरआईएलसी में कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) भी सूचित की जा रही है।

यह लेख मार्च 2018 (सारणी 1) के अंत तक एनपीए के नमूने पर आधारित है। अनर्जक उधारकर्ता के नमूने में से, जिन विशिष्ट रेटेड उधारकर्ता हैं, जिनका सीआईएन प्राप्त और मान्य है को अध्ययन के लिए चुना गया है, और प्रोवेस - कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग्स पर डेटा का एक वैकल्पिक बाहरी स्रोत (सारणी 2)⁵ में सूचित उधारकर्ता के साथ मिलाया गया है। इस प्रकार, लेख के

सारणी 1: एनपीए जनसंख्या का आकार (मार्च 2018 के अंत तक)

मद	कुल	रेटेड	अनरेटेड
विशिष्ट उधारकर्ता	7,147	2,625 (37%)	5,172 (72%)
बैंक-उधारकर्ता मामले	10,931	4,504 (41%)	6,427 (59%)
राशि (रु. ट्रिलियन)	8.85	5.27 (60%)	3.58 (40%)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल में शेयर का दर्शाते हैं।

2. जैसा कि सीआरआईएलसी में सूचित किया गया उधारकर्ता एक से अधिक बैंक के संपर्क में हो सकता है, यहां विशिष्ट उधारकर्ताओं (प्रत्येक उधारकर्ता को केवल एक बार गिना जाता है) और बैंक-उधारकर्ता के बीच फर्क किया गया है (उधारकर्ता के बैंकिंग संबंधों के आधार पर गिना जाता है)।
3. विशिष्ट उधारकर्ताओं के लिए अनुपात का योग 100 तक नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि एक ही उधारकर्ता को एक बैंक द्वारा रेट किया जा सकता है और दूसरे बैंक द्वारा रेट नहीं किया जा सकता है।

स्रोत: सीआरआईएलसी

⁵ जबकि बैंक सीआरआईएलसी के बाहरी रेटिंग के आधार पर जानकारी देते हैं, उधारकर्ताओं का एक वर्ग सीआरआईएलसी में अनरेटेड हैं। इस लेख में अनरेटेड उधारकर्ताओं पर चर्चा शामिल नहीं है। इसके अलावा, हालांकि सीआईएन की रिपोर्टिंग अनिवार्य है, सीआईएन के संग्रह पर काम चल रहा है। लेख केवल उन मामलों का उपयोग करता है जहां सीआईएन प्राप्त हुआ है और मान्य है।

सारणी 2: सीआरआईएलसी में सूचित कुल रेटेड एनपीए का नमूना

मद	कुल रेटेड एनपीए	प्रोवेस में सूचित सीआरए से रेटिंग प्राप्त विशिष्ट सीआरआईएन के एनपीए
विशिष्ट उधारकर्ता	2,625	560 (21%)
बैंक-उधारकर्ता मामले	4,504	1,274 (28%)
राशि (रु. ट्रिलियन)	5.27	2.13 (40%)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दी गयी संख्या कुल का प्रतिशत दर्शाती है।

2. रिपोर्ट किए गए सीआरए से तात्पर्य उन मामलों से है जिनके लिए रेटिंग सूचना सीआरआईएलसी में सूचित की गई उसी सीआरए के प्रोवेस में उपलब्ध है।

लिए नमूना, 560 एनपीए उधारकर्ता जो लगभग 21 प्रतिशत हैं और मार्च 2018 के अंत तक एनपीए की कुल राशि का 40 प्रतिशत अत्यधिक है। यह देखते हुए कि लेख का पता चलता है। इन एनपीए उधारकर्ताओं का इतिहास, केवल तिमाही-विशिष्ट नहीं है, बल्कि पूरे तिमाहियों में बड़े उधारकर्ताओं के व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है।

उधारकर्ता की एनपीए स्थिति को अध्ययन के शुरुआती बिंदु के रूप में जानबूझकर लिया जाता है, क्योंकि (ए) यह विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) श्रेणियों के विपरीत डिफॉल्ट तिथि के बाद से उधारकर्ता को 90-दिवसीय अवधि के साथ सबसे खराब संभव आस्ति वर्गीकरण प्रदान करता है;⁶ और (बी) आम तौर पर, बड़े उधारकर्ताओं में एनपीए श्रेणी से बहुत कम या ऊपर की तरफ अवस्थांतर नहीं होता है।⁷

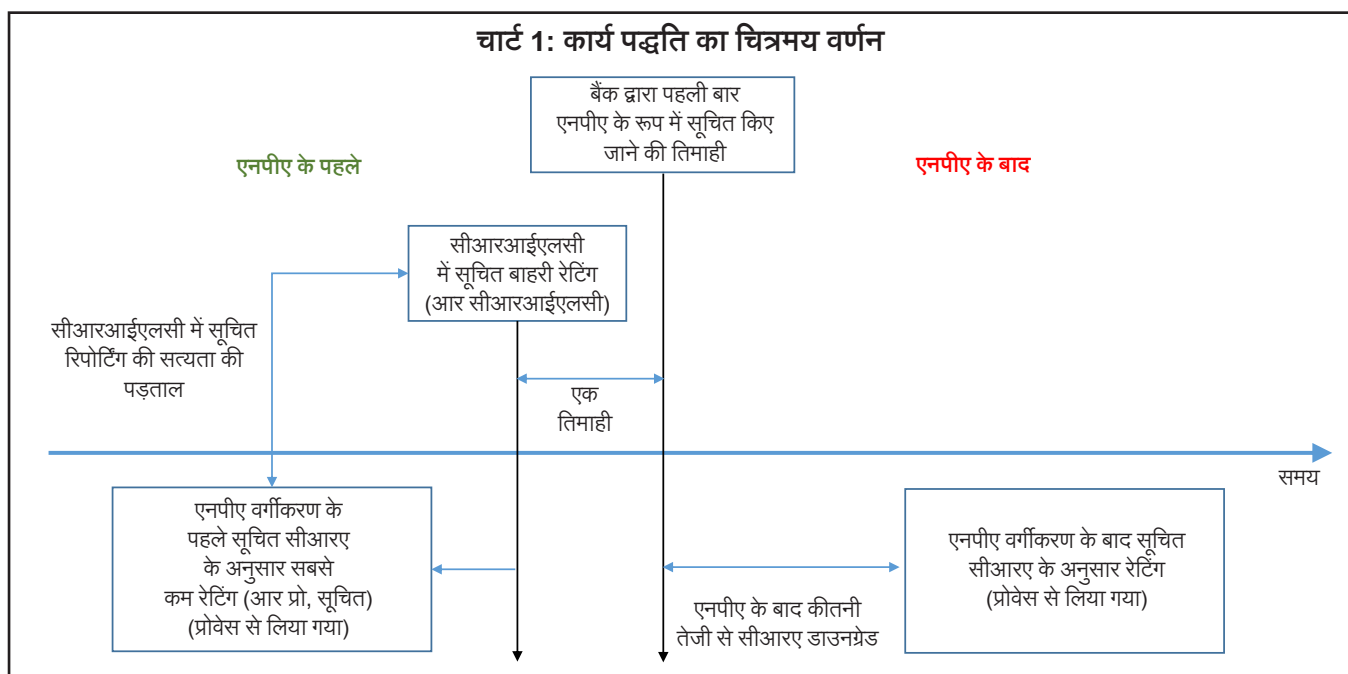
चार्ट 1 में लेख की कार्यपद्धति का वर्णन दिया गया है (विस्तृत चर्चा के साथ अनुलग्नक 1 में)।

III. प्रमुख निष्कर्ष

III.1 आस्ति गुणवत्ता दर्शाने के लिए रेटिंग की क्षमता

यह लेख बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता की पहचान के लिए रेटिंग क्षमता में कमियों को सामने लाता है। सीआरआईएलसी से किए गए लगभग 24 प्रतिशत नमूना एनपीए एक्सपोजर अनर्जक (सारणी 3) बनने से ठिक एक तिमाही पहले निवेश ग्रेड रेटिंग में थे। चूंकि शेयर केवल सीआरआईएलसी से लिया गया था, इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि कमियां या

चार्ट 1: कार्य पद्धति का चित्रमय वर्णन



⁶ एसएमए अर्थात, एसएमए0, एसएमए1 और एसएमए2 के अंतर्गत तीन उप-श्रेणियां हैं, जिसमें मूल या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण और आंशिक रूप से क्रमशः 1 और 30 दिनों, 31 और 60 दिनों, और 61 और 90 दिनों के लिए बकाया है, जिसके बाद आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

⁷ जून 2014 के सीआरआईएलसी डेटा के आधार पर तिमाही तथा वार्षिक औसत एनपीए – एनपीए अवस्थांतर 94 प्रतिशत अनुमानित किया गया।

तो उन तरीकों के कारण हो सकती हैं, जिन्हें सीआरए द्वारा रेटिंग दी जाती है या जिस तरह से बैंकों या दोनों द्वारा रेटिंग बताई जाती है। सीआरआईएलसी को प्रोवेस के साथ मैप करके, यह देखा गया कि लगभग 14 प्रतिशत नमूना एनपीए एक्सपोजर ने प्रोवेस में उप-निवेश ग्रेड दिखाई, लेकिन सीआरआईएलसी में निवेश ग्रेड दिखाई, जिससे सीआरआईएलसी में बैंकों द्वारा देर से रिपोर्टिंग के बारे में संकेत मिलता है (III.3 में विस्तृत चर्चा की गयी है)। विशेष रूप से, सीआरआईएलसी के लगभग 12 प्रतिशत एनपीए एक्सपोजर, प्रोवेस के अनुसार भी, एनपीए बनने से ठीक एक तिमाही पहले, निवेश ग्रेड में थे सीआरए (सारणी 3)⁸ द्वारा दी गई रेटिंग की सीमित प्रभावकारिता दर्शाता है।

III.2 विभिन्न सीआरए के कार्य निष्पादन की तुलना

विभिन्न सीआरए के रेटिंग निष्पादन में मतभेद था। मान्यता प्राप्त सीआरए की तुलना के आधार पर, जैसा कि प्रोवेस में बताया गया है, यह देखा गया है कि आस्ति गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करने वाली रेटिंग के बारे में चिंताएं कुछ सीआरए (सारणी 4)⁹ के लिए अधिक तीव्र थीं। तीन सीआरए के लिए, निवेश ग्रेड में नमूना एनपीए एक्सपोजर का हिस्सा अनर्जक बनने से ठीक एक तिमाही पहले 20 प्रतिशत से अधिक था। इनमें से दो सीआरए के लिए, एनपीए एक्सपोजर का एक बड़ा हिस्सा क्रॉस-ओवर श्रेणियों

सारणी 3: मार्च 2018 के अंत तक एनपीए राशि का वितरण (प्रतिशत)

	आरपीआरओ, सूचित		कुल
	निवेश ग्रेड	उप-निवेश ग्रेड	
निवेश ग्रेड	10.6	13.9	24.4
उप-निवेश ग्रेड	1.5	74.1	75.6
कुल	12.0	88.0	100.0

स्रोत: सीआरआईएलसी और प्रोवेस से आकलित

⁸ उधारकर्ताओं की साख का आकलन करने में सीआरए के लिए आमतौर पर उद्धृत बाधाओं में से एक जानकारी तक उनकी सीमित पहुंच है; अनौपचारिक फर्मों के लिए सूचना बाधा को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण कहा जाता है, जो आम तौर पर भारत में सीआरए की रेटिंग जगत का एक बड़ा हिस्सा है; गोपालन और अन्य (2017) देखें। इसके अलावा, CRILC के माध्यम से एकत्र की गई पर्यवेक्षी जानकारी के विपरीत, जो मुख्य रूप से पोस्ट-डिफॉल्ट (उधारकर्ताओं की एसएमए और एनपीए स्थिति) है, रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपेक्षित जानकारी अनिवार्य रूप से आगे देखने वाली है, जिसका उद्देश्य भावी चूक के बारे में पूर्वानुमान प्रदान करना है।

⁹ वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा 7 सीआरए प्रमाणित किए गए हैं। यह अध्ययन 6 सीआरए पर आधारित है; अंतिम सीआरए 2017 में प्रमाणित किया जाना था लेकिन बहुत ही कम टिप्पणियों के कारण शामिल नहीं किया गया।

सारणी 4: सूचित सीआरए और आरपीआरओ के अनुसार मार्च 2018 के अंत तक एनपीए राशि का वितरण

(प्रतिशत)

सीआरए	सीआरए आरपीआरओ, सूचित		कुल
	निवेश ग्रेड	उप-निवेश ग्रेड	
सीआरए 1	26	74	100
सीआरए 2	9	91	100
सीआरए 3	14	86	100
सीआरए 4	22	78	100
सीआरए 5	5	95	100
सीआरए 6	47	53	100
सभी सीआरए	12	88	100

स्रोत: प्रोवेस से आकलित

(बीबीबी / बीबी) (अनुबंध 2) में केंद्रित था। इसके विपरीत, शेष सीआरए के लिए, प्रमुख एक्सपोजर न्यूनतम संभव ग्रेड (सी / डी श्रेणियों) में केंद्रित था। इस प्रकार, सीआरए के मतभेद, तब और भी स्पष्ट दिखाई दिए जब एक्सपोजर को विभिन्न निवेशों और उप-निवेश ग्रेड रेटिंग श्रेणियों में विभाजित किया गया।

III.3 सीआरए द्वारा दी गई रेटिंग और बैंकों द्वारा सूचित रेटिंग के बीच मतभेद

जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, प्रोवेस में सीआरए द्वारा दी गयी रेटिंग और बैंकों द्वारा रिपोर्ट सीआरआईएलसी में की सूचित की गई रेटिंग में अंतर था। इस मतभेद के संभावित कारणों में से एक यह हो सकता है कि बैंक द्वारा उधारकर्ताओं की केवल उन्हीं सुविधाओं के लिए रेटिंग की रिपोर्ट करता है जिसके लिए बैंक को जोखिम है। हालाँकि, मतभेद दिखाने वाले अधिकांश एक्सपोजर प्रोवेस (अनुबंध 3) के अनुसार सी / डी श्रेणियों तक पहुंच गए थे। चूंकि उधारकर्ता की विभिन्न सुविधाओं के लिए एक ही सीआरए द्वारा दी गई रेटिंग्स आम तौर पर अनुबद्ध होने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता पर आधारित होती हैं, रेटिंग में मतभेद बैंकों की ओर से रिपोर्टिंग मुद्दों के कारण हो सकता है। सबसे पहले, बैंकों द्वारा यादृच्छिक रिपोर्टिंग त्रुटियों की संभावना सीमित लगती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीआरआईएलसी में निवेश ग्रेड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए 14 प्रतिशत एक्सपोजर के मुकाबले जब वह प्रोवेस में सब-इन्वेस्टमेंट ग्रेड में था, तो सीआरआईएलसी में सब-इन्वेस्टमेंट ग्रेड के अंतर्गत केवल 2 प्रतिशत एक्सपोजर ही था जब प्रोवेस में उसका इन्वेस्टमेंट ग्रेड था (सारणी 3)।

दूसरी संभावना बैंकों द्वारा विलंबित रिपोर्टिंग की थी। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, लगभग 74 प्रतिशत एनपीए एक्सपोजर (दोनों में उप-निवेश ग्रेड के तहत रिपोर्ट किया गया) के संबंध में प्रोवेस और सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग के बीच अतिव्याप्ति थी, एक्सपोजर के 14 प्रतिशत के संबंध में मतभेद था, जिसमें सीआरआईएलसी ने प्रोवेस से (सारणी 3) उच्च रेटिंग दिखाई। विलंबित रिपोर्टिंग के मामले का पता लगाने के लिए, प्रोवेस के अनुसार उप-निवेश ग्रेड के उधारकर्ताओं का (सारणी 3 में एनपीए एक्सपोजर के 88 प्रतिशत) एनपीए की तारीख से पहले एक तिमाही पीछे पता लगाया गया जब कम से कम उनकी सुविधाओं में से एक निवेश ग्रेड में थी।¹⁰ रेटिंग श्रेणी में आरपीआओ, अधिकतम रूप में दर्शाया गया है। यह देखा गया कि एनपीए एक्सपोजर के 71 प्रतिशत उधारकर्ताओं के पास पिछले कुछ समय में कम से कम एक सुविधा निवेश ग्रेड में थी (सारणी 5)। एनपीए एक्सपोजर के शेष 17 प्रतिशत उधारकर्ताओं को निवेश ग्रेड में कभी भी कोई सुविधा नहीं थी। केवल उधारकर्ताओं की पूर्व श्रेणी के लिए विलंबित रिपोर्टिंग की संभावना थी। आगे खोज करने के लिए, इस तरह के उधारकर्ताओं की सभी सुविधाएं उप-निवेश श्रेणी में जाने की तिथि का पता लगाया गया और इस तिथि से एनपीए की तारीख तक का औसत समय निकाला गया था (इसे औसत अंतर. उप.निवेश, सकल-एनपीए के रूप में दर्शाया गया)। सीआरआईएलसी में तथा प्रोवेस दोनों में जो उधारकर्ता उप-निवेश ग्रेड में रिपोर्ट किए गए थे, उसी के (सारणी 5 में एनपीए जोखिम के 58 प्रतिशत), औसत अंतर. उप.निवेश, सकल-एनपीए का अनुमान 29 महीने (सारणी 6) था। तुलना के लिए,

सारणी 5: सर्वोत्तम उपलब्ध रेटिंग के संदर्भ में एनपीए राशि का वितरण (मार्च 2018 के अंत में)

		आरपीआओ, अधिकतम		कुल
		निवेश ग्रेड	उप-निवेश ग्रेड	
और सीआरआईएलसी	निवेश ग्रेड	12.8	1.0	13.9
	उप-निवेश ग्रेड	58.4	15.7	74.1
कुल		71.3	16.7	88.0

स्रोत: सीआरआईएलसी और प्रोवेस से आकलित

¹⁰ सितंबर 2010 तक की रेटिंग देखी गयी।

सारणी 6: औसत अंतराल (महीने में)

		औसत अंतर
		उप निवेश, सकल-एनपीए
और सीआरआईएलसी	निवेश ग्रेड	12
	उप-निवेश ग्रेड	29
कुल		25

स्रोत: सीआरआईएलसी और प्रोवेस से आकलित

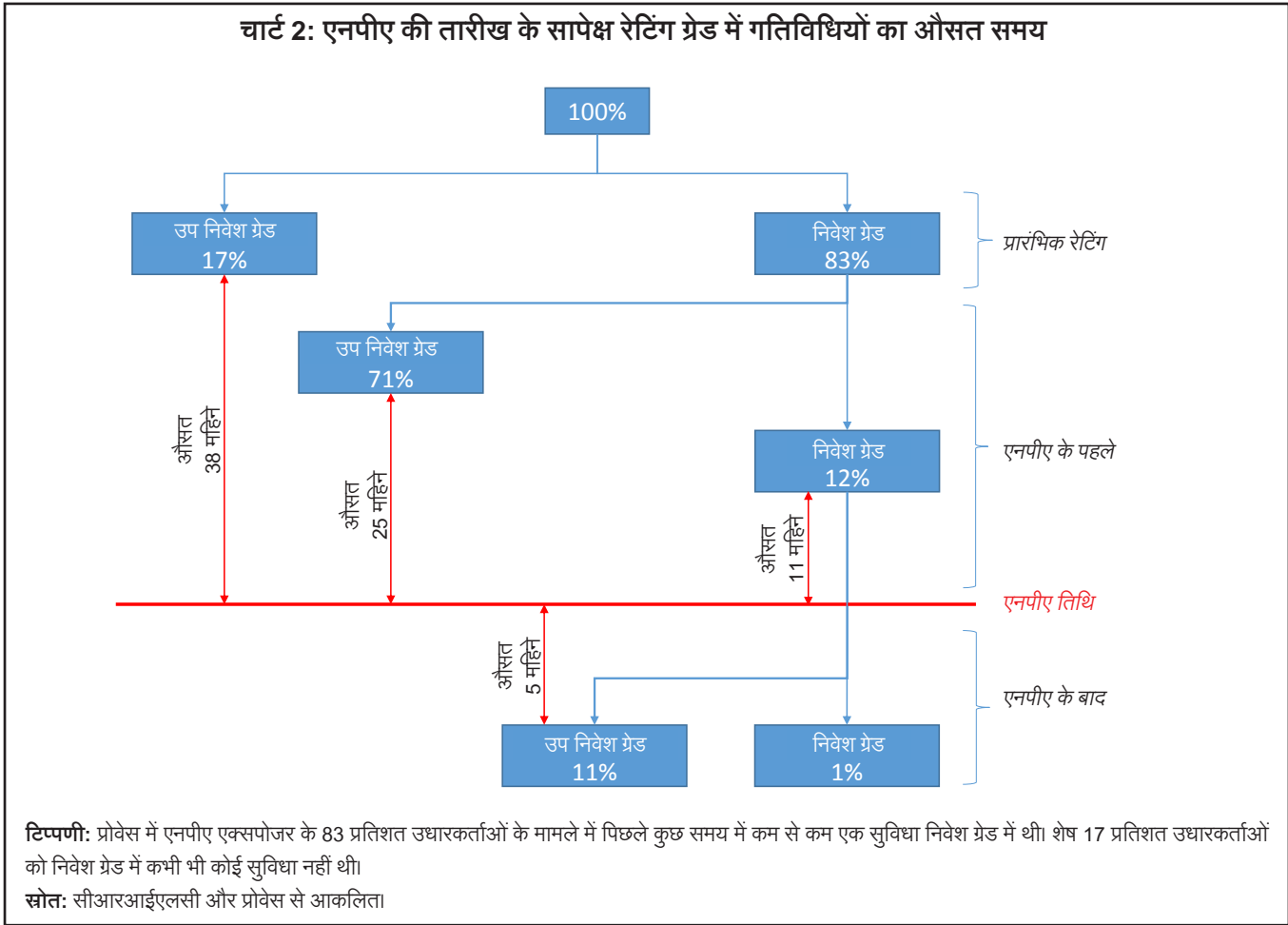
बैंकों द्वारा सीआरआईएलसी निवेश ग्रेड के अंतर्गत सूचित उधारकर्ताओं को प्रोवेस में उप-निवेश ग्रेड में रिपोर्ट किए गए थे, (सारणी 5 में एनपीए एक्सपोजर के लगभग 13 प्रतिशत) यह अंतराल 12 महीने में बहुत कम था, जो यह दर्शाता है कि बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई रेटिंग हाल के रेटिंग परिवर्तनों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती है।

III.4 समय पर आस्ति गुणवत्ता को सही प्रतिबिंबित करने के लिए रेटिंग की क्षमता

यह अनुमान लगाने के लिए कि रेटिंग्स, बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता के बारे में कितने जल्द संकेत देते हैं, एनपीए बनने से पहले उधारकर्ताओं को डाउनग्रेड करने में औसत समय-सीमा का विश्लेषण किया गया था। जैसा कि सारणी 3 और 5 से देखा जा सकता है, एनपीए एक्सपोजर के लगभग 83 प्रतिशत उधारकर्ताओं के पास एनपीए बनने से पहले कुछ समय एक निवेश रेटिंग थी (सारणी 5 से 71.3 प्रतिशत और सारणी 3 से 12.0 प्रतिशत जोड़कर)। इनमें से, 71 प्रतिशत एनपीए एक्सपोजर के उधारकर्ताओं के लिए, बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता (जब एक उधारकर्ता की सभी सुविधाएं उप-निवेश ग्रेड में फिसल जाती है) का संकेत एनपीए की तारीख से औसतन 25 महीने पहले मिला था (चार्ट 2)। शेष 12 प्रतिशत एक्सपोजर उधारकर्ताओं के पास एनपीए की तारीख से 11 महीने पहले भी एक निवेश रेटिंग (उनकी सभी सुविधाओं के लिए) थी। ऐसे उधारकर्ताओं के लिए, अवधि में पूर्ण रूप से डाउनग्रेड (उप-निवेश ग्रेड में सभी सुविधाओं के साथ) के लिए एनपीए के बाद औसत पांच महीने का समय लगा।¹¹

¹¹ मार्च 2018 तक निवेश ग्रेड में रहे लगभग 1 प्रतिशत एनपीए बने रहे। तथापि, इसमें रिपोर्ट न किए गए मामले भी हो सकते हैं।

चार्ट 2: एनपीए की तारीख के सापेक्ष रेटिंग ग्रेड में गतिविधियों का औसत समय



IV. निष्कर्ष

लेख सीआरआईएलसी में सूचित रेटिंग को मैप करके तैयार किए गए अनर्जक उधारकर्ताओं के मूल्यांकन पर आधारित है, जो प्रोवेस में हैं। हालांकि प्रारंभिक, निष्कर्ष बताते हैं: (ए) रेटिंग हमेशा उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता को समय पर सही प्रतिबिंबित नहीं करती हैं; (बी) बैंकों द्वारा देरी से रेटिंग सूचित की जाती हैं; (सी) रेटिंग एजेंसियों में आस्ति गुणवत्ता देखने के रेटिंग्स की क्षमता भिन्न होती है। हालांकि मौजूदा नियामक ढांचे के तहत एजेंसी रेटिंग का उपयोग अपरिहार्य है, सीआरए द्वारा अपनी रेटिंग प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के तरीकों का पता लगाने की जरूरत है।¹²

¹² इस संदर्भ में चौधरी और अन्य (2017) ने सीआरए को भिन्न जोखिम भार देने पर चर्चा की है।

संदर्भ:

- Balin, B. (2010), "Basel I, Basel II, and Emerging Markets: A Nontechnical Analysis", *Working Paper, Accessed from SSRN 1477712*, 2008.
- BCBS (2017), "High-level Summary of Basel III Reforms", BIS.
- Beattie, V. and S. Searle (1992), "Bond Ratings and Inter-Rater Agreement: A Cross-Sectional Analysis", *Journal of International Securities Markets*, 6 (2).
- Cantor, R. and F. Packer (1997), "Differences of Opinion in the Credit Rating Industry", *Journal of Banking and Finance*, 21(10).
- Choudhary A. K., B. Nethaji and A. Basu (2017): "Risk-weighting under Standardised Approach of Computation

of Capital for Credit Risk in Basel Framework – An Analysis of Default Experience of Credit Rating Agencies in India”, *Reserve Bank Working Paper* 06/2017.

Ederington, L.H. (1986), "Why Split Ratings Occur?", *Financial Management*, 15 (1).

Study Report (2009), "Assessment of Long Term Performance of Credit Rating Agencies in India", *National Institute of Securities Markets*.

Gopalan, R., Y. Gopalan, and K. Koharki, (2016), "Market Information and Rating Agency Catering", *CAFRAL Working Paper*.

Roy, P. V. (2005), "Credit Ratings and the Standardised Approach to Credit Risk in Basel III", *ECB working paper* 517/August 2005.

Sinclair, T. J. (2010), "Credit Rating Agencies and the Global Financial Crisis", *economic sociology_the european electronic newsletter*, ISSN 1871-3351, *Max Planck Institute for the Study of Societies (MPIfG)*, Cologne, Vol. 12, Iss. 1, pp. 4-9

अनुबंध:**अनुबंध 1: कार्य पद्धति का विवरण**

लेख के लिए डेटा का विश्लेषण निम्नलिखित तरीके से किया गया था:

1. शुरुआती बिंदु के रूप में, मार्च 2018 के अंत में एनपीए उधारकर्ताओं जिनके लिए सीआरआईएलसी में सीआईएन रिपोर्ट किए गए थे, को चुना गया था। कॉरपोरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) डेटाबेस के साथ सीआईएन को सत्यापित करते हुए, केवल मान्य सीआईएन के उधारकर्ताओं को शामिल करने के लिए और जिस पर प्रोवेस में जानकारी उपलब्ध थी, और अधिक छंटाई की गयी थी।
2. एनपीए उधारकर्ताओं की छंटनी सूची के लिए सीआरआईएलसी से रेटिंग वितरण प्राप्त किया गया था। शून्य वर्गीकरण से ठीक पहले की रेटिंग सीआरआईएलसी से प्राप्त की गई थी। यहां, एनपीए वर्गीकरण तारीख जब उधारकर्ता को रिपोर्टिंग बैंक में पहली बार एनपीए श्रेणी में

रिपोर्ट किया गया था की तारीख थी।¹³ एनपीए की तारीख से पहले की तिमाही में रिपोर्ट की गई रेटिंग ली गई थी इसलिए सीआरआईएलसी से रेटिंग ली गई।

3. इसी तरह, सीआरए के लिए प्रोवेस (जैसा कि सीआरआईएलसी में सूचित किया गया है) में एनपीए की तारीख से पहले की तिमाही में नवीनतम सबसे कम रेटिंग को चुना गया था। जैसा कि प्रोवेस सुविधाओं के अनुसार रेटिंग प्रदान करता है, उधारकर्ता की सुविधाओं में सूचित सीआरए के अनुसार सबसे कम रेटिंग सीआरआईएलसी में रिपोर्टिंग के साथ अनुरूपता के लिए चुनी गई थी।
4. चूंकि, प्रोवेस में शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों तरह की सुविधाओं के लिए रेटिंग्स शामिल हैं, रेटिंग्स को एक सामान्य पैमाने पर मैप किया गया था, जिसका उपयोग तुलनात्मकता के लिए सीआरआईएलसी में किया गया था।

¹³ मार्च 2018 तक सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग तिमाही आधार पर थी, एनपीए वर्गीकरण की तिथि तिमाही का अंतिम दिन लिया गया जब उधारकर्ता पहली बार एनपीए के रूप में सूचित किया गया।

अनुबंध 2: मार्च 2018 के अंत तक एनपीए राशि का वितरण

(प्रतिशत)

		आरपीआरओ, सूचित								कुल
		एएए	एए	ए	बीबीबी	बीबी	बी	सी	डी	
सीआरआईएलसी में रिपोर्टेड सीआरए	सीआरए1	-	-	13.1	12.4	17.3	1.9	44.7	10.6	100.0
	सीआरए2	-	-	0.8	7.9	7.0	1.8	19.8	62.7	100.0
	सीआरए3	-	-	3.8	10.4	0.9	2.4	15.2	67.4	100.0
	सीआरए4	-	-	5.2	16.6	3.0	0.2	12.3	62.8	100.0
	सीआरए5	-	-	0.0	4.7	1.1	0.6	8.2	85.5	100.0
	सीआरए6	-	-	13.5	33.8	19.0	3.8	6.7	23.1	100.0
कुल		-	-	2.8	9.2	6.9	1.6	20.4	59.1	100.0

स्रोत: सीआरआईएलसी और प्रोवेस से आकलित

- शून्य / नगण्य:

अनुबंध 3: मार्च 2018 के अंत तक एनपीए की राशि का वितरण

(प्रतिशत)

		आरपीआरओ, सूचित								कुल
		एएए	एए	ए	बीबीबी	बीबी	बी	सी	डी	
आर सीआरआईएलसी	एएए	-	-	0.2	0.1	-	-	0.2	1.9	2.3
	एए	-	-	0.1	0.2	-	-	0.1	0.3	0.7
	ए	-	-	2.3	0.4	0.4	-	0.7	2.4	6.1
	बीबीबी	-	-	0.2	7.1	0.5	-	1.9	5.6	15.3
	बीबी	-	-	0.1	1.2	5.7	0.4	12.8	6.4	26.6
	बी	-	-	-	0.2	0.1	1.1	1.9	3.0	6.3
	सी	-	-	-	-	-	-	1.4	0.7	2.1
	डी	-	-	-	-	0.2	0.1	1.5	38.9	40.6
कुल		-	-	-	9.2	6.9	1.6	20.4	59.1	100.0

स्रोत: सीआरआईएलसी और प्रोवेस से आकलित

- शून्य / नगण्य:

वर्किंग पेपर की प्रेस प्रकाशनियां

अमेरिका से भारतीय बाजारों में टर्म प्रीमियम स्पिलओवर
सी-डाइवर्जेंस पर आधारित रोबस्ट वाल्ड-टाइप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स

अमेरिका से भारतीय बाजारों में टर्म प्रीमियम स्पिलओवर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अपनी वेबसाइट पर भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर सीरीज़ के अंतर्गत “अमेरिका से भारतीय बाजारों में टर्म प्रीमियम स्पिलओवर” नामक एक वर्किंग पेपर रखा। इस पेपर की लेखिका अर्चना दिलीप है।

यह पेपर भारत में टर्म प्रीमियम का अनुमान लगाता है और विश्लेषण करता है तथा भारत की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रिक बांड आय की परस्पर संबद्धता और अमेरिकी टर्म संरचना से झटके का प्रसारण का आकलन करता है। टर्म प्रीमियम का अनुमान आय का दो घटकों में विघटन कर किया जाता है - जोखिम-तटस्थ

दर जो भावी अल्पकालिक दरों की अपेक्षाओं को दर्शाता है; और टर्म प्रीमियम भावी केंद्रीय बैंक नीति, मुद्रास्फीति और वृद्धि के झटके से निवेशकों की अपेक्षाओं की खोज करता है। भारत में टर्म प्रीमियम को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारकों के रूप में इस पेपर ने मुद्रास्फीति की अस्थिरता और मौद्रिक नीति अनिश्चितता की पहचान की है। इसके अलावा, अनुभवजन्य निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि अप्रैल 2009 से अप्रैल 2019 तक नमूना अवधि के दौरान भारत में अमेरिकी ट्रेजरी आय और सरकारी प्रतिभूति आय के बीच स्पिलओवर में वृद्धि हुई है। यह पेपर वित्तीय एकीकरण में वृद्धि और अस्थिर बांड बाजार के साथ मजबूत स्पिलओवर पाता है। पेपर में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि दीर्घकालिक आय के लिए, टर्म प्रीमियम चैनल जोखिम-तटस्थ दर चैनल की तुलना में एक मजबूत प्रसारण चैनल है।

सी-डाइवर्जेस पर आधारित रोबस्ट वाल्ड-टाइप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स

भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर सीरीज़ के अंतर्गत आज भारतीय रिज़र्व बैंक ने “ सी-डाइवर्जेस पर आधारित रोबस्ट वाल्ड-टाइप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स “ नामक वर्किंग पेपर वेबसाइट पर रखा गया है। इस पेपर के लेखक अविजित माजी और लिण्ड्रो पार्डो हैं।

सी-डाइवर्जेस अनुमानों में एक कमी यह है कि सामान्य रूप से उनका एसिम्प्टोटिक वितरण, ची-स्क्वेयर वितरण नहीं है, बल्कि ची-स्क्वेयर वितरण का एक रेखीय संयोजन है। इस कमी को दूर करने के लिए इस पेपर में न्यूनतम सी-डाइवर्जेस अनुमानों के आधार पर वाल्ड-टाइप टेस्ट के आंकड़ों का प्रस्ताव है। यह आगे स्थापित करता है कि परीक्षण के आंकड़ों का यह परिवार एक ची-स्क्वेयर वितरण है और सरल शून्य परिकल्पना और यौगिक शून्य परिकल्पना के तहत क्षमता फलन का अनुमान करता है।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी खाते और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक श्रृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिदा आर्थिक संकेतक भारतीय रिज़र्व बैंक	51
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	52
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	53
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय/विक्रय	54
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	55
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं मुद्रा और बैंकिंग	55
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	56
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	57
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	58
9	कुल चलनिधि राशियां	58
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	59
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	59
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	60
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	60
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	61
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	62
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	63
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक मूल्य और उत्पादन	64
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	65
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	65
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	65
21	थोक मूल्य सूचकांक	66
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100) सरकारी खाते और खज़ाना बिल	69
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	69
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	70
25	खज़ाना बिलों की नीलामी वित्तीय बाजार	70
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	71
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	72
28	वाणिज्यिक पत्र	72
29	चुनिदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	72
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	73

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	74
32	विदेशी मुद्रा भंडार	74
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	74
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	75
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	75
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	76
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	76
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरिकी डॉलर)	77
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	78
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	79
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	81
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	82
	प्रासंगिक शृंखला	
44	लघु बचत	84
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	85
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	86
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	87
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	88
49	राज्य सरकारों की बाजार उधारियां	89

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2018-19		2019-20	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.6	7.7	6.9	4.9	4.3
1.1.1 कृषि	2.9	5.1	4.9	2.0	2.1
1.1.2 उद्योग	6.2	9.9	6.1	1.7	-0.5
1.1.3 सेवाएं	7.7	7.5	7.5	6.7	6.4
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.3	7.2	10.0	4.1	6.9
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	10.0	13.3	11.8	4.0	1.0
	2018-19	2018		2019	
		अक्टूबर	नवंबर	अक्टूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	3.80	8.4	0.2	-3.8	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	9.0	10.8	10.3	9.5
2.1.2 ऋण	13.3	14.6	16.2	8.9	7.2
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.4	14.8	16.3	8.8	7.2
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.9	3.2	2.0	7.0	8.6
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	17.4	18.9	15.3	12.4
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.5	10.0	10.4	10.6	9.8
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.50	19.50	18.50	18.50
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.7	4.8	4.9	4.8
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	76.7	77.1	75.8	75.5
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.9	118.3	111.6	17.0	22.5
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	29.2	28.5	28.3	28.3
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.4	34.0	17.8	73.3	62.4
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.50	6.50	5.15	5.15
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	6.25	6.25	4.90	4.90
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.75	6.75	5.40	5.40
4.4 बैंक दर	6.50	6.75	6.75	5.40	5.40
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.85/9.45	8.95/9.45	8.95/9.40	8.95/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	8.05/8.40	8.15/8.45	7.70/8.20	7.65/8.10
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.25/7.25	6.25/7.50	6.25/6.85	6.25/6.60
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.25/3.50	3.25/3.50
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	6.50	6.39	5.07	5.03
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	6.94	6.77	5.04	4.99
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	7.23	7.06	5.21	5.12
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	7.48	7.22	5.30	5.14
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	7.84	7.64	6.54	6.65
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	73.37	69.66	70.96	71.73
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	83.41	79.36	78.81	78.98
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरिकी डालर					
1-माह (%)	6.07	4.58	4.31	3.38	3.35
3-माह (%)	4.80	4.36	4.02	3.61	3.35
6-माह (%)	4.16	4.33	4.13	3.99	3.76
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	3.4	3.4	2.3	4.6	5.5
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	5.2	4.9	7.6	8.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	4.3	5.5	4.5	0.2	0.6
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	2.7	2.5	0.6	6.4	7.7
6.3.2 ईंधन और पावर	11.5	18.7	15.5	-8.3	-7.3
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	3.7	4.6	4.2	-0.8	-0.8
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	10.4	19.1	5.5	-16.3	-12.7
7.2 निर्यात	8.7	16.5	-0.8	-0.9	-0.3

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2018	2019				
			दिसंबर	नवंबर 29	दिसंबर 6	दिसंबर 13	दिसंबर 20
1	2	3	4	5	6	7	
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2113764	1999241	2230697	2248925	2258713	2245888	2244106
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	13	12	12	10	12	12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2113775	1999254	2230709	2248937	2258723	2245900	2244118
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	79481	71943	88261	89063	87939	88812	89990
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2033559	1926484	2141628	2159063	2169991	2156312	2153365
1.2.3 रुपया सिक्का	735	827	820	811	793	776	763
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	806012	705087	896950	931817	909371	894034	913132
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	100	100	100	101	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	43	42	43	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	565707	533173	542975	540118	530600	562488	541417
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4197	3442	4657	4643	4406	6867	6593
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3494	2142	2784	2844	2761	2886	2698
2.1.1.7 अन्य बैंक	32036	28612	31479	30755	31155	31461	31221
2.1.1.8 अन्य	199734	137575	313483	353313	340307	290189	331060
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	700		1430				
2.1.2 अन्य देयताएं	1087686	1055947	1135150	1133173	1116870	1124290	1145007
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	1893698	1761034	2032100	2064990	2026242	2018324	2058139
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	13	12	12	10	12	12
2.2.2 विदेश में रखे शेष	646640	674899	891144	870635	846361	873823	903533
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	52575	31003	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	10	762	1261	9072	10609	1256	2112
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	180688	188109	23012	14725	21493	25746	30427
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	13463	5971	4913	4930	4433	4744	4479
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	700						
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	923080	807078	1003900	1004017	1003981	1002796	1005802
2.2.6 अन्य आस्तियां	129106	84202	107858	109024	108352	109947	111774
2.2.6.1 सोना	87169	75911	102903	104123	103090	104113	105494

* डाटा अन्तिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिपो दर				विक्रय	क्रय	
नव. 1, 2019	3552	18338	1825	274978	4030	-134	-	-	-	-284043
नव. 2, 2019	64	25168	-	-	2825	-	-	-	-	-22279
नव. 4, 2019	4052	23971	-	287005	4210	-	-	-	-	-302714
नव. 5, 2019	4082	16543	8175	247322	3612	-	-	-	-	-247996
नव. 6, 2019	3722	19341	-	220358	5250	-	-	-	-	-230727
नव. 7, 2019	3652	19475	-	225197	3265	-	-	10	10	-237755
नव. 8, 2019	3737	33712	8200	186171	5026	-	-	-	-	-202920
नव. 11, 2019	3647	17637	100	181134	3742	-	-	-	-	-191282
नव. 12, 2019	-	5132	-	-	850	-	-	-	-	-4282
नव. 13, 2019	6052	14843	-	196152	3600	-396	-	-	-	-201739
नव. 14, 2019	3727	13193	-	207015	3614	426	-	10	235	-212216
नव. 15, 2019	5627	14371	1300	191761	3575	-	-	-	765	-194865
नव. 16, 2019	4800	12968	-	-	1	-	-	-	-	-8167
नव. 18, 2019	4527	12853	-	178928	3850	-	-	-	595	-182809
नव. 19, 2019	3667	12984	10150	163670	5775	-176	-	-	675	-156563
नव. 20, 2019	4068	19174	-	137238	4196	-190	-	-	645	-147693
नव. 21, 2019	3667	11556	-	124981	3500	190	-	-	710	-128470
नव. 22, 2019	3667	36609	9375	122437	3231	-	-	-	665	-142108
नव. 25, 2019	3967	16228	-	134136	3652	-	-	-	575	-142170
नव. 26, 2019	3692	14021	100	153166	3950	-	-	-	675	-158770
नव. 27, 2019	3467	22350	-	146927	3915	-	-	-	970	-160925
नव. 28, 2019	3537	13549	-	170024	3330	-645	-	970	805	-177516
नव. 29, 2019	3522	20484	175	170949	3212	432	-	700	915	-183877
नव. 30, 2019	-	47201	-	-	5075	-	-	-	-	-42126

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डालर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		नवंबर	अक्तूबर	नवंबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	-15377	-644	7102	6928
1.1 क्रय (+)	40804	3127	7302	7458
1.2 विक्रय (-)	56181	3771	200	530
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	-111946	-5562	50257	49142
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरिकी डालर)	-15377	-26510	18453	25381
(करोड़ ₹)	-111945	-188087	125266	174408
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	-13774	-1924	-7473	-6143

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2018-19	2018	2019	
		नवंबर	अक्तूबर	नवंबर
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डालर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	13935	51	0	0
1.2 विक्रय (-)	13935	51	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डालर)	0	0	0	0

**सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)**

मद	30 नवंबर 2019 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	805	755	50
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	2625	2580	45
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	5367	1705	3662
4. 1 वर्ष से अधिक	120	10020	-9900
कुल (1+2+3+4)	8917	15060	-6143

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2018	2019					नवंबर 22	दिसंबर 20
			दिसंबर 21	जुलाई 19	अगस्त 30	सितंबर 27	अक्तूबर 25		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1 सीमांत स्थायी सुविधा	12882	3205	1151	55	48	4373	3231	3856	
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त									
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा									
3.1 सीमा	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
3.2 बकाया	2678	2082	2356	1879	2372	1884	1604	1615	
4 अन्य									
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	15560	5287	3507	1934	2420	6257	4835	5471	

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2018	2019		
		नवंबर 23	अक्टूबर 25	नवंबर 8	नवंबर 22
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2052209	1924446	2161881	2176171	2172488
1.1 संचलन में नोट	2110883	1985008	2231090	2245619	2241262
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25144	24954	25302	25380	25380
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	84561	86259	95254	95571	94897
2 जनता की जमाराशियां	1658254	1364028	1508717	1473693	1480272
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1626512	1338265	1477505	1441821	1447960
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	25763	31212	31872	32312
3 एम₁ (1 + 2)	3710464	3288474	3670598	3649864	3652760
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	140599	127270	138437	138437	138437
5 एम₂ (3 + 4)	3851063	3415744	3809035	3788301	3791197
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	11721603	11230301	12284764	12339740	12292989
7 एम₃ (3 + 6)	15432067	14518775	15955362	15989604	15945749
8 कुल डाकघर जमाराशियां	367287	342354	395361	395361	395361
9 एम₄ (7 + 8)	15799354	14861129	16350723	16384965	16341110

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		नवंबर 23	अक्टूबर 25	नवंबर 8	नवंबर 22
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4388490	4344589	4852157	4969808	4890841
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	801951	712721	966959	1010459	965438
1.1.1 सरकार पर दावे	929686	725156	993464	1010601	1001006
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	928166	725156	992794	1002178	1000408
1.1.1.2 राज्य सरकारें	1520	0	670	8423	598
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियां	127735	12435	26505	142	35568
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	127693	12393	26462	100	35526
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	43	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3586539	3631868	3885198	3959349	3925403
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	10382719	9724300	10457195	10463189	10468270
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	15363	9318	7680	7350	7144
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	10367356	9714982	10449515	10455839	10461126
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	9771722	9132626	9840562	9846375	9860303
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	585931	573778	592379	592426	588692
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	9703	8577	16574	17038	12132
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3070841	2929711	3338248	3386930	3418513
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	2848587	2797517	3126960	3175642	3207225
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	2848800	2797747	3127169	3175851	3207434
3.1.2 विदेशी देयताएं	213	230	209	209	209
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	222254	132194	211288	211288	211288
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25697	26045	26123	26123
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2435870	2505523	2718283	2856446	2857998
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1058795	1089968	1094490	1105571	1137091
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1377075	1415555	1623793	1750875	1720907
एम₃ (1+2+3+4-5)	15432067	14518775	15955362	15989604	15945749

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
		नवंबर 23	अक्टूबर 25	नवंबर 8	नवंबर 22
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	3710464	3288474	3670598	3649864	3652760
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	8911512	8272950	9117554	9122216	9103488
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	15646602	14714082	16111023	16139478	16087659
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2052209	1924446	2161881	2176171	2172488
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	13184397	12414878	13581853	13602605	13560689
1.2.1 मांग जमाराशियां	1626512	1338265	1477505	1441821	1447960
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11557885	11076613	12104348	12160784	12112729
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5201048	4984476	5446957	5472353	5450728
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	168704	167104	167474	158123
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6356837	6092137	6657391	6688431	6662001
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	31742	25763	31212	31872	32312
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	378254	348995	336077	328830	322170
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	15659336	14898754	16210358	16320289	16251859
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4388490	4344589	4852157	4969808	4890841
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	801951	712721	966959	1010459	965438
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3586539	3631868	3885198	3959349	3925403
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11270846	10554164	11358201	11350481	11361017
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	15363	9318	7680	7350	7144
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11255483	10544846	11350521	11343131	11353873
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	879849	818761	892285	878468	883989
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25697	26045	26123	26123
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2801726	2690076	3046312	3086167	3141351
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2797517	3126960	3175642	3207225
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-46861	-107441	-80647	-89475	-65874
2.4 पूंजी खाता	2346743	2351618	2440799	2446150	2482957
2.5 अन्य मदें (निवल)	493605	548826	730894	846951	848715

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2018-19	2018		2019	
		नवंबर	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	15646602	14714082	15976308	16111023	16087659
2 डाकघर जमाराशियां	367287	342354	390764	395361	395361
3 एल₁ (1 + 2)	16013889	15056436	16367072	16506384	16483020
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	2932	2932	2932	2932	2932
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2656	2656	2656	2656	2656
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	31	31	31	31	31
4.3 सावधि जमाराशियां	245	245	245	245	245
5 एल₂ (3 + 4)	16016821	15059368	16370004	16509316	16485952
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	..	31905
7 एल₃ (5 + 6)	16048726	..	16401909

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018		2019	
		नवंबर 23	अक्टूबर 25	नवंबर 8	नवंबर 22
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	2010705	2257135	2271742	2267385
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमा राशियां	601969	510355	587853	564056	555408
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	558496	476573	548240	525365	517462
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	31742	25763	31212	31872	32312
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	2770481	2546823	2876200	2867669	2855104
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	954802	813577	817685	771476	758848
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	801951	712721	966959	1010459	965438
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	800473	712763	966332	1002078	964882
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	6360	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	927427	724311	992089	995155	999581
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	927427	724311	992089	995155	999581
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	739	845	705	663	827
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमा राशियां	127693	12393	26462	100	35526
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1478	-42	627	8381	556
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	137488	91538	-156954	-246333	-213734
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	137488	91538	-156954	-246368	-213734
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	15363	9318	7680	7350	7144
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	2678	2120	1884	1750	1604
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25697	26045	26123	26123
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2797517	3126960	3175642	3207225
2.3.1 सोना	159585	155356	191868	191683	192307
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2689019	2642179	2935109	2983976	3014935
2.4 पूंजी खाता	970265	1048846	982299	991010	1012649
2.5 अन्य मदें (निवल)	88530	41122	112191	114561	124442

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
		2018		2019				
		नवंबर 30	अक्टूबर 25	नवंबर 1	नवंबर 8	नवंबर 15	नवंबर 22	नवंबर 29
		1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	2770481	2556873	2876200	2867866	2867669	2876404	2855104	2874296
1 घटक								
1.1 संचलन में मुद्रा	2136770	1995899	2257135	2257789	2271742	2269253	2267385	2256875
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमा राशियां	601969	535315	587853	578304	564056	575770	555408	581895
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियां	31742	25659	31212	31774	31872	31382	32312	35526
2 स्रोत								
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	801951	785769	966959	1061602	1010459	1030442	965438	1001249
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	137488	38967	-156954	-271081	-246333	-257808	-213734	-247355
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	15363	8978	7680	7266	7350	7381	7144	6877
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	2848587	2738645	3126960	3149078	3175642	3208493	3207225	3222285
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	25887	25786	26045	26123	26123	26123	26123	26178
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1058795	1041272	1094490	1105121	1105571	1138226	1137091	1134938

सं. 12: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		नवंबर 23	अक्टूबर 25	नवंबर 8	नवंबर 22
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	12410053	11659886	12797668	12819022	12778214
1.1.1 मांग जमाराशियां	1511287	1225962	1361293	1325364	1331740
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	10898766	10433924	11436375	11493658	11446474
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	4904445	4695266	5146369	5172146	5150913
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	284993	168704	167104	167474	158123
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	5994321	5738658	6290006	6321512	6295561
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	378254	348995	336077	328830	322170
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14032206	13379952	14416362	14482918	14463919
2.1.1 सरकार को ऋण	3379001	3425087	3675526	3749372	3715868
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	10653205	9954865	10740836	10733546	10748051
2.1.2.1 बैंक ऋण	9771722	9132626	9840562	9846375	9860303
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	9730112	9060338	9770784	9766327	9768999
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	8542	11366	8984	9087	9021
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2055	1074	7967	8578	3700
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	870886	809799	883322	869505	875027
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-46861	-107441	-80647	-89475	-65874
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	262383	178454	229900	212882	236374
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	163719	153688	180416	178956	180260
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	145526	132207	130131	123401	121989
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	538104	461277	790274	857349	816180
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	565707	476573	548240	525365	517462
2.3.2 उपलब्ध नकदी	74877	76242	85079	85616	84984
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	102480	91538	-156954	-246368	-213734
2.4 पूंजी खाता	1352307	1278601	1434329	1430969	1446137
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	382835	446305	557914	671970	667703
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	398120	381271	380921	378302	385783
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	-47846	-50688	-42589	-45560	-45368

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 29, 2019 की स्थिति	2018	2019		
		नवंबर 23	अक्टूबर 25	नवंबर 8	नवंबर 22
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3381056	3426161	3683493	3757950	3719568
2 वाणिज्यिक पत्र	90362	107691	97516	98336	99328
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	11535	11704	11329	11649	11286
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	69592	73111	65652	65705	66368
3.3 अन्य	6379	6204	5519	6608	5515
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	134819	125515	124883	121110	112750
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	268783	226837	242931	234082	228685
4.3 अन्य	170047	126739	177860	157052	151689
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	20988	47067	56587	46164	48279
5.2 वित्तीय संस्थाएं	98382	84929	83313	81074	80912

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2018-19	2018	2019		2018-19	2018	2019	
		नवंबर	अक्टूबर	नवंबर		नवंबर	अक्टूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	222	223	219	219	147	149	142	142
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	276350	235717	260623	249308	271426	230970	255643	244433
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	181651	155215	188936	187449	176828	150918	184140	182731
1.2 बैंकों से उधार राशि	79487	67079	59888	49892	79459	66743	59827	49866
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15212	13423	11799	11967	15139	13308	11675	11836
2 अन्य के प्रति देयताएं	13835976	13136667	14184753	14313828	13495672	12820847	13825214	13953219
2.1 कुल जमाराशियां	12901579	12262530	13324129	13446605	12573772	11960292	12978084	13098829
2.1.1 मांग	1542554	1320483	1392881	1448495	1511287	1292922	1361293	1416506
2.1.2 मीयादी	11359025	10942048	11931247	11998110	11062484	10667370	11616791	11682323
2.2 उधार	381864	357202	339832	335572	378254	352993	336077	331841
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	552533	516934	520792	531652	543646	507562	511052	522549
3 रिजर्व बैंक से उधार	180688	113296	22273	23012	180688	113296	22273	23012
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	180688	113296	22273	23012	180688	113296	22273	23012
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	657555	592003	649788	642083	640584	577876	633319	626158
4.1 उपलब्ध नकदी	76554	77982	87248	85087	74877	76097	85079	83184
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	581001	514021	562540	556997	565707	501779	548240	542975
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	372670	320972	359754	261524	327814	284678	307216	207281
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	245880	219629	261933	168777	223048	202260	236433	142276
5.1.1 चालू खाते में	17216	11969	16691	14492	13329	9310	14136	12215
5.1.2 अन्य खातों में	228663	207660	245242	154285	209719	192950	222297	130062
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	47047	38481	27172	23341	32252	23427	11047	7015
5.3 बैंकों को अग्रिम	32950	32233	28927	28990	29635	32150	25437	24968
5.4 अन्य आस्तियां	46793	30629	41722	40416	42879	26841	34298	33022
6 निवेश	3475607	3507114	3781133	3814593	3381056	3413749	3683493	3716854
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3467845	3500267	3766764	3797574	3379001	3412693	3675526	3706537
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7762	6847	14368	17019	2055	1056	7967	10317
7 बैंक ऋण	10047125	9603936	10127275	10175315	9771722	9221898	9840562	9890071
7क खाद्यान्न ऋण	64636	102857	96809	117556	41610	79830	69778	90526
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	9792287	9384771	9917389	9968155	9521994	9007305	9634456	9686695
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	27641	20849	26014	24641	26223	19510	24720	23902
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	160984	139734	126797	126309	158296	137357	125199	124288
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	24914	23717	24353	23182	24588	23430	24071	22762
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	41299	34864	32723	33028	40622	34296	32117	32424

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			नवंबर 23	अक्तूबर 25		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	8674892	8165199	8733112	8764913	1.0	7.3
1.1 खाद्यान्न ऋण	41474	72060	69555	91005	119.4	26.3
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	8633418	8093139	8663557	8673908	0.5	7.2
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1111300	1064753	1134705	1134004	2.0	6.5
1.2.2 उद्योग	2885778	2708395	2786751	2772248	-3.9	2.4
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	375505	362976	359018	362758	-3.4	-0.1
1.2.2.2 मझौले	106395	105113	105558	102601	-3.6	-2.4
1.2.2.3 बड़े	2403878	2240306	2322175	2306889	-4.0	3.0
1.2.3 सेवाएं	2415609	2253815	2352418	2362956	-2.2	4.8
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	138524	129229	139103	139754	0.9	8.1
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	18535	19126	19063	19052	2.8	-0.4
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	39005	38437	43399	43468	11.4	13.1
1.2.3.4 नौवहन	7748	6377	5893	6704	-13.5	5.1
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	171517	168471	169783	170660	-0.5	1.3
1.2.3.6 व्यापार	528158	479515	505037	501677	-5.0	4.6
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	250528	211595	218722	217567	-13.2	2.8
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	277630	267920	286315	284109	2.3	6.0
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	202291	187665	220300	220685	9.1	17.6
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	641208	566312	713344	730907	14.0	29.1
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	668623	658683	536499	530048	-20.7	-19.5
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2220732	2066176	2389684	2404701	8.3	16.4
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	6299	3274	5557	5499	-12.7	68.0
1.2.4.2 आवास	1160111	1077416	1268734	1274747	9.9	18.3
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	82873	68160	62902	62892	-24.1	-7.7
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	6265	5969	5056	4982	-20.5	-16.5
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	88262	85278	105026	105860	19.9	24.1
1.2.4.6 शिक्षा	67988	69190	67238	66902	-1.6	-3.3
1.2.4.7 वाहन ऋण	202154	198707	206720	207996	2.9	4.7
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	606780	558182	668451	675823	11.4	21.1
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2739021	2604065	2766084	2694733	-1.6	3.5
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1104988	1058673	1125522	1125474	1.9	6.3
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1067175	995653	1053403	1057378	-0.9	6.2
1.2अ.2.1 विनिर्माण	375505	362976	359018	362758	-3.4	-0.1
1.2अ.2.2 सेवाएं	691670	632677	694385	694620	0.4	9.8
1.2अ.3 आवास	432703	404312	455536	454000	4.9	12.3
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	24101	23005	32525	33526	39.1	45.7
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	53950	56835	53736	53410	-1.0	-6.0
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	397	341	397	387	-2.5	13.5
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	662628	598556	704413	698449	5.4	16.7
1.2अ.8 निर्यात ऋण	15566	18529	14040	13219	-15.1	-28.7

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 29, 2019	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			नवंबर 23	अक्तूबर 25		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	2885778	2708395	2786751	2772248	-3.9	2.4
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	41752	42992	41176	41372	-0.9	-3.8
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	157058	140744	139693	136930	-12.8	-2.7
1.2.1 चीनी	29705	23898	25914	24624	-17.1	3.0
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	21343	20788	17681	17430	-18.3	-16.2
1.2.3 चाय	4966	5444	5497	5832	17.4	7.1
1.2.4 अन्य	101044	90614	90601	89044	-11.9	-1.7
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	14662	13954	14717	14030	-4.3	0.5
1.4 वस्त्र	203549	198409	187677	186323	-8.5	-6.1
1.4.1 सूती वस्त्र	97726	98660	83999	83448	-14.6	-15.4
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2119	2078	2209	2181	2.9	5.0
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26748	23699	25763	25820	-3.5	8.9
1.4.4 अन्य वस्त्र	76956	73972	75706	74874	-2.7	1.2
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11071	11074	11052	10813	-2.3	-2.4
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	11968	11386	11992	11968	0.0	5.1
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	30319	30326	30507	30230	-0.3	-0.3
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	63136	53598	52477	52466	-16.9	-2.1
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	191484	169217	176120	173231	-9.5	2.4
1.9.1 उर्वरक	40043	26848	34080	34112	-14.8	27.1
1.9.2 औषधि और दवाइयां	50500	50814	48873	48501	-4.0	-4.6
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	46717	39455	39743	37445	-19.8	-5.1
1.9.4 अन्य	54224	52100	53424	53173	-1.9	2.1
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	45803	43624	46919	47029	2.7	7.8
1.11 कांच और कांच के सामान	9887	10187	8687	8686	-12.1	-14.7
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	55683	55589	60587	59309	6.5	6.7
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	371564	379180	351144	347906	-6.4	-8.2
1.13.1 लोहा और स्टील	282878	290818	268259	265599	-6.1	-8.7
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	88686	88362	82885	82307	-7.2	-6.9
1.14 सभी अभियांत्रिकी	168621	157976	166861	162680	-3.5	3.0
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	37856	36895	35706	32895	-13.1	-10.8
1.14.2 अन्य	130765	121081	131155	129785	-0.7	7.2
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	79859	78494	82552	81472	2.0	3.8
1.16 रत्न और आभूषण	72014	67951	62792	61310	-14.9	-9.8
1.17 निर्माण	99473	92992	99394	100091	0.6	7.6
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1055921	957886	1019784	1025154	-2.9	7.0
1.18.1 पावर	568966	539667	559953	562711	-1.1	4.3
1.18.2 दूरसंचार	115585	89964	127493	130960	13.3	45.6
1.18.3 सड़क	186852	182246	185424	186529	-0.2	2.4
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	184518	146009	146914	144954	-21.4	-0.7
1.19 अन्य उद्योग	201954	192816	222620	221247	9.6	14.7

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2018		2019					
		अगस्त, 31	अगस्त, 02	अगस्त, 16	अगस्त, 30	सितंबर, 13	सितंबर, 27	अक्टूबर, 11	अक्टूबर, 25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	30	30	30	30	30	30	30
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	62003.4	55007.3	62315.4	62450.6	63160.4	63423.7	62908.4	62777.3	63217.0
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	18241.3	16666.7	17663.1	18031.6	18487.0	18611.6	18621.8	18129.1	18067.8
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5842.3	5078.1	5177.3	5344.5	5227.3	5229.1	5430.0	5159.1	5177.4
2.1.1.2 अन्य	9,808.6	7975.9	9306.0	9146.7	9680.7	9467.8	9639.3	9385.4	9439.3
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	585.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	20.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	2590.5	3026.8	3179.9	3540.4	3579.0	3914.6	3532.4	3564.6	3431.1
2.2 मीयादी देयताएं	98531.4	87307.3	105587.4	106075.6	106261.7	106990.8	107416.5	108105.1	109131.6
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	45655.9	38844.1	51747.2	51932.3	51940.4	52259.6	53251.8	53846.0	54502.9
2.2.1.2 अन्य	52194.8	47031.4	53009.5	53304.0	53479.7	53955.9	53269.0	53391.9	53777.6
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	700.5	0.0	13.5	54.5	0.0	0.0	34.9	0.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	680.7	731.2	830.8	825.7	787.1	775.3	895.6	832.2	851.0
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	50375.4	42526.9	44584.5	42502.1	42578.1	44323.7	44794.9	41809.7	45180.3
4.1 मांग	16826.7	14077.4	14372.5	14323.1	14751.5	13879.2	13568.4	12371.6	12636.9
4.2 मीयादी	33548.7	28449.5	30212.0	28179.0	27826.7	30444.5	31226.5	29438.0	32543.4
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5721.0	4654.0	5186.6	5717.7	5376.6	5927.0	5487.0	5619.6	6010.5
5.1 उपलब्ध नकदी	319.1	322.8	282.0	302.0	320.8	296.8	286.7	297.4	289.4
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5401.9	4331.1	4904.6	5415.7	5055.8	5630.3	5200.3	5322.2	5721.0
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1543.2	981.3	1268.7	3558.1	1008.4	1005.7	796.9	685.0	695.9
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	30885.3	31668.8	30989.5	30631.9	30772.2	30656.8	31724.0	31460.3	32366.1
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	16190.2	16962.3	17738.0	18008.4	16730.6	18098.5	20083.3	17754.6	18708.5
9 बैंक ऋण (10.1+11)	60089.8	54326.0	62015.8	62273.3	61704.0	61037.6	62865.8	61797.8	62515.4
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	60086.2	54323.6	62015.3	62272.8	61703.4	61037.1	62865.3	61797.3	62514.9
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	82610.9	71901.8	76748.4	75814.1	74819.4	75750.4	74965.4	75841.0	78322.8
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	3.7	2.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	नवंबर 18	अक्तूबर 19	नवंबर 19	नवंबर 18	अक्तूबर 19	नवंबर 19	नवंबर 18	अक्तूबर 19	नवंबर 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	139.5	138.4	139.1	140.0	148.3	150.8	139.1	151.9	153.6	139.7	149.6	151.8
1.1 अनाज और उत्पाद	137.7	137.2	137.5	137.1	141.0	141.8	138.1	143.5	144.1	137.4	141.8	142.5
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	150.8	161.6	163.7	146.3	159.8	162.4	149.2	161.0	163.2
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	136.7	141.2	143.8	137.8	144.7	148.4	137.1	142.6	145.6
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	141.9	146.5	147.1	141.6	145.6	145.9	141.8	146.2	146.7
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	122.8	125.6	126.0	118.1	121.1	121.5	121.1	123.9	124.3
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	143.9	145.7	146.2	141.5	150.6	148.9	142.8	148.0	147.5
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	147.5	178.8	191.2	145.2	207.2	215.7	146.7	188.4	199.5
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	121.0	133.1	136.2	115.3	131.2	134.6	119.1	132.5	135.7
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	111.6	113.6	113.8	112.5	114.8	115.0	111.9	114.0	114.2
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	140.6	145.5	147.3	141.4	145.2	146.3	140.9	145.4	147.0
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	137.5	138.6	138.7	128.0	130.2	130.5	133.5	135.1	135.3
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.4	156.1	157.4	157.7	152.6	156.8	157.2	154.5	157.1	157.5
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	159.4	162.9	160.4	161.9	166.3	167.2	164.4	169.3	169.9	162.6	167.1	167.9
3 कपड़ा और जूते	150.3	139.3	145.9	150.8	151.0	151.5	140.5	143.9	144.2	146.7	148.2	148.6
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	151.7	151.7	152.3	142.4	145.9	146.3	148.0	149.4	149.9
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	145.5	146.7	146.9	130.2	132.4	132.6	139.1	140.8	141.0
4 आवास	--	145.6	145.6	--	--	--	146.9	153.0	153.5	146.9	153.0	153.5
5 ईंधन और लाइट	147.0	129.3	140.3	150.3	147.7	148.4	136.7	128.9	132.2	145.1	140.6	142.3
6 विविध	138.6	131.1	134.9	140.1	145.7	146.1	132.2	136.0	136.3	136.3	141.0	141.3
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	148.0	150.6	150.9	135.8	138.7	139.1	142.2	145.0	145.3
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	145.4	153.7	154.3	136.8	142.4	142.8	142.1	149.4	149.9
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	130.3	131.7	132.1	121.2	121.5	121.7	125.5	126.3	126.6
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	143.1	148.7	149.1	131.3	136.2	136.7	136.5	141.7	142.1
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	150.2	160.7	160.8	146.1	151.7	151.8	147.8	155.4	155.5
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	133.1	140.3	140.7	130.5	139.5	139.8	132.0	140.0	140.3
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	141.3	137.7	139.6	142.4	148.3	149.9	139.0	146.0	147.0	140.8	147.2	148.6

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2019		
				नवंबर	अक्तूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	302	325	328
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	914	987	1000
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	915	921	993	1006

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2018		2019	
		नवंबर	अक्तूबर	अक्तूबर	नवंबर
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	31193	31010	38214	38122	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	38404	36879	45578	44938	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
			नवंबर	सितंबर	अक्तूबर (अ)	नवंबर (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	119.8	121.6	121.3	122.2	122.3
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	134.2	136.8	143.0	146.0	147.3
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	143.7	146.2	155.4	160.2	162.4
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	146.7	148.6	160.1	160.8	162.5
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.3	155.6	175.2	194.1	199.4
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	144.1	145.7	146.0	146.4
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	137.4	144.7	145.6	148.6
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	131.6	145.1	148.8	153.0
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	144.1	143.0	143.2	142.5
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	123.1	124.6	126.8	126.3	127.0
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	130.9	129.4	127.3	123.5
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	140.7	154.5	151.4	149.6
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.3	108.1	104.2	103.1	104.1
1.1.2.4 फूल	0.204	164.1	169.3	181.7	207.4	238.5
1.1.3 खनिज	0.833	136.5	151.4	154.8	158.4	154.8
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	123.0	141.4	149.8	153.7	149.8
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.5	186.2	172.3	175.0	172.3
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	92.4	92.9	88.0	85.8	83.1
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	104.1	109.3	100.6	102.1	101.3
1.2.1 कोल	2.138	123.3	123.4	124.8	124.8	124.8
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	133.3	136.5	136.5	136.5
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	120.0	129.9	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	96.7	105.5	90.5	93.0	91.6
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	109.3	110.0	110.0	110.0
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	117.9	118.8	117.9	117.9	117.8
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	128.6	128.8	134.1	134.5	135.3
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	137.1	136.8	138.6	137.5
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.1	135.0	141.5	139.3	138.9
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	113.9	113.7	113.9	114.6
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	116.4	115.7	116.4	119.0
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.2	134.9	145.6	146.2	147.0
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.6	143.1	147.5	148.0	148.3
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.6	115.3	138.0	137.0	135.2
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.3	129.5	132.9	133.2	133.9
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	111.2	112.7	120.2	120.1	119.8
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	126.8	127.6	128.6	126.8
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	136.3	137.9	138.1	132.6
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	137.9	144.0	140.9	142.7
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.2	123.0	131.9	133.9	135.5
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	126.0	127.9	126.8	126.7
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.6	142.3	165.1	167.5	167.5
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.5	160.8	179.9	180.1	178.6
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	120.7	122.1	123.9	123.4	123.8
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	113.8	115.1	118.3	118.2	118.4
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	121.7	126.8	126.5	125.8
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	132.8	129.8	128.6	130.0
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	150.4	149.6	154.6	155.2	153.2
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.4	149.6	154.6	155.2	153.2
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.9	119.0	117.6	117.7	117.1
1.3.4.1 धागों की कटाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	112.0	107.9	107.7	106.5
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	128.1	129.1	130.0	130.1
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	113.8	115.9	114.7	114.5
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	129.1	135.6	134.8	135.4
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.7	142.7	142.1	143.0	146.0
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.3	120.3	117.8	118.1	118.0
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.8	138.4	138.8	138.4	138.9
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.4	138.7	139.4	138.8	139.6
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	137.0	137.6	137.0	137.4	137.2

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018	2019		
		1	2	नवंबर	सितंबर	नवंबर (अ)
				3	4	5
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	121.8	121.6	118.6	118.6	118.7
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	111.0	110.8	104.8	104.8	106.0
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	134.7	135.5	135.3	136.2	135.9
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	123.5	123.2	120.8	120.7	120.3
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और काँक के उत्पाद	0.772	133.5	133.9	134.1	134.4	133.7
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.5	124.7	120.0	121.8	120.2
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड	0.493	136.3	136.9	135.2	135.2	134.9
1.3.7.3 बिल्डरों की बर्दईगीरी	0.036	158.7	159.7	176.1	176.1	176.3
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.1	120.4	131.8	131.5	130.2
1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	123.3	125.4	120.7	120.3	119.7
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	129.3	132.8	125.0	123.4	122.5
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.5	117.4	113.4	114.9	114.1
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	121.6	121.2	121.0	120.9
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	146.6	146.5	149.9	153.2	152.3
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.6	146.5	149.9	153.2	152.3
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	119.1	121.2	117.7	117.4	116.8
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	129.0	120.3	119.4	117.7
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.1	123.4	123.1	122.9	123.4
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	119.6	113.7	112.7	111.8
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	120.2	121.0	122.8	123.0	122.7
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	112.7	114.3	114.5	114.0
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	117.8	118.3	118.6	117.9
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	118.1	113.7	113.7	113.8
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	107.0	98.1	97.5	96.7
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	123.5	124.3	125.8	125.9	126.6
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.5	124.3	125.8	125.9	126.6
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	109.6	110.0	108.2	108.3	107.7
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	99.3	99.2	98.8	98.3
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.7	91.9	94.1	93.8	94.0
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.6	118.1	114.8	115.2	114.4
1.3.13 अन्य अघात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	115.9	115.5	116.9	115.8	115.4
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	120.4	123.1	120.9	120.8
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	112.4	109.6	109.3	108.5
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.0	96.4	102.7	103.4	100.1
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	112.3	114.5	112.7	112.5
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	114.3	112.7	119.9	118.6	118.6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	121.3	121.2	121.3	121.4
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	118.8	120.0	119.1	120.4	118.2
1.3.13.8 अन्य अघात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.4	139.5	89.8	84.9	84.9
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	112.2	114.0	104.4	103.6	103.3
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	117.3	95.5	95.3	96.1
1.3.14.2 मेटलिक आयरन	0.653	117.8	119.5	103.9	102.1	101.8
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	100.1	93.5	92.9	92.5
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	110.2	112.3	103.4	102.7	101.8
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	119.6	122.2	106.4	103.3	102.3
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	112.4	99.6	98.9	99.4
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	113.6	101.0	98.7	99.7
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	127.0	124.8	124.7	123.1
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.2	112.8	106.9	106.5	106.6
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.8	109.3	114.2	115.7	112.4
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	136.1	149.2	147.8	150.4
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.1	115.8	115.3	115.0	115.5
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	113.5	113.6	113.2	113.5
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.3	129.0	123.4	125.0	125.6
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	105.9	103.8	106.0	106.3	106.3
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैमिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.3	96.8	100.2	99.6	99.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	99.9	100.5	100.5	100.3
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	123.9	124.2	122.5	123.6
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	111.8	112.9	109.9	109.8	109.5
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजें	0.402	100.9	102.6	97.9	97.5	97.7
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	135.1	135.1	135.1	135.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारत	2018-19	2018	2019		
			नवंबर	सितंबर	अक्टूबर (अ)	नवंबर (अ)
		1	2	3	4	5
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.7	116.5	117.6	117.5	118.4
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.8	104.9	97.3	97.2	95.3
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.1	110.6	112.9	112.9	112.5
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	137.9	138.6	136.5	136.5	139.7
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.2	99.8	102.8	102.5	103.1
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	107.2	109.5	109.5	109.4
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.7	112.1	110.6	111.2	110.9
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.7	109.0	107.7	108.5	108.8
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.7	118.3	116.8	117.0	117.3
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.1	126.3	105.0	108.4	105.2
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	111.2	111.8	109.5	109.7	110.1
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	105.9	111.9	112.5	111.8
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	121.1	120.7	120.6	120.1
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	108.4	108.7	107.7	105.0
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	111.3	111.9	113.6	112.8	112.6
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	103.5	105.2	104.5	104.1
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	118.8	120.1	120.1	120.2
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	108.9	111.7	111.0	110.9
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.2	112.3	109.6	111.6	107.2
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	78.2	77.4	80.0	80.1	80.4
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने –उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	111.6	112.4	111.7	111.3
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.6	129.9	135.2	128.4	128.6
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	117.9	121.1	120.9	120.9
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	102.5	108.8	107.9	107.9
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	76.5	74.2	75.7	74.1
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	128.7	121.5	120.4	125.7
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.9	118.5	122.3	117.6	117.7
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.8	122.9	126.5	127.1	127.6
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	67.0	66.6	66.6	66.6
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	112.8	113.6	113.7	114.6	115.7
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.3	114.0	114.7	115.2	115.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.2	113.2	112.6	114.0	116.3
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	111.7	112.0	117.9	118.0	118.3
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली –वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	104.7	103.4	106.7	106.6	106.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	107.0	114.3	114.4	114.7
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	127.8	128.7	128.0	128.0	128.1
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.5	124.8	125.7	125.9	126.9
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	127.3	127.4	131.1	130.8	131.2
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.3	127.4	131.1	130.8	131.2
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	107.0	107.1	114.1	116.7	113.6
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	103.9	104.0	111.3	114.1	110.7
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	177.1	176.0	166.4	175.9
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.4	128.8	129.2	129.2	130.9
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	132.2	134.3	136.0	135.9	137.0
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	160.7	162.4	162.5	162.5
2 खाद्य सूचकांक	24.378	138.1	139.7	147.4	150.6	152.3

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारंक	2017-18	2018-19	अप्रैल-अक्तूबर		अक्तूबर	
				2018-19	2019-20	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	125.3	130.1	127.9	128.6	132.8	127.7
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन और उत्खनन	14.37	104.9	107.9	100.8	100.4	108.2	99.5
1.2 विनिर्माण	77.63	126.6	131.5	129.4	130.1	133.9	131.1
1.3 बिजली	7.99	149.2	156.9	162.3	164.9	166.0	145.8
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	121.8	126.1	124.2	124.4	129.5	121.7
2.2 पूंजीगत माल	8.22	105.6	108.4	107.6	94.7	114.1	89.1
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	125.1	126.2	123.5	137.5	125.5	153.4
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	132.0	141.7	139.3	135.9	143.9	130.6
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	123.6	130.4	133.8	124.5	139.7	114.5
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	139.9	145.5	137.7	143.6	143.4	141.8

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-नवंबर			
	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	2018-19 (वास्तविक)	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2019-20	2018-19
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	1962761	983214	870306	50.1	50.4
1.1 कर राजस्व (निवल)	1649582	750614	731669	45.5	49.4
1.2 करेतर राजस्व	313179	232600	138637	74.3	56.6
2 पूंजीगत प्राप्तियां	119828	29009	26277	24.2	28.5
2.1 ऋण की वसूली	14828	10910	10467	73.6	85.8
2.2 अन्य प्राप्तियां	105000	18099	15810	17.2	19.8
3 कुल प्राप्तियां (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	2082589	1012223	896583	48.6	49.3
4 राजस्व व्यय	2447780	1606215	1421778	65.6	66.4
4.1 ब्याज भुगतान	660471	341812	348233	51.8	60.5
5 पूंजी व्यय	338569	213842	191430	63.2	63.7
6 कुल व्यय (4+5)	2786349	1820057	1613208	65.3	66.1
7 राजस्व घाटा (4-1)	485019	623001	551472	128.4	132.6
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}	703760	807834	716625	114.8	114.8
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	43289	466022	368392	1,076.5	759.9

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2018		2019				
		नवंबर 30	अक्टूबर 25	नवंबर 1	नवंबर 8	नवंबर 15	नवंबर 22	नवंबर 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18521	33999	20364	18346	20834	18712	16907	15658
1.2 प्राथमिक व्यापारी	17878	17475	9730	15582	20673	17165	16006	14558
1.3 राज्य सरकारें	26999	77903	71344	73754	69241	68239	58739	62729
1.4 अन्य	27747	64375	82056	79312	74394	82060	87989	93697
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	31953	37535	80120	75756	74887	74027	73881	72356
2.2 प्राथमिक व्यापारी	38738	47154	33701	34123	35015	31739	26258	27263
2.3 राज्य सरकारें	28036	34448	7327	6419	6159	6094	6087	6078
2.4 अन्य	18567	17240	27799	27804	25034	26255	28958	26531
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	48811	53511	62695	62969	64376	63501	62867	61801
3.2 प्राथमिक व्यापारी	74170	77993	61223	60381	59045	57792	59216	61512
3.3 राज्य सरकारें	18892	18092	17930	17930	17930	17930	17920	17890
3.4 अन्य	62393	57215	57226	56950	56008	57142	55177	53155
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	165605	127626	128165	88365	69380	61745	141900	129972
4.4 अन्य	252	492	220	1547	401	973	333	243
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	412704	536942	531515	529327	523594	520657	510007	513228

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य					
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
91-दिवसीय खज़ाना बिल											
2019-20											
अक्टूबर 30	9000	48	103917	6003	12	8997	6003	15000	98.76	5.0361	
नवंबर 6	9000	58	35332	8629	19	8996	8629	17625	98.76	5.0340	
नवंबर 13	9000	70	60855	1305	18	8995	1305	10300	98.76	5.0505	
नवंबर 20	10000	74	52172	10043	21	9988	10043	20031	98.76	5.0196	
नवंबर 27	10000	79	69336	8001	11	9999	8001	18000	98.77	4.9896	
182-दिवसीय खज़ाना बिल											
2019-20											
अक्टूबर 30	4000	55	27042	0	32	4000	0	4000	97.47	5.2056	
नवंबर 6	4000	58	20581	10	7	3990	10	4000	97.50	5.1398	
नवंबर 13	4000	69	25740	0	10	4000	0	4000	97.49	5.1602	
नवंबर 20	4000	64	14535	2	27	3998	2	4000	97.51	5.1317	
नवंबर 27	4000	49	12578	17	8	3983	17	4000	97.51	5.1197	
364-दिवसीय खज़ाना बिल											
2019-20											
अक्टूबर 30	3000	65	17115	0	27	3000	0	3000	94.98	5.2998	
नवंबर 6	3000	72	18738	0	3	3000	0	3000	95.03	5.2397	
नवंबर 13	3000	53	16419	0	12	3000	0	3000	95.04	5.2298	
नवंबर 20	3000	72	14432	1	14	2999	1	3000	95.10	5.1666	
नवंबर 27	3000	57	11882	0	4	3000	0	3000	95.13	5.1389	

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
नवंबर	1, 2019	3.70-5.25	5.04
नवंबर	2, 2019	3.20-5.15	4.86
नवंबर	4, 2019	3.70-5.25	5.03
नवंबर	5, 2019	3.70-5.25	5.04
नवंबर	6, 2019	3.70-5.25	5.07
नवंबर	7, 2019	3.70-5.25	5.05
नवंबर	8, 2019	3.70-5.25	5.02
नवंबर	11, 2019	3.70-5.25	5.06
नवंबर	13, 2019	3.70-5.25	5.09
नवंबर	14, 2019	3.70-5.35	5.06
नवंबर	15, 2019	3.70-5.35	5.07
नवंबर	16, 2019	3.40-5.25	4.61
नवंबर	18, 2019	3.70-5.25	5.06
नवंबर	19, 2019	3.70-5.30	5.07
नवंबर	20, 2019	3.70-5.25	5.07
नवंबर	21, 2019	3.70-5.25	5.05
नवंबर	22, 2019	3.70-5.30	5.04
नवंबर	25, 2019	3.70-5.30	5.04
नवंबर	26, 2019	3.70-5.30	5.04
नवंबर	27, 2019	3.70-5.25	5.02
नवंबर	28, 2019	3.70-5.25	5.03
नवंबर	29, 2019	3.70-5.25	5.03
नवंबर	30, 2019	3.20-5.25	4.59
दिसंबर	2, 2019	3.60-5.25	4.99
दिसंबर	3, 2019	3.60-5.25	5.05
दिसंबर	4, 2019	3.70-5.30	5.02
दिसंबर	5, 2019	3.50-5.25	5.03
दिसंबर	6, 2019	3.70-5.25	5.02
दिसंबर	7, 2019	3.50-5.20	4.69
दिसंबर	9, 2019	3.70-5.25	5.01
दिसंबर	10, 2019	3.70-5.25	4.99
दिसंबर	11, 2019	3.70-5.25	5.00
दिसंबर	12, 2019	3.50-5.25	4.95
दिसंबर	13, 2019	3.60-5.25	4.97

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2018	2019			
	नवंबर 23	अक्तूबर 11	अक्तूबर 25	नवंबर 8	नवंबर 22
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	148505.55	181011.00	171396.00	171696.00	162443.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	27973.54	3073.99	4406.72	10862.41	15649.53
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.92-8.50	5.31-6.35	5.33-7.28	5.15-7.31	5.04-7.24

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2018	2019			
	नवंबर 30	अक्तूबर 15	अक्तूबर 31	नवंबर 15	नवंबर 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	560613.81	486121.25	462308.75	461813.40	458415.60
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	130058.70	106083.50	80459.45	94360.65	80022.90
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.63-11.09	5.19-13.22	5.03-14.08	4.78-13.23	5.01-13.30

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2018	2019					
		नवंबर 23	अक्तूबर 25	नवंबर 1	नवंबर 8	नवंबर 15	नवंबर 22	नवंबर 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	31280	34218	19676	18807	19981	14933	21914	18304
2 नोटिस मुद्रा	4930	955	995	5927	210	4797	196	3595
3 मीयादी मुद्रा	740	400	771	680	604	661	743	757
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	213010	229996	271001	355067	282849	370683	308704	379116
5 बाजार रिपो	200970	174864	194202	229569	187131	239155	189037	259645
6 कापरेट बांड में रिपो		843	40	1270	4588	4512	2074	2953
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	55903	61785	70784	59278	58932	59361	70279
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	65800	50780	41074	46843	65474	56638	95305	70233
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	4320	3257	3699	2596	3342	4406	5598	4846
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3380	4942	4462	1093	4015	4849	4035	2223
10.2 182-दिवसीय	1450	1939	1391	1785	1776	2072	1683	1505
10.3 364-दिवसीय	1620	2777	3580	1865	2610	3263	1700	1901
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1400	136			8224	308	90	6
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	77970	63830	54206	54183	85440	71536	108411	80714
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	2764	128	3	22	199	29	240

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(करोड़ ₹)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2018-19 (अप्रै.-नवं.)*		2019-20 (अप्रै.-नवं.)*		नवंबर 2018		नवंबर 2019*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	129	16754	102	13756	53	59783	5	56	4	440
1ए प्रीमियम	124	16083	100	13312	52	38386	5	42	4	411
1.1 पब्लिक	119	14606	98	12628	42	8528	5	56	4	440
1.1.1 प्रीमियम	115	14123	96	12263	41	8347	5	42	4	411
1.2 राइट्स	10	2149	4	1128	11	51255	—	—	—	—
1.2.1 प्रीमियम	9	1962	4	1049	11	30038	—	—	—	—
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 बांड और डिबेंचर	25	36680	14	28302	23	8766	1	262	—	—
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	25	36680	14	28302	23	8766	1	262	—	—
3.1.1 पब्लिक	25	36680	14	28302	23	8766	1	262	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 कुल (1+2+3+4)	154	53434	116	42058	76	68549	6	318	4	440
4.1 पब्लिक	144	51284	112	40929	65	17294	6	318	4	440
4.2 राइट्स	10	2149	4	1128	11	51255	—	—	—	—

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2018		2019			
			नवंबर	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर
			1	2	3	4	5	6
1 निर्यात	करोड़ ₹	2307726	187335	180518	185541	186092	187733	185645
	मिलियन अमरिकी डालर	330078	26072	26235	26079	26088	26427	25982
1.1 तेल	करोड़ ₹	325929	33813	24004	22995	25033	26005	29213
	मिलियन अमरिकी डालर	46554	4706	3489	3232	3509	3661	4089
1.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	1981797	153522	156513	162546	161058	161728	156432
	मिलियन अमरिकी डालर	283525	21366	22746	22847	22578	22766	21893
2 आयात	करोड़ ₹	3594675	313681	273914	281697	266369	265630	272274
	मिलियन अमरिकी डालर	514078	43655	39808	39594	37341	37392	38106
2.1 तेल	करोड़ ₹	986275	97134	66350	77544	64371	68400	79040
	मिलियन अमरिकी डालर	140921	13518	9643	10899	9024	9628	11062
2.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	2608400	216546	207564	204153	201998	197230	193234
	मिलियन अमरिकी डालर	373158	30137	30166	28695	28317	27763	27044
3 व्यापार शेष	करोड़ ₹	-1286948	-126346	-93396	-96157	-80277	-77897	-86630
	मिलियन अमरिकी डालर	-184000	-17584	-13573	-13515	-11254	-10965	-12124
3.1 तेल	करोड़ ₹	-660346	-63321	-42346	-54550	-39338	-42395	-49827
	मिलियन अमरिकी डालर	-94367	-8812	-6154	-7667	-5515	-5968	-6974
3.2 तेल से इतर	करोड़ ₹	-626602	-63025	-51050	-41607	-40939	-35502	-36802
	मिलियन अमरिकी डालर	-89633	-8771	-7419	-5848	-5739	-4998	-5151

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2018	2019					
		दिसंबर 21	नवंबर 15	नवंबर 22	नवंबर 29	दिसंबर 6	दिसंबर 13	दिसंबर 20
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड़ ₹	2753660	3219968	3219474	3235893	3234873	3219350	3235017
	मिलियन अमरिकी डालर	393288	448249	448596	451080	453422	454492	454948
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड़ ₹	2577150	2991738	2990717	3008401	3005418	2992223	3005923
	मिलियन अमरिकी डालर	367971	416472	416725	419367	421258	422422	422732
1.2 स्वर्ण	करोड़ ₹	147850	191868	192307	191164	193185	191029	192925
	मिलियन अमरिकी डालर	21224	26709	26796	26648	27078	26968	27132
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1052	1046	1046	1046	1046	1046	1046
	करोड़ ₹	10220	10309	10333	10299	10282	10226	10257
	मिलियन अमरिकी डालर	1459	1435	1440	1436	1441	1444	1443
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड़ ₹	18440	26053	26118	26028	25989	25872	25912
	मिलियन अमरिकी डालर	2634	3633	3635	3629	3644	3658	3642

* अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरिकी डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2018	2019		2018-19	2019-20
		नवंबर	अक्टूबर	नवंबर	अप्रैल-नवंबर	अप्रैल-नवंबर
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130,423	125,685	133,720	132,698	6,407	6,189
1.1 एफसीएनआर (बी)	23,170	20,433	24,710	24,326	-1,592	1,156
1.2 एनआर (ई) आरए	92,017	90,515	93,045	92,325	6,452	3,651
1.3 एनआरओ	15,236	14,737	15,965	16,048	1,548	1,383

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018-19	2019-20	2018	2019	
		अप्रैल-नवंबर	अप्रैल-नवंबर	नवंबर	अक्टूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	30,712	21,180	24,403	1,077	1,980	1,175
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	43,302	29,276	32,089	1,585	3,347	1,836
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	62,001	40,591	44,647	3,298	4,726	4,556
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45,055	29,549	32,558	1,797	3,269	2,862
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2,429	2,032	2,982	210	61	58
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिजर्व बैंक	36,315	23,556	24,814	1,378	2,496	2,210
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	5,622	3,514	4,314	151	654	536
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	689	447	447	58	58	58
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	13,672	8,872	8,803	1,150	1,150	1,150
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,274	2,170	3,286	351	307	544
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	18,699	11,315	12,558	1,713	1,379	2,720
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18,452	11,116	12,398	1,700	1,275	2,719
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	247	199	161	13	104	1
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12,590	8,096	7,686	508	1,366	661
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	7,201	4,752	4,074	257	896	329
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3,032	2,022	2,066	253	253	253
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5,202	2,766	3,121	207	361	352
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	2,845	1,443	1,575	208	143	272
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	-618	-8,710	12,649	2,991	3,210	2,120
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1,820	1,820	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	-2,225	-12,324	12,667	2,965	2,780	2,726
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	213	-1,794	18	-26	-430	606
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	30,094	12,470	37,052	4,068	5,190	3,295

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	2018-19	2018	2019		
		नवंबर	सितंबर	अक्टूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	13787.58	996.80	1592.36	1523.77	1482.00
1.1 जमाराशियां	455.94	29.41	46.86	39.57	39.42
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.53	6.64	7.40	8.65	7.14
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.90	24.88	34.74	38.80	73.99
1.4 उपहार	1370.24	102.21	129.29	148.39	153.02
1.5 दान	8.67	0.62	1.55	0.71	0.48
1.6 यात्रा	4803.81	339.73	642.88	578.97	522.28
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2800.88	208.02	242.83	256.77	262.96
1.8 चिकित्सा उपचार	28.59	3.39	2.24	3.18	3.04
1.9 विदेश में शिक्षा	3569.87	267.73	467.23	432.66	400.98
1.10 अन्य	242.15	14.17	17.36	16.08	18.69

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2017-18	2018-19	2018	2019	
			दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.64	72.72	72.54	72.67
1.2 रीर	119.71	114.01	114.51	116.42	116.63
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.18	74.17	73.84	74.00
2.2 रीर	121.94	116.32	116.74	118.89	119.15
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	63.23	63.28	63.35
1.2 रीर	129.19	121.70	122.74	126.69	127.32
2 आधार : 2016-17 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	93.12	93.18	93.28
2.2 रीर	100.00	94.20	95.01	98.07	98.56

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार पंजीकरण

(राशि अमरिकी मिलियन डालर में)

मद	2018-19	2018	2019	
		नवंबर	अक्तूबर	नवंबर
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	999	78	100	122
1.2 राशि	28,387	1,296	2,877	2,116
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	21	2	2	-
2.2 राशि	13,537	770	538	-
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1,020	80	102	122
3.2 राशि	41,924	2,066	3,415	2,116
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.20	6.20	5.30	7.10
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.20	0.92	1.46	2.03
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-15.00	0.00-15.00	0.00-10.50	0.00-15.00

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्र.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	290140	292008	-1868	301536	296418	5118
1 चालू खाता (1.1+1.2)	160019	179073	-19054	161210	167487	-6276
1.1 पण्य	83399	133436	-50037	80014	118097	-38083
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	76620	45637	30984	81196	49390	31806
1.2.1 सेवाएं	50094	29839	20256	52380	31937	20443
1.2.1.1 यात्रा	7038	5813	1225	7643	6031	1611
1.2.1.2 परिवहन	4641	5086	-446	5183	6009	-826
1.2.1.3 बीमा	646	396	250	603	354	249
1.2.1.4 जीएनआईई	140	261	-122	169	298	-128
1.2.1.5 विविध	37629	18282	19348	38782	19245	19537
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	20757	1472	19286	23247	2182	21064
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9408	9690	-282	10878	11211	-333
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1311	1132	180	1239	594	645
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	606	278	328	635	354	281
1.2.2 अंतरण	20891	1560	19331	21986	1999	19986
1.2.2.1 आधिकारिक	35	215	-180	50	251	-202
1.2.2.2 निजी	20856	1346	19511	21936	1748	20188
1.2.3 आय	5635	14238	-8603	6831	15454	-8623
1.2.3.1 निवेश आय	4560	13646	-9086	5426	14791	-9364
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1074	592	482	1404	663	741
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	129539	112935	16604	140326	128273	12053
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	77035	69423	7612	85399	75487	9913
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	14827	7417	7410	15298	7862	7436
2.1.1.1 भारत में	14076	4055	10021	14523	4482	10041
2.1.1.1.1 इक्विटी	10081	3894	6187	9935	4446	5489
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3344		3344	3310		3310
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	652	161	490	1279	37	1242
2.1.1.2 विदेश में	751	3361	-2610	775	3380	-2605
2.1.1.2.1 इक्विटी	751	1376	-625	775	1478	-703
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	758	-758	0	780	-780
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1228	-1228	0	1122	-1122
2.1.2 संविभाग निवेश	62208	62006	202	70101	67625	2476
2.1.2.1 भारत में	61036	61616	-580	68312	66307	2005
2.1.2.1.1 एफआईआई	59216	61616	-2400	68312	66307	2005
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	50860	52179	-1319	48252	51608	-3355
2.1.2.1.1.2 ऋण	8356	9436	-1081	20059	14699	5361
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	1820	0	1820	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1173	391	782	1789	1318	471
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	23578	16652	6926	21567	18396	3171
2.2.1 बाह्य सहायता	1216	1264	-48	1805	1362	443
2.2.1.1 भारत द्वारा	12	30	-18	5	24	-19
2.2.1.2 भारत को	1204	1234	-30	1800	1338	462
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	8951	6766	2185	9030	5656	3374
2.2.2.1 भारत द्वारा	1515	1349	166	1287	1082	205
2.2.2.2 भारत को	7436	5417	2019	7743	4574	3169
2.2.3 भारत को अल्पावधि	13411	8622	4789	10731	11378	-646
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	7392	8622	-1230	10731	10940	-209
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	6019	0	6019	0	437	-437
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	21194	20672	522	23881	25699	-1818
2.3.1 वाणिज्य बैंक	21194	20670	524	23881	25364	-1483
2.3.1.1 आस्तियां	5370	5638	-268	9914	10148	-235
2.3.1.2 देयताएं	15823	15031	792	13967	15216	-1249
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	15402	12075	3326	13458	11178	2280
2.3.2 अन्य	0	2	-2	0	335	-335
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	1	-1	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	7732	6187	1545	9479	8689	790
3 भूल-चूक	582	582	0	582	658	-658
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	1868	0	1868	0	5118	-5118
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	1868	0	1868	0	5118	-5118

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2035381	2048484	-13103	2123697	2087648	36049
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1122561	1256224	-133664	1135391	1179595	-44204
1.1 पण्य	585056	936075	-351019	563533	831746	-268213
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	537505	320150	217355	571858	347850	224009
1.2.1 सेवाएं	351421	209324	142097	368905	224927	143978
1.2.1.1 यात्रा	49373	40780	8593	53826	42478	11348
1.2.1.2 परिवहन	32556	35682	-3126	36504	42320	-5817
1.2.1.3 बीमा	4534	2780	1755	4245	2494	1751
1.2.1.4 जीएनआईई	981	1834	-853	1193	2096	-904
1.2.1.5 विविध	263977	128249	135728	273138	135539	137599
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	145615	10323	135292	163725	15370	148355
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	65998	67978	-1981	76611	78960	-2348
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	9200	7939	1261	8729	4187	4543
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4252	1951	2302	4475	2494	1981
1.2.2 अंतरण	146556	10945	135611	154844	14081	140763
1.2.2.1 आधिकारिक	246	1506	-1260	349	1768	-1419
1.2.2.2 निजी	146310	9439	136871	154495	12313	142182
1.2.3 आय	39528	99881	-60353	48109	108842	-60733
1.2.3.1 निवेश आय	31992	95729	-63736	38218	104171	-65953
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7535	4152	3383	9891	4671	5220
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	908738	792260	116478	988305	903419	84886
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	540417	487014	53403	601461	531648	69814
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	104014	52029	51985	107745	55373	52372
2.1.1.1 भारत में	98746	28449	70297	102287	31568	70719
2.1.1.1.1 इक्विटी	70719	27316	43403	69970	31310	38661
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	23456	0	23456	23309	0	23309
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	4570	1132	3438	9007	258	8749
2.1.1.2 विदेश में	5268	23581	-18313	5458	23805	-18346
2.1.1.2.1 इक्विटी	5268	9650	-4382	5458	10409	-4950
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5318	-5318	0	5496	-5496
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	8613	-8613	0	7900	-7900
2.1.2 संविभाग निवेश	436403	434985	1418	493716	476275	17441
2.1.2.1 भारत में	428177	432244	-4067	481114	466993	14122
2.1.2.1.1 एफआईआई	415410	432244	-16834	481114	466993	14122
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	356793	366047	-9253	339837	363469	-23632
2.1.2.1.1.2 ऋण	58616	66197	-7581	141277	103523	37754
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	12768	0	12768	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8226	2741	5485	12602	9283	3320
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	165403	116817	48586	151892	129560	22332
2.2.1 बाह्य सहायता	8528	8864	-336	12711	9592	3120
2.2.1.1 भारत द्वारा	81	209	-128	36	169	-132
2.2.1.2 भारत को	8447	8655	-208	12675	9423	3252
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	62796	47467	15329	63600	39837	23764
2.2.2.1 भारत द्वारा	10627	9465	1162	9066	7623	1444
2.2.2.2 भारत को	52168	38001	14167	54534	32214	22320
2.2.3 भारत को अल्पावधि	94079	60487	33592	75580	80132	-4551
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	51855	60487	-8632	75580	77050	-1470
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	42224	0	42224	0	3081	-3081
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	148677	145018	3659	168191	180998	-12807
2.3.1 वाणिज्य बैंक	148677	145002	3675	168191	178639	-10448
2.3.1.1 आस्तियां	37674	39555	-1881	69820	71474	-1654
2.3.1.2 देयताएं	111003	105447	5556	98370	107165	-8794
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	108045	84711	23334	94785	78728	16056
2.3.2 अन्य	0	16	0	0	2359	-2359
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	9	-9	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	54241	43401	10840	66761	61198	5563
3 भूल-चूक	4083	0	4083	0	4633	-4633
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	13103	0	13103	0	36049	-36049
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/कमी +)	13103	0	13103	0	36049	-36049

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	160019	179051	-19033	161208	167462	-6254
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क. + 1.अ.ख.)	133493	163275	-29781	132394	150033	-17640
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	83399	133436	-50037	80014	118097	-38083
1.अ.क.1 बोओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	83400	124239	-40839	79356	113743	-34388
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-1	0	-1	658	0	658
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		9197	-9197		4353	-4353
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	50094	29839	20256	52380	31937	20443
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	58	8	50	58	33	25
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	43	259	-216	44	253	-208
1.अ.ख.3 परिवहन	4641	5086	-446	5183	6009	-826
1.अ.ख.4 यात्रा	7038	5813	1225	7643	6031	1611
1.अ.ख.5 निर्माण	766	635	131	677	714	-37
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	646	396	250	603	354	249
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1311	1132	180	1239	594	645
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	162	1942	-1780	248	1776	-1528
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	21428	1869	19559	23947	2654	21293
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9408	9690	-282	10878	11211	-333
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	447	774	-328	551	923	-372
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	140	261	-122	169	298	-128
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	4007	1972	2035	1139	1085	54
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	5635	14238	-8603	6831	15454	-8623
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1074	592	482	1404	663	741
1.आ.2 निवेश आय	3486	13340	-9854	4372	14576	-10204
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1788	6108	-4320	1756	6902	-5146
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	53	3525	-3471	54	3760	-3706
1.आ.2.3 अन्य निवेश	135	3694	-3559	602	3899	-3297
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1508	13	1495	1960	15	1945
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1075	306	769	1055	215	840
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	20891	1539	19352	21984	1975	20009
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	20856	1346	19511	21936	1748	20188
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	20224	991	19233	21291	1336	19955
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	633	354	278	645	412	233
1.इ.2 सामान्य सरकार	35	193	-159	48	227	-179
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	75	96	-21	90	186	-97
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	2	4	-2	9	93	-84
2.2 पूंजी अंतरण	72	92	-19	81	93	-12
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	131333	112861	18472	140238	133230	7008
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	14827	7417	7410	15298	7862	7436
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	14076	4055	10021	14523	4482	10041
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13425	3894	9531	13244	4446	8799
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	10081	3894	6187	9935	4446	5489
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3344		3344	3310		3310
3.1.अ.2 ऋण लिखत	652	161	490	1279	37	1242
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	652	161	490	1279	37	1242
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	751	3361	-2610	775	3380	-2605
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	751	2134	-1383	775	2258	-1483
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	751	1376	-625	775	1478	-703
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		758	-758		780	-780
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1228	-1228	0	1122	-1122
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1228	-1228		1122	-1122
3.2 संविभाग निवेश	60388	62006	-1618	70101	67625	2476
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	59216	61616	-2400	68312	66307	2005
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	50860	52179	-1319	48252	51608	-3352
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	8356	9436	-1081	20059	14699	5361
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1173	391	782	1789	1318	471
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5623	4344	1278	7395	7138	257
3.4 अन्य निवेश	48627	39093	9534	47444	45487	1957
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	1820	0	1820	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमा राशियां	15402	12078	3324	13458	11513	1945
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	2	-2	0	335	-335
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमा राशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमा राशियां)	15402	12075	3326	13458	11178	2280
3.4.2.3 सामान्य सरकार						
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र						
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	15959	16624	-665	21258	21204	54
3.4.3अ भारत को ऋण	14433	15245	-812	19965	20098	-132
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	1527	1379	147	1292	1106	186
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	36	142	-106	54	71	-17
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	13411	8622	4789	10731	11378	-646
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	1999	1626	373	1942	1321	621
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार				0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	1868	0	1868	0	5118	-5118
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए						
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए						
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	1868	0	1868	0	5118	-5118
4. कुल आस्तियां / देयताएं	131333	112861	18472	140238	133230	7008
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	71867	63085	8782	71511	66838	4672
4.2 ऋण लिखत	53779	48150	5629	66786	59952	6833
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	5687	1626	4060	1942	6439	-4498
5. निवल भूल-चूक	582	0	582	0	658	-658

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोरोड़ ₹)

मद	जुलाई-सितंबर 2018			जुलाई-सितंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1122558	1256075	-133518	1135379	1179423	-44044
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	936477	1145399	-208922	932438	1056673	-124234
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	585056	936075	-351019	563533	831746	-268213
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	585065	871555	-286490	558895	801084	-242189
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	-10	0	-10	4638	0	4638
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	64520	-64520	0	30661	-30661
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	351421	209324	142097	368905	224927	143978
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	408	56	351	408	235	173
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	305	1818	-1513	310	1779	-1468
1.अ.ख.3 परिवहन	32556	35682	-3126	36504	42320	-5817
1.अ.ख.4 यात्रा	49373	40780	8593	53826	42478	11348
1.अ.ख.5 निर्माण	5373	4456	917	4770	5031	-261
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4534	2780	1755	4245	2494	1751
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	9200	7939	1261	8729	4187	4543
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1137	13626	-12489	1749	12511	-10762
1.अ.ख.9 दरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	150318	13109	137210	168656	18693	149963
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	65998	67978	-1981	76611	78960	-2348
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3133	5433	-2300	3882	6503	-2621
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	981	1834	-853	1193	2096	-904
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	28107	13834	14273	8021	7641	380
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	39528	99881	-60353	48109	108842	-60733
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	7535	4152	3383	9891	4671	5220
1.आ.2 निवेश आय	24452	93582	-69130	30790	102655	-71866
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	12545	42849	-30304	12365	48608	-36243
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	375	24727	-24352	380	26481	-26100
1.आ.2.3 अन्य निवेश	950	25914	-24964	4241	27463	-23223
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	10581	92	10489	13803	103	13700
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7540	2147	5394	7428	1515	5913
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	146553	10796	135757	154831	13908	140923
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्ततंत्र निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	146310	9439	136871	154495	12313	142182
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	141872	6953	134920	149953	9410	140544
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4438	2486	1951	4542	2903	1639
1.इ.2 सामान्य सरकार	243	1357	-1113	336	1596	-1260
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	523	672	-150	632	1312	-680
2.1 अनुत्पादित वित्ततंत्र आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	14	28	-14	63	656	-593
2.2 पूँजी अंतरण	509	644	-135	569	656	-87
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	921321	791737	129585	987686	938328	49358
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	104014	52029	51985	107745	55373	52372
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	98746	28449	70297	102287	31568	70719
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	94175	27316	66859	93280	31310	61970
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	70719	27316	43403	69970	31310	38661
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	23456	0	23456	23309	0	23309
3.1.अ.2 ऋण लिखत	4570	1132	3438	9007	258	8749
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	4570	1132	3438	9007	258	8749
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	5268	23581	-18313	5458	23805	-18346
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	5268	14968	-9700	5458	15904	-10446
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	5268	9650	-4382	5458	10409	-4950
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5318	-5318	0	5496	-5496
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	8613	-8613	0	7900	-7900
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	8613	-8613	0	7900	-7900
3.2 संविभाग निवेश	423635	434985	-11350	493716	476275	17441
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	415410	432244	-16834	481114	466993	14122
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	356793	366047	-9253	339837	363469	-23632
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	58616	66197	-7581	141277	103523	37754
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8226	2741	5485	12602	9283	3320
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	39443	30477	8966	52083	50270	1813
3.4 अन्य निवेश	341126	274245	66881	334142	320362	13780
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	12768	0	12768	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	108045	84728	23317	94785	81087	13697
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	16	-16	0	2359	-2359
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	108045	84711	23334	94785	78728	16056
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	111956	116621	-4665	149718	149339	379
3.4.3.अ भारत को ऋण	101248	106947	-5699	140615	141548	-932
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	10709	9675	1034	9103	7791	1311
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	253	999	-746	383	501	-117
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	94079	60487	33592	75580	80132	-4551
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	14024	11410	2614	13676	9303	4373
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	13103	0	13103	0	36049	-36049
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	13103	0	13103	0	36049	-36049
4. कुल आस्तियां / देयताएं	921321	791737	129585	987686	938328	49358
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	504159	442549	61611	503643	470736	32907
4.2 ऋण लिखत	377267	337778	39489	470367	422240	48127
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	39895	11410	28485	13676	45352	-31676
5. निवल भूल-चूक	4083	0	4083	0	4633	-4633

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018		2019			
			सितंबर		जून		सितंबर	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169964	399234	163537	362031	173017	417292	175622	416476
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111122	382105	107925	346220	112890	399381	114373	398164
1.2 अन्य पूंजी	58841	17129	55613	15811	60127	17911	61249	18312
2 संविभाग निवेश	4699	260313	2641	237895	5012	267073	4541	259993
2.1 इक्विटी	590	147479	1804	135249	1806	151162	2344	144039
2.2 ऋण	4109	112834	837	102645	3206	115912	2197	115953
3 अन्य निवेश	54538	419279	41541	395576	54511	429560	55904	430051
3.1 व्यापार ऋण	924	105191	904	104340	2140	107224	1707	106581
3.2 ऋण	9884	168112	7084	157613	9765	173962	7895	174988
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25158	130644	16628	122137	24169	133846	27563	133105
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18574	15332	16925	11486	18437	14529	18739	15378
4 रिज़र्व्स	412871		400525		429837		433707	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642072	1078827	608244	995501	662378	1113926	669775	1106520
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436755		-387257		-451548		-436745

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	2018-19	2018	2019		2018-19	2018	2019	
			नवंबर	अक्तूबर			नवंबर	अक्तूबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)				2.78				10655649
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)				1.01				6869045
1.1.1 आउटराइट				0.63				862104
1.1.2 रेपो				0.19				2359755
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो				0.19				3647186
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन				1.74				3525359
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @				0.04				261245
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)				133.87				8679806
1.1 ग्राहक लेनदेन				131.61				7469569
1.2 इंटरबैंक लेनदेन				2.27				1210237
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)				18750.31				2226286
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @				0.64				33
2.2 एपीबीएस \$				1364.56				6908
2.3 ईसीएस जमा				0.00				-
2.4 आईएमपीएस				2280.75				202904
2.5 एनएसीएच जमा \$				722.06				92562
2.6 एनईएफटी				2194.59				1734651
2.7 यूपीआई @				12187.71				189229
2.7.1 जिसमें से यूएसएसडी@				0.74				13
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)				766.41				70199
3.1 भीम आधार पे @				6.46				97
3.2 ईसीएस नामे				0.00				-
3.3 एनएसीएच नामे \$				758.18				70097
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @				1.77				5
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)				6062.09				137707
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)				1762.12				60130
4.1.1 पीओएस आधारित \$				1033.52				31730
4.1.2 अन्य \$				728.60				28401
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)				4299.96				77577
4.2.1 पीओएस आधारित \$				2483.18				37007
4.2.2 अन्य \$				1816.79				40570
5 प्रीपेड भुगतान साधन (5.1 से 5.2)				4672.07				17844
5.1 वॉलेट				3354.08				14652
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)				1317.99				3192
5.2.1 पीओएस आधारित \$				123.86				738
5.2.2 अन्य \$				1194.13				2454
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)				866.12				644802
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)				864.86				643678
6.2 अन्य				1.26				1124
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)				31117.01				3096840
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)				31250.88				11776646
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				30384.76				11131843

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	2018-19	2018	2019		2018-19	2018	2019	
		नवंबर	अक्तूबर	नवंबर		नवंबर	अक्तूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)								
1.1 इंद्रा-बैंक \$	-	-	-	13623.07	-	-	-	471295
1.2 इंटर-बैंक \$	-	-	-	1323.68	-	-	-	96802
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	-	-	-	12299.40	-	-	-	374494
2.1 इंद्रा-बैंक @	-	-	-	2552.21	-	-	-	2193730
2.2 अंतर-बैंक @	-	-	-	559.52	-	-	-	947068
बी. एटीएम	-	-	-	1992.69	-	-	-	1246662
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	-	-	-	6305.28	-	-	-	293580
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	-	7.99	-	-	-	381
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	-	6269.60	-	-	-	284083
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	-	27.68	-	-	-	9116
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	-	-	-	66.63	-	-	-	173
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	-	62.30	-	-	-	125
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	-	-	4.32	-	-	-	48
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	-	-	-	339.83	-	-	-	9648
5.1 ईपीएस @	-	-	-	339.83	-	-	-	9648

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	2019			
	2018-19	2018	2019	
		नवंबर	अक्तूबर	नवंबर
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)				
1.1 क्रेडिट कार्ड	-	-	-	8851.69
1.2 डेबिट कार्ड	-	-	-	544.11
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	-	-	-	8307.59
2.1 वॉलेट @	-	-	-	17253.28
2.2 कार्ड @	-	-	-	16243.87
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	-	-	-	1009.41
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	-	-	-	2.32
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	-	-	-	2.10
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	-	-	-	0.22
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	-	-	-	2.35
6 भारत क्यूआर @	-	-	-	48.83
	-	-	-	15.94

@: दिसंबर 2019 से नया समावेश

\$: दिसंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा

नोट: 1. डेटा अनंतिम है

2. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए दिसंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

3. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

प्रासंगिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2018	2019		
			मई	मार्च	अप्रैल	मई
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115,714.00	8,935.00	21,055.00	9,481.00	11,968.00
	बकाया	918,459.00	819,624.00	918,459.00	927,995.00	939,947.00
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91,108.00	7,265.00	11,498.00	8,647.00	10,029.00
	बकाया	618,418.00	541,158.00	618,418.00	627,065.00	637,094.00
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31,037.00	2,052.00	5,384.00	3,688.00	844.00
	बकाया	140,247.00	113,847.00	140,247.00	143,935.00	144,779.00
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31.00	-28.00	230.00	-35.00	-37.00
	बकाया	3,107.00	3,067.00	3,107.00	3,072.00	3,035.00
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53.00	-6.00	18.00	-5.00	-4.00
	बकाया	10.00	-55.00	10.00	5.00	1.00
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10,967.00	921.00	1,005.00	712.00	1,056.00
	बकाया	192,658.00	183,316.00	192,658.00	193,370.00	194,426.00
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13,990.00	1,229.00	1,262.00	1,140.00	1,435.00
	बकाया	55,708.00	44,035.00	55,708.00	56,848.00	58,283.00
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25,000.00	2,053.00	2,605.00	2,390.00	3,086.00
	बकाया	124,292.00	102,919.00	124,292.00	126,682.00	129,768.00
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71,534.00	61,456.00	71,534.00	72,823.00	74,527.00
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5,910.00	4,763.00	5,910.00	5,983.00	6,084.00
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6,901.00	6,323.00	6,901.00	6,898.00	6,944.00
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39,947.00	30,377.00	39,947.00	40,978.00	42,213.00
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10,081.00	1,044.00	994.00	756.00	3,649.00
	बकाया	102,401.00	94,045.00	102,401.00	103,157.00	106,806.00
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	बकाया	-26.00	-37.00	-26.00	-25.00	-25.00
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16,067.00	1,413.00	4,047.00	937.00	1,738.00
	बकाया	221,517.00	208,476.00	221,517.00	222,509.00	224,231.00
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11,318.00	359.00	3,697.00	862.00	1,230.00
	बकाया	98,492.00	87,725.00	98,492.00	99,354.00	100,584.00
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334.00	117.00	-37.00	-108.00	-131.00
	बकाया	263.00	46.00	263.00	155.00	24.00
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18,678.00	-1,257.00	-1,929.00	-1,955.00	-1,881.00
	बकाया	19,303.00	35,537.00	19,303.00	17,348.00	15,467.00
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23,018	2,202	2,316	2,138	2,520
	बकाया	93,630	74,203.00	93,630.00	95,768.00	98,288.00
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93.00	3.00	-	-	-
	बकाया	2.00	-143.00	2.00	-	-2.00
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18.00	-11.00	-	-	-
	बकाया	-80.00	-80.00	-80.00	-80.00	-82.00
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9,907.00	11,188.00	9,907.00	9,964.00	9,952.00
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8,539.00	257.00	5,510.00	-103.00	201.00
	बकाया	78,524.00	69,990.00	78,524.00	78,421.00	78,622.00

स्रोत : महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2018		2019		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	5602830	5758103	5921026	6072243	6314426
1. वाणिज्य बैंक	41.41	40.51	40.28	39.05	39.66
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.37	0.33	0.31	0.36	0.42
3. बीमाकृत कंपनियां	24.61	24.57	24.34	24.88	24.86
4. म्यूच्युअल फंड	1.41	0.64	0.35	0.64	0.77
5. सहकारी बैंक	2.51	2.38	2.29	2.17	2.01
6. वित्तीय संस्थाएं	0.97	1.01	1.05	1.05	1.15
7. कॉरपोरेट	1.01	1.05	0.97	0.99	0.92
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.65	3.60	3.22	3.27	3.31
9. भविष्य निधियां	5.71	5.54	5.47	5.35	4.87
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	11.76	13.81	15.27	15.67	14.99
11. अन्य	6.58	6.55	6.46	6.57	7.05
11.1 राज्य सरकार	1.99	1.97	2.00	2.02	1.99

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2018		2019		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	2566833	2669393	2777229	2826935	2905169
1. वाणिज्य बैंक	34.66	34.00	33.87	32.57	32.53
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.58	0.60	0.58	0.81	0.72
3. बीमाकृत कंपनियां	33.74	33.90	33.04	33.94	33.39
4. म्यूच्युअल फंड	1.05	1.23	1.20	1.24	1.12
5. सहकारी बैंक	4.75	4.67	4.55	4.65	4.24
6. वित्तीय संस्थाएं	0.43	0.37	0.42	0.44	0.33
7. कॉरपोरेट	0.17	0.22	0.29	0.32	0.28
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.10	0.09	0.09	0.08	0.05
9. भविष्य निधियां	21.04	21.29	22.15	21.88	22.36
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	3.48	3.64	3.81	4.08	4.98
11.1 राज्य सरकार	0.07	0.07	0.11	0.14	0.16

श्रेणी	खजाना बिल				
	2018		2019		
	सितंबर	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	565750	529826	412704	524618	538041
1. वाणिज्य बैंक	47.84	53.76	57.56	53.60	50.81
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.86	2.06	2.68	1.85	1.92
3. बीमाकृत कंपनियां	4.55	4.74	6.61	5.13	5.55
4. म्यूच्युअल फंड	10.69	5.65	2.78	13.00	14.08
5. सहकारी बैंक	1.20	1.21	2.48	2.54	2.55
6. वित्तीय संस्थाएं	1.67	1.88	2.49	2.14	1.82
7. कॉरपोरेट	6.67	1.86	2.23	1.67	1.57
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.01	0.02	0.08	0.07	0.01
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	25.50	28.72	23.10	19.99	21.70
11.1 राज्य सरकार	21.36	24.04	17.91	15.59	17.91

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	1	2	3	4	(सं.अ.) 5	(ब.अ.) 6
1. कुल वितरण	3285210	3760611	4265969	4515946	5516932	6071777
1.1 गतिविधियां	1872062	2201287	2537905	2635110	3344948	3660857
1.1.1 राजस्व	1483018	1668250	1878417	2029044	2543965	2830634
1.1.2 पूंजी	332262	412069	501213	519356	694352	732102
1.1.3 ऋण	56782	120968	158275	86710	106630	98121
1.2 गैर गतिविधियां	1366769	1510810	1672646	1812455	2089516	2315637
1.2.1 राजस्व	1269520	1379727	1555239	1741432	2002766	2204742
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	584542	648091	724448	814757	901783	1009776
1.2.2 पूंजी	94687	127306	115775	69370	85375	109030
1.2.3 ऋण	2563	3777	1632	1654	1375	1865
1.3 अन्य	46379	48514	55417	68381	82469	95284
2. कुल प्राप्तियां	3189737	3778049	4288432	4528422	5364245	6003162
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2387693	2748374	3132201	3376416	4205473	4653758
2.1.1 कर प्राप्तियां	2020728	2297101	2622145	2978134	3512454	3910428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1212348	1440952	1652377	1853859	2186529	2399337
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	805176	852271	965622	1121189	1323113	1506912
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3204	3878	4146	3086	2812	4179
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	366965	451272	510056	398282	693019	743330
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	39622	35779	33220	34224	36739	33619
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	60955	59827	69063	142433	136636	170056
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	22072	16561	20942	42213	56398	63131
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	38883	43266	48122	100219	80238	106926
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	836563	952410	1064704	997097	1174823	1247962
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	-37476	231090	617123	144792	386389	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-334185	60472	195816	-144847	325987	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	861106	708572	429585	844375	793327	----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	664058	673298	689821	794856	831554	959294
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-56580	-78515	-105038	-163222	-217165	-208528
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	34339	35261	45688	42351	42703	42482
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	5109	-3322	-6436	18423	-14577	-871
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27545	13470	17792	25138	16011	13706
3ख.1.6 नकद शेष	95474	-17438	-22463	-12476	152688	68615
3ख.1.7 अन्य	53684	316908	427343	284095	368504	376216
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.3	27.3	27.8	26.4	29.0	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	25.6	27.4	27.9	26.5	28.2	28.5
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.2	20.0	20.4	19.8	22.1	22.1
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.2	16.7	17.1	17.4	18.5	18.5
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.9	6.9	5.8	6.2	5.9

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2019 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1612	19	870	14	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	171	4	-	-	-	-
6	गोवा	77	14	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	305	16	73	6
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	569	24	615	5
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	318	29	842	26	284	14
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	94	19	191	15	74	13
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	222	29	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	227	27	744	25	392	9
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	886	20	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	147	16	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2019 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	7832	771	2	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1194	1	--	0
3	असम	4092	49	--	4000
4	बिहार	6680	--	--	1000
5	छत्तीसगढ़	4184	--	1	5700
6	गोवा	564	283	--	0
7	गुजरात	12917	456	--	0
8	हरियाणा	1960	1139	--	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	1200
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	--	0
12	कर्नाटक	3971	--	--	12000
13	केरल	2030	--	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	872	--	0
15	महाराष्ट्र	36973	402	--	23000
16	मणिपुर	356	95	--	0
17	मेघालय	576	28	9	0
18	मिजोरम	520	37	--	0
19	नगालैंड	1542	31	--	0
20	उड़ीसा	12658	1372	80	26515
21	पुदुचेरी	304	--	--	899
22	पंजाब	227	--	8	0
23	राजस्थान	--	--	129	1800
24	तमिलनाडु	6262	--	45	10583
25	तेलंगाना	5360	1161	1	0
26	त्रिपुरा	311	5	--	0
27	उत्तराखंड	--	--	180	0
28	उत्तरप्रदेश	2987	75	--	0
29	पश्चिम बंगाल	10436	500	214	0
	कुल	123936	7277	668	86696

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2017-18		2018-19		2019-20						2019-20 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	अक्तूबर		सितंबर		नवंबर		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	22800	18922	30200	23824	4170	3003	4000	3184	4206	4206	28454	21455
2	अरुणाचल प्रदेश	888	703	719	693	-	-	-	-	-	-	472	472
3	असम	7760	6797	10595	8089	1000	1000	1000	1000	2000	2000	5700	5700
4	बिहार	10000	8908	14300	10903	3042	2249	4000	4000	-	-600	14642	12249
5	छत्तीसगढ़	8100	8100	12900	12900	-	-	1000	1000	-	-700	2000	1300
6	गोवा	1800	1400	2350	1850	200	100	100	100	200	200	1400	1000
7	गुजरात	24000	15785	36971	27457	3500	2000	2600	1300	1000	1000	20400	13400
8	हरियाणा	16640	15840	21265	17970	3500	3500	2500	1300	-	-	14501	12601
9	हिमाचल प्रदेश	4600	2551	4210	2108	400	400	-	-	-	-	2000	2000
10	जम्मू और कश्मीर	6200	3974	6684	4927	334	334	800	800	800	800	4683	4144
11	झारखंड	6000	4807	5509	4023	-	-252	-	-600	-	-	1500	-344
12	कर्नाटक	22098	17348	39600	31383	8200	8200	1000	250	8200	6200	21400	16650
13	केरल	20500	16203	19500	14784	1400	550	600	-750	1000	324	14682	11206
14	मध्य प्रदेश	15000	13125	20496	14971	-	-	-	-1560	1000	1000	7000	5440
15	महाराष्ट्र	45000	36480	20869	3117	8000	6250	2000	-1250	-	-	22500	12500
16	मणिपुर	525	278	970	667	-	-189	-	-	-	-	803	614
17	मेघालय	1116	920	1122	863	-	-124	100	50	-	-	450	226
18	मिज़ोरम	424	277	0	-123	100	-1	-	-	-	-	358	257
19	नगालैंड	1135	766	822	355	-	-	150	150	150	61	400	51
20	उड़ीसा	8438	8438	5500	4500	1000	1000	-	-	1000	1000	4000	4000
21	पुदुचेरी	825	488	825	475	200	200	-	-	200	200	400	400
22	पंजाब	17470	13349	22115	17053	2800	1100	2300	1000	1900	880	17820	9600
23	राजस्थान	24914	16777	33178	20186	1700	430	6000	5000	1750	750	25332	17250
24	सिक्किम	995	745	1088	795	-	-	238	238	-	-	451	451
25	तमिलनाडु	40965	36023	43125	32278	5500	3300	3575	575	8700	6700	37390	30190
26	तेलंगाना	24600	21828	26740	22183	3000	2166	3000	2416	3000	3000	21800	16798
27	त्रिपुरा	1137	1137	1543	1387	615	465	-	-	615	615	1680	1530
28	उत्तराखंड	41600	37178	46000	33307	9000	6524	6000	4500	3000	1694	29000	18718
29	उत्तरप्रदेश	6660	5830	6300	5289	-	-	300	300	-	-	1600	1000
30	पश्चिम बंगाल	36911	25304	42828	30431	2500	2407	7500	5614	6500	4169	28010	13700
	कुल	419100	340281	478323	348643	60161	44614	48763	28617	45221	33499	330827	234559

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं आरआरबी को छोड़कर हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनपुगी सस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आँकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आँकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मंबुई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए हैं।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियां और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2018-19 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 मई 2019 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2019-20 से लिया गया है। वर्ष 2017-18 से एनसीटी दिल्ली और पदुचेरी के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खजाना बिलों (364-दिन के खजाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

--: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2020	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2019-20 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नंस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
- टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
- भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, Division of Reports and knowledge dissemination, Department of Economic and Policy Research, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, Director, Division of Reports and knowledge dissemination, Department of Economic and Policy Research, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शि कायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।

